R.N.I. NO.HIN/2002/8718 M.P./BHOPAL/642/2021-23

• प्रदेश में डेढ़ हजार शौचालय गायब • उम्रदराज हाइड्रल पावर प्लांट बीमार

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

कमाई से ज्यादा खर्च

वर्ष 19, अंक-12 16 से 31 मार्च 2021 पृष्ठ-48 मूल्य 25 रूपये

5 राज्यों में होगी अग्निपरीक्षा

Anu Sales Corporation

We Deal in Pathology & Medical Equipments

Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

M. : 9329556524, 9329556530, E-mail : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

लापरवाही

9 | लीपापोती की तैयारी

मप्र में नियमों को ताक पर रखकर शराब बनाने वाले समूह सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिना अनुमति बनाए गए स्प्रिट टैंकों के मामले में अब लीपापोती की तैयारी हो रही है। एक तो सोम ने बिना अनुमति अपने परिसर...

मप्र कांग्रेस

11 | नहीं दिखा 96 का दम

सरकार जाने के बाद कांग्रेस में फिर गुटबाजी का पुराना रोग उभरकर सामने आ गया है। विधानसभा में विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के पास 96 विधायक हैं। यानी इस नाते कांग्रेस को मजबूत और सरकार को मजबूर...

लालफीताशाही

14 | कैसे पूरा होगा मेट्रो का सपना

सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू करवा दे। लेकिन प्रदेश सरकार के बजट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार अभी मेट्रो ट्रेन चलाना नहीं चाहती। बजट में भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए कुल 262 करोड़ की राशि...

उपलब्धि

16 | 3 साल में हर घर नल से जल

मप्र के 51 हजार से अधिक गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम मिशन स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा-निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव की निगरानी में नल-जल योजना प्रगति पर है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

5 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 27 मार्च से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और मतगणना 2 मई को होगी। चुनावी मैदान में पार्टियां और नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस अग्निपरीक्षा में कौन सफल होगा यह तो 2 मई को ही पता चलेगा। अभी भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, एआईएडीएमके, डीएमके सहित कई पार्टियां चुनावी मैदान में पसीना बहा रही हैं।

राजनीति

30-31 | मौके पर चौका

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का घमासान चरम पर है। भाजपा और टीएमसी के लिए मैदानी और जुबानी जंग चरम पर है। भाजपा राज्य में भगवा फहराने के लिए टीएमसी में लगातार तोड़-फोड़ कर रही है। 8 मार्च को 5 और टीएमसी विधायक भाजपा में शामिल हुए।

महाराष्ट्र

35 | मराठा आरक्षण में फंसा पेंच

महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल, मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने विगत दिनों वर्चुअल सुनवाई शुरू की है। यह सुनवाई 18 मार्च तक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान संवैधानिक बेंच ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है।

बिहार

38 | अब गांव की सरकार पर नजर

बिहार के कई राजनीतिक दल अब गांव तक अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 'गांव की सरकार' में अपना वर्चस्व बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके तहत पार्टियां पंचायत चुनाव के मैदान में उतरे अपने कार्यकर्ताओं को मदद देने की रणनीति...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

कुल मिलाकर सब हरा ही हरा है...

किसी कवि ने कहा है...

मुलाकातें जरूरी हैं, अगर रिश्ते निभाने हैं
वरना लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं।

लेकिन यह बात माननीयों को कौन बताए। वे पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पौधारोपण तो करते हैं, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि उनके द्वारा रोपित पौधा सूख गया या पेड़ बन गया। मप्र सहित देशभर में हर साल अरबों की संख्या में पौधे रोपे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हरियाली बढ़ने की बजाय लगातार घट रही है। अभी हाल ही में मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया है कि वे रोज एक पौधा लगाएंगे। वे अपने संकल्प के तहत रोजाना एक पौधा लगा भी रहे हैं, लेकिन एक पौधा लगाने की प्रक्रिया के दौरान जिस तरह शासन-प्रशासन का जमावड़ा दिख रहा है, उससे लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या दिखावे के लिए पौधारोपण हो रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि प्रदेश में इससे पहले भी पौधारोपण का इतिहास बना है, लेकिन वह इतिहास काला धब्बा बनकर रह गया। नर्मदा नदी के किनारे एक दिन में 6 करोड़ पौधे रोपने का रिकार्ड बनाया गया था, लेकिन बाद में न तो वे पौधे मिले और न ही जवाबदार। यानी कुल मिलाकर सब हरा ही हरा रहा। दरअसल, भारत में पौधारोपण का पर्व जिस उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है, अगर उसी तरह पौधों का संरक्षण होता रहता तो आज देश में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती। लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रदेश में वन क्षेत्र तेजी से कम हो रहे हैं और कांक्रीट का जंगल तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल, केवल दिखावे के लिए पौधारोपण का प्रहसन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप मप्र में कुछ वर्ष पहले नर्मदा किनारे 6 करोड़ पौधे लगाने के मामले को ही ले लें। इस पौधारोपण महाभियान के लिए अधिकारियों ने पूरे प्रदेश की नर्सरियों में मौजूद सभी पौधे खरीद लिए लेकिन 6 करोड़ पूरे नहीं हुए। बड़े नर्सरी मालिकों और वन विभाग को आदेश हुआ कि कैसे भी हो, पौधे उपलब्ध कराए जाएं। आनन-फानन में उप्र की नर्सरी मालिकों से संपर्क किया गया। इसके बाद मप्र-उप्र सभी जगह जिम्मेदारों ने पेड़ों की डालें तोड़ी और एक बड़ी डाल से कई छोटी-छोटी टहनियां तोड़कर काली पॉलीथिन में मिट्टी भरकर उन्हे पौधे की तरह लगा दिया। इस तरह 6 करोड़ पौधे मप्र पहुंच गए और उन टहनियों को मिट्टी सहित नदी किनारे गड्डों में लगा दिया गया। नर्मदा के तट काली पॉलीथिन से पट गए। अब टहनियों में जड़े तो थी नहीं कि वे पनपते इसलिए सूख गए। ऐसा नहीं कि सभी 6 करोड़ पौधे बिना जड़ की टहनियां थी लेकिन जिनमें जड़े थीं वह भी सूख गए क्योंकि उनकी देखभाल के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था। उन 6 करोड़ पौधों का कैजुअलटी रेट 100 फीसदी रहा। अब ऐसे पौधारोपण का क्या औचित्य है। दरअसल, भारत में हर काम दिखावे का हो गया है। मप्र के मुख्यमंत्री का पौधारोपण कार्यक्रम तो ऐसा हो गया है जो इवेंट में बदल गया है। मुख्यमंत्री जहां भी पौधारोपण करते हैं वहां प्रशासन और पुलिस के छोटे-बड़े अधिकारी का मौजूद रहना अनिवार्य हो गया है। पौधारोपण को हाईप्रोफाइल बनाने के लिए भीड़ भी जुटा ली जाती है। सवाल उठता है कि क्या पौधारोपण का यह प्रदर्शन क्या प्रदेश में हरियाली ला पाएगा?

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 19, अंक 12, पृष्ठ-48, 16 से 31 मार्च, 2021

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर मोबाइल - 7000123977

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

अन्नदाता से खिलवाड़

प्रदेश में एक तरफ अन्नदाता खाद के लिए मारा मारा फिरता है। यहां तक कि एक-एक बोरी खाद के लिए भी उसे जद्दोजहद करनी पड़ती हैं। मंदसौर में किसानों के हक का हजारों क्विंटल खाद घोटाला अन्नादाता के साथ खिलवाड़ है। सरकार को इसकी कड़ी जांच करनी चाहिए।

● **नीतेश साहू,** भोपाल (म.प्र.)

राजस्व कमाने का रास्ता

प्रदेश के लगभग हर शहर में फिल्मों की शूटिंग की जा रही है। इनमें से महेश्वर भी फिल्म मेकर्स की पसंद बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने यहां फिल्म की शूटिंग से राजस्व कमाने का रास्ता निकाला है। इससे प्रदेश के शहरों की चर्चा देशभर में की जा रही है।

● **सोनम शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

तय करना होगा लंबा रास्ता

वर्तमान में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी बताने के आरोपों को राज्य में साबित करने लिए लंबा रास्ता तय करना होगा। भाजपा में शामिल किए गए अधिकांश प्रभावशाली नेता मूल पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन वे वाम मोर्चा अथवा टीएमसी को छोड़कर शामिल हुए हैं।

● **विशाल सोनी,** ग्वालियर (म.प्र.)

अंदरूनी गुटबाजी पर ध्यान दे कांग्रेस

करीब एक साल पहले सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस ने दम भरा था कि वह भाजपा को चैन से नहीं बैठने देगी। लेकिन कांग्रेस सरकार को न तो सदन में घेर पा रही है और न ही बाहर। पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर सड़कों पर हल्ला बोल रही कांग्रेस ने अब आंदोलनों से हाथ पीछे खींच लिए है। आम लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है और अब कांग्रेस पार्टी खुद संगठन में गुटबाजी से जूझ रही है। ऐसे में सरकार के जन हितैषी फैसलों पर सवाल उठाने की बजाय कांग्रेस को अंदरूनी गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए।

● **मधु वर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ रहा टकराव

आज जैसे-जैसे इंसानी आबादी बढ़ रही है और जीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं, उसका असर इंसान और जानवरों के संबंधों पर भी पड़ रहा है। इस वजह से इंसानों और जानवरों के बीच आवास और भोजन के लिए टकराव भी बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष की कीमत इंसानों को अपनी फसल, मवेशियों और संपत्ति के रूप में चुकानी पड़ती है। कभी-कभी इसका नतीजा उनकी मृत्यु का कारण भी बन रहा है। दूसरी तरह के जानवर भी इस संघर्ष की भेंट चढ़ रहे हैं।

● **कमलेश सिंह,** सीहोर (म.प्र.)

बिजली का खेल

मप्र में बिजली का खेल कुछ इस तरह चल रहा है कि अफसरों की भर्राशाही का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में अधिकतर बिजली निजी क्षेत्रों के संयंत्रों में उत्पादित हो रही है। इसका असर यह हो रहा है कि प्रदेश में सरकारी बिजली संयंत्रों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए दो साल पहले शुरू हुई इकाईयों (प्लांट) में तकनीकी खराबी आई।

● **राजेश सूर्यवंशी,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

दीदी का दम

विधानसभा चुनाव के नतीजे भले कुछ भी आएं पर ममता बनर्जी ने साबित कर दिखाया है कि वे सचमुच स्ट्रीट फाइटर हैं। दीदी को बंगाल की शेरनी यूं ही नहीं कहा जाता। भाजपा उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद सभी हथकंडे अपना रही है। उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का सिलसिला लोकसभा चुनाव के बाद से ही जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर खुद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तक पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत से जुटे हैं। ममता लगातार आरोप लगाती आ रही हैं कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों को तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने में बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं। प्रलोभन अलग दिए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में रहते जिन नेताओं को भ्रष्ट और दागी बताते नहीं अघाते थे, सत्ता के लोभ में अब उन्हीं को गले लगा रहे हैं। पर वे डरने वाली नहीं हैं। यकीनन ममता का आत्मविश्वास अब भी कायम है। तभी तो भाजपा से पहले ही एकमुश्त अपने 291 उम्मीदवारों की सूची एक झटके में जारी कर दी। उनसे बगावत कर भाजपा खेमे में जा पहुंचे शुभेंदु अधिकारी की चुनौती भी बेखौफ स्वीकार कर ली। शुभेंदु पिछला चुनाव तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर नंदीग्राम से जीते थे। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बाद दीदी को चुनौती दी थी कि उनमें हिम्मत है तो नंदीग्राम में उनसे लड़कर दिखाएं। दीदी ने ऐसा ही किया।

सबकी नजर कमल हसन पर

तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से ही फिल्मी सितारों का कब्जा रहते आया है। तमिल राजनीति के कद्दावर नेता एमजी रामचंद्रन दक्षिण भारत के सुपर स्टार थे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम में शामिल होने से पहले वे कांग्रेस के साथ थे। 1972 में उन्होंने डीएमके से अलग होकर अन्नाद्रमुक बना डाली थी। तब डीएमके की कमान करुणानिधि के हाथों में थी जो स्वयं तमिल फिल्मों के बड़े स्क्रिप्ट राइटर थे। एमजी रामचंद्रन के बाद अन्नाद्रमुक की कमान उस दौर की सबसे बड़ी अदाकारा जयललिता के हाथों चली गई। यह पहला चुनाव है जिसमें न तो करुणानिधि हैं, न जयललिता। दक्षिण की फिल्मी दुनिया के एक अन्य सितारे विजयकांत जरूर मैदान में हैं किंतु उन्हें जनता पहले ही नकार चुकी है। दक्षिण के अमिताभ कहलाए जाने वाले रजनीकांत ने बड़े जोर-शोर से राजनीति में एंट्री का ऐलान किया, फिर यकायक ही खराब स्वास्थ का हवाला देकर उन्होंने बैकआउट कर लिया। ऐसे में इन चुनावों में केवल कमल हसन अकेले सुपरस्टार हैं जो अपनी पार्टी 'मक्कल निधि मैय्यम' के साथ मैदान में हैं। हसन का जादू कितना चलेगा इसको लेकर चुनावी विशेषज्ञ असमंजस में हैं। हालांकि उनकी पार्टी का टिकट पाने के लिए होड़ मच चुकी है।

गहलोत-सचिन से नाराज राहुल

राहुल गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से खासे नाराज बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान के रूपनगढ़ में आयोजित किसान रैली के दौरान सचिन पायलट के समर्थकों ने अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर राहुल गांधी को गुस्सा दिला दिया था। सचिन के समर्थकों ने एक बार भी राहुल और गहलोत के पक्ष में नारे नहीं लगाए। राहुल की नाराजगी भांप तब प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पायलट को मंच छोड़ने की सलाह दी ताकि उनके समर्थकों की नारेबाजी रोकी जा सके। पायलट मंच से तो उतर गए लेकिन इससे उनके समर्थक ज्यादा नाराज हो गए। दूसरी तरफ अशोक गहलोत से भी राहुल की नाराजगी बढ़ने की खबर है। सूत्रों की मानें तो गहलोत निर्देश मिलने के बाद भी न तो सचिन को मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं, न ही उनके समर्थक विधायकों को सरकार में एडजस्ट करने को तैयार हैं। सरकार की कई कमेटियों में पद खाली होने के बावजूद गहलोत का आलाकमान की न सुनना और राहुल गांधी के खिलाफ 2014 में अमेठी से चुनाव लड़ चुके आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की पत्नी को राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाना आलाकमान को खास नहीं सुहाया है।

उल्टा प्रदेश

नाम के हिसाब से तो उप्र को उल्टा-पुल्टा प्रदेश कहा जाता था। पर सियासी नजरिए से देखें तो दरअसल हरियाणा दिखता है उल्टा प्रदेश। गृहमंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच खटपट कभी थमी नहीं। लगता है कि दोनों आपस में मिल बैठकर संवाद नहीं करते। करते होते तो विज अपने गृह सचिव से नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 30 साल से ज्यादा की सेवा वाले 7 आईपीएस अफसरों की सूची भेजने को क्यों कहते। मौजूदा डीजीपी मनोज यादव का दो साल का निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल पूरा होने पर जब मुख्यमंत्री ने उन्हें पहले ही सेवा विस्तार दे दिया था। अब केंद्र से मंजूरी भी आ गई और तय हो गया है कि यादव एक साल और रहेंगे सूबे की पुलिस के मुखिया। गृह सचिव ने भी कमाल कर दिया। अपने बॉस गृहमंत्री की जानकारी यह कहते हुए बढ़ा दी कि सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी के न्यूनतम कार्यकाल की शर्त लगाई है, अधिकतम की नहीं। विज ही क्यों उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी विरोधाभासी आचरण करने में पीछे नहीं हैं।

मनोज सिन्हा का जयकारा

प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद के बाद भी उप्र की गद्दी पर काबिज न हो सके मनोज सिन्हा अब जम्मू-कश्मीर की जनता का दिल जीतने में जुटे हुए हैं। पहल मोदी सरकार में मंत्री रह चुके सिन्हा बतौर उपराज्यपाल लगातार प्रदेश की जनता संग संवाद बनाने और 'एलजी से मुलाकात' कार्यक्रम के जरिए जनसामान्य की समस्याओं को दूर कर जनता का विश्वास जीतने में सफल होते नजर आने लगे हैं। खबर है कि उनके जनसंवाद कार्यक्रमों में अब भीड़ उमड़ने लगी है। कोविड महामारी के चलते ज्यादातर ऐसे कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किए जा रहे हैं। मनोज सिन्हा स्वयं हर फरियादी से बात करके तत्काल संबंधित विभाग को समस्या का निदान करने के निर्देश देते हैं। सिन्हा की परफॉरमेंस से प्रधानमंत्री खासे प्रसन्न बताए जा रहे हैं। जानकारों का दावा है कि प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश अपने कार्यालय को दिए हैं।

हम प्याला... हम निवाला

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों दो दोस्तों की कारस्तानी खूब चर्चा में है। हम प्याला, हम निवाला की तर्ज पर दोनों दोस्त दिन में लक्ष्मी बटोरने में व्यस्त रहते हैं और फिर रात में प्याला टकराकर अपनी थकान मिटाते हैं। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इन दोनों दोस्तों में से एक मंत्री हैं और दूसरा उनका पीए। दरअसल, दोनों एक साथ पढ़े हैं। ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले से ताल्लुक रखने वाले मंत्रीजी जबसे पाला बदलकर दूसरी पार्टी में आए हैं, तब से उन पर राजा-रजवाड़े का शौक हावी हो गया है। वहीं मंत्रीजी के पीए तो राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में लेन-देन के मामले में ख्यात हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कफन में से भी चिंदी मांग लेते हैं। अब उन्हें उनके ही सहपाठी रहे मंत्रीजी का साथ मिल गया है। फिर क्या है, दोनों मिलकर फाइलें निपटा रहे हैं और पैग भी लगा रहे हैं। गौरतलब है कि मंत्रीजी के पास सबसे बड़ा विभाग है। इस विभाग में केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हैं। इन योजनाओं में अथाह बजट मिलता है। ऐसे में मंत्रीजी के दोस्त पीए जो इसी विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हें नए-नए तरीके से पैसे कमाने का गुर सिखा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि मंत्रीजी का ध्यान विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की अपेक्षा पीए के साथ मिलकर कमाई पर लगा है। गौरतलब है कि मंत्रीजी के पीए तो खुलेआम दो प्रतिशत मांगने के लिए ख्यात हैं। इस संदर्भ में उनकी एक रिकॉर्डिंग भी वीथिकाओं में घूम रही है।

तिनके का भी सहारा नहीं

सत्ता जाने के बाद कांग्रेस के विधायक मझधार में फंसे हुए हैं। वैसे जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब भी मंत्रियों और विधायकों के हाथ बंधे हुए थे। अब सत्ता जाने के बाद तो उनकी स्थिति क्या है, यह आप भी सहज अनुमान लगा सकते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा में 5 समितियों का गठन किया गया, जिसमें से सबसे अहम लोक लेखा समिति का सभापति पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ विधायकों को उम्मीद थी कि उन्हें इस समिति में जगह मिलेगी, ताकि उनका रसूख तो कायम रहे। लेकिन किसी को तिनके का सहारा भी नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस शासनकाल में विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन रहे एक विधायक इस कदर नाराज हुए हैं कि उन्होंने तो विधानसभा में आना ही बंद कर दिया है। वे अपनी शिकायत लेकर पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के पास पहुंचे। बताया जाता है कि गोविंद सिंह ने उनसे साफ-साफ शब्दों में कहा कि 'भाई इस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जाकर बताओ।'

हथेली पर दूब की खेती

मप्र की राजनीति में दिग्विजय सिंह एकमात्र ऐसे नेता हैं जो हथेली पर भी दूब उगा सकते हैं। इसको एक बार फिर से उन्होंने सिद्ध कर दिया है। दरअसल, सत्ता जाने के बाद कांग्रेस पूरी तरह बिखर गई है। इस कारण प्रदेश में पिछले एक साल से कांग्रेस मृतप्राय नजर आ रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह एकमात्र ऐसे नेता दिख रहे हैं जो कांग्रेस के साथ ही अपने आपको सक्रिय रखे हुए हैं। दरअसल, सत्ता जाने के बाद से ही कांग्रेस के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच दरार बढ़ती जा रही है। एक तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निष्क्रिय हैं, वहीं दूसरी तरफ दिग्गी राजा ने ऐसी स्थिति में भी अपने आपको सक्रिय रखने के लिए किसान महापंचायत का सहारा लिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह प्रदेशभर में किसान महापंचायत आयोजित कर हुंकार भर रहे हैं। दिग्गी राजा की हुंकार का भाजपा पर भले ही कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन कमलनाथ हैरान-परेशान हैं। अब उन्हें अहसास हो रहा है कि दिग्गी राजा का काटा पानी भी नहीं मांग पाता है। दरअसल, जब कांग्रेस के पास सत्ता थी तो दिग्विजय सिंह ने पूरी सरकार पर अपना वर्चस्व कर लिया था। अब सत्ता नहीं है तो उन्होंने कांग्रेस पर कुंडली मारना शुरू कर दिया है। दिग्गी राजा के इस कदम से कई नेताओं की राजनीति हाशिए पर पहुंच गई है। इनमें से एक नेता स्वयं कमलनाथ भी हैं।

आखिर मौन क्यों?

मप्र में विपक्ष पूरी तरह दंतहीन नजर आ रहा है। सत्तापक्ष को घेरने के लिए बड़ी-बड़ी बात करने वाले विपक्ष के सामने मुद्दों की भरमार है, लेकिन न तो सदन में और न ही सदन के बाहर विपक्ष कुछ कर पा रहा है। ताजा मामला एक महिला मंत्री के भाई का सामने आया है। छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने मंत्री के भाई को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन विपक्ष की तरफ से एक आवाज नहीं उठी है। वहीं एक आदिवासी जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष पर एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का मामला सामने आया है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे विपक्ष को इसकी जानकारी ही नहीं है। यही नहीं सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन विपक्ष की बोलती बंद है। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने में पूरी तरह असफल रहा। जबकि भ्रष्टाचार और चरित्रहनन के कई मामले सामने आए, लेकिन विपक्ष मौन धारण किए हुए है। चर्चा तो यह है कि विपक्ष कई गुटों में बंट गया है, इसलिए विधायक एकजुट होकर सरकार को घेरने की तैयारी नहीं कर पाए हैं।

प्रशिक्षण और शिक्षण जरूरी

मुरैना में दलित के घर भोजन को लेकर चाल, चरित्र, चेहरे वाली पार्टी में जिस तरह का घमासान देखने को मिला, उससे पार्टी में यह चर्चा जोरों पर होने लगी है कि बेमेल खिचड़ी ऐसे ही पकती है। दरअसल, मुरैना जिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री एक दलित के यहां भोजन करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में सिंधिया समर्थक नेता भी शामिल होने पहुंचे, लेकिन भाजपाईयों ने उन्हें रोक दिया। इसको लेकर तू-तू, मैं-मैं की स्थिति निर्मित हो गई। ऐसे में अब यह चर्चा जोरों पर है कि भले ही पूर्व कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके मन भाजपाईयों से नहीं मिल पाए हैं। इस मामले में क्षेत्र के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री रहे वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना है कि ऐसे झगड़े आगे भी होते रहेंगे, अगर कांग्रेस से आए नेताओं को प्रशिक्षण और शिक्षण नहीं दिया गया। दरअसल, दो विचारधाराओं का मिलन विवाद पैदा करता ही है। अब देखना यह है कि इस टकराव के बाद भाजपा में राजनीति किस ओर करवट लेती है। क्योंकि इस पूरे मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष की गलती सामने आ रही है।

आज की युवा पीढ़ी को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जो आज भी जिंदगी में आपको मुश्किलों से जूझने की सीख देगी। गीता हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। यह बहस को प्रोत्साहित करती है और हमारे दिमाग को खुला रखती है।

● **नरेंद्र मोदी**

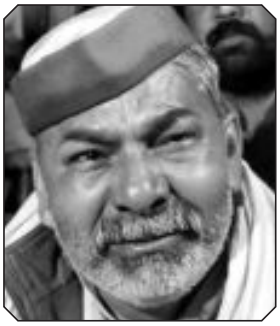

किसानों की मांग को दिल्ली ऐसे नहीं मानेगी, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई से ही तो किले जीते गए हैं। अगर हम हाथ जोड़ते रहेंगे तो लुटेरे नहीं मानने वाले हैं। बगावत अपने घर से शुरू होती है। जो अपने घर के बंधन में रहेगा वो आंदोलन कभी नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने बोरिया-बिस्तर बांधकर आंदोलन के लिए मैदानी मोर्चा संभाल लिया है।

● **राकेश टिकैत**

ऋषभ पंत का प्रदर्शन हर दिन बेहतर हो रहा है। अब वह फॉर्म में आ गया है। उसे अकेला छोड़ दें, ताकि वह अपना नेचुरल गेम खेल सके। पंत पर दबाव न बनाया जाए। उसके खेल में हर दिन सुधार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन किया। घरेलू सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका फॉर्म शानदार रहा है।

● **रोहित शर्मा**

शाही परिवार मेरे बेटे आर्ची को प्रिंस नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके जन्म से पहले उन्हें डर था कि कहीं उसका रंग ब्लैक ना हो। आर्ची के जन्म से पहले शाही परिवार ने प्रिंस हैरी से इस बारे में चर्चा की थी, जो मेरे लिए काफी दर्दनाक था।

● **मेगन मर्केल**

मां को लगता था कि मैं भोली हूं, मोटी चमड़ी की नहीं। मुझसे ज्यादा उन्हें भरोसा था कि खुशी के लिए फिल्मी दुनिया ज्यादा ठीक रहेगी। मां मेरे लिए रिलैक्स्ड लाइफ चाहती थीं। जब मैंने मां को बताया था कि मैं एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती हूं तो हमारी कई बातें हुईं, वह काफी असमंजस में थीं मगर वह यह बात जानती थीं कि मुझे एक्टिंग का कीड़ा काट चुका है। जब मैं छोटी थी तो मां हमेशा चाहती थीं कि मैं डॉक्टर बनूं लेकिन मैं मॉम को सॉरी बोलना चाहती हूं, क्योंकि मेरे अंदर डॉक्टर बनने लायक समझदारी नहीं थी। फिल्म लाइन में भी मुझे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।

● **जान्हवी कपूर**

वाक्युद्ध

जो लोग हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, मैं उन्हें साफ बताना चाहती हूं कि मैं भी एक हिंदू परिवार से आई लड़की हूं। मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। मैं एक ब्राह्मण हूं और हिंदू रस्मों के बारे में भगवा पार्टी के नेताओं से कईं ज्यादा जानती हूं। अगर किसी को मेरे धर्म के बारे में शक है तो मैं उससे बहस करने को तैयार हूं।

● **ममता बनर्जी**

इस देश में बड़ी विकट परिस्थिति है। 70 साल तक खुद को सेक्युलर कहने वाले लोग, जो लोग ब्राह्मण पितृसत्ता के कारण देश समाप्त होने की बात करते थे, वे आज अचानक ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण का बेटा बन गए हैं। यही वो लोग हैं, जिन्होंने भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, इसके लिए कमर कस के लगे थे।

● **संबित पात्रा**

लीपापोती की तैयारी

मप्र में नियमों को ताक पर रखकर शराब बनाने वाले समूह सोम डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिना अनुमति बनाए गए स्प्रिट टैंकों के मामले में अब लीपापोती की तैयारी हो रही है। एक तो सोम ने बिना अनुमति अपने परिसर में 19 स्प्रिट टैंक बनवा लिए और उनके निर्माण में नियमों को भी ताक पर रख दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि नियम विरूद्ध बने इन टैंकों की जांच विगत दिनों **आबकारी विभाग** की एक समिति से कराई गई। समिति ने अपनी जांच में बताया कि रिसीवर रूम के चारों ओर 30 फीट ऊंची दीवार बना दी गई है। स्थल निरीक्षण पर सबकुछ सही पाया गया है। सवाल उठता है कि जिन टैंकों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया है, विभाग उनकी सुरक्षा की जांच क्यों करवा रहा है?

मामला **सोम के उन 19 टैंकों से** जुड़ा हुआ है, जो सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टलरीज के कैंपस में असुरक्षित तरीके से संचालित किए जा रहे थे। ये टैंक नियमों की अवहेलना कर बनाए गए थे। जिनके आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं मिले। इसके चलते आबकारी विभाग ने इसी साल 22 जनवरी को ये सभी टैंक सील कर दिए थे। मामले को लेकर आबकारी विभाग के आयुक्त राजीव दुबे ने गत दिनों सोम के प्रबंधन का पक्ष सुना था। सोम का पक्ष सुनने के पहले ही विभाग के सामने यह स्पष्ट हो गया था कि सोम ने अपने नए प्लांट के लिए सरकार को अनुमति का कोई आवेदन ही नहीं दिया था। नए प्लांट को आबकारी विभाग ने ऐसी ही एक विभागीय समिति की रिपोर्ट पर एक लाख रुपए का जुर्माना कर अनुमति दे दी थी। बाद में इन विवादित टैंकों के मामले में भी यही किस्सा सामने आया कि नए प्लांट के नक्शे में इन टैंकों का कहीं जिक्र ही नहीं था।

अब जरा मामले से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखें। राज्य विधानसभा में इसी फरवरी में यह मामला उठा। सरकार ने रिकॉर्ड पर जानकारी दी कि सोम द्वारा सेहतगंज में खुले में स्थापित स्प्रिट रिसीवर टैंक और स्टोरेज टैंक के लिए आबकारी विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई है। सनसनीखेज बात यह भी कि विधानसभा में सरकार ने यह भी स्वीकारा कि उसे इस बात की भनक ही नहीं लगी कि ये रिसीवर टैंक और स्टोरेज टैंक कब बना लिए गए थे। जाहिर है कि विधानसभा में भी यह साफ हो गया था कि इन टैंकों के संबंध में सोम ने नियमों को ताक पर रखकर काम किया है। हालांकि इसके बावजूद सोम के खिलाफ कोई कार्रवाई होने की एक बार फिर कोई संभावना नहीं रह गई है। क्योंकि तमाम सचों के बावजूद सोम के मामले की जांच आबकारी विभाग की एक समिति बनाकर मामले को रफा-दफा करने का बंदोबस्त कर दिया गया है।

समिति जिन बिंदुओं पर जांच करेगी, उनमें से कुछ बेहद रोचक हैं। मसलन, इसे ये पता लगाने को कहा गया है कि जिन टैंकों पर विवाद है, उन्हें बनाने की प्लानिंग का क्या सोम ने सरकार से जिक्र किया था। और ये भी पता लगाने की बात समिति को सौंपी गई है कि क्या इन टैंकों के बनाने या उन्हें एडवांस रूप देने का काम इसके लिए सरकार द्वारा मंजूर किए गए नक्शे के मुताबिक हुआ है या नहीं। समिति को यह भी पता लगाना है कि इन टैंकों के लिए सरकार से आवश्यक अनुमतियां ली भी गई थीं या नहीं। यानी विधानसभा में जिन नियमों और औपचारिकताओं के सरासर उल्लंघन की बात स्वीकारी जा चुकी है, उन्हीं सारे बिंदुओं की जांच के लिए अब समिति बना दी गई है। समिति से कहा गया है कि वह 25 मार्च तक सरकार को रिपोर्ट सौंप दे।

जानकार सूत्र बताते हैं कि अब समिति बहुत से बहुत यह अनुशंसा करेगी कि प्लांट में टैंकों को लेकर हुई गड़बड़ी के लिए सोम पर जुर्माना लगाकर **सभी टैंक नियमित कर दिए जाएं।** इसके लिए टैंक निर्माण में हुए भारी-भरकम खर्च का हवाला दिया जा सकता है। बता दें कि प्लांट की अनुमति के मामले में सोम को इसी तरह पहले भी बचाया गया था। इन्हीं टैंकों की पूर्व में आबकारी आयुक्त स्तर पर जांच हुई थी। उसके बाद तत्कालीन आयुक्त ने सोम प्रबंधन पर केवल एक लाख रुपए का जुर्माना लगाकर प्लांट को नियमित करवा लिया था। अब एक बार फिर ऐसा ही करने की तैयारी कर ली गई है। इस मामले में राज्य सरकार की कार्यवाही को लेकर सवाल उठना बेमानी नहीं है। टैंक सील किए जाने के बावजूद सोम प्रबंधन ने बीच में जो काम किए, उनके लिए कोई भी कार्यवाही करने की सरकार हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है। जबकि मामला सरकारी अमले की जान-माल की सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। यह घटना तब सामने आई, जब बीते दिनों रायसेन जिले के प्रभारी आबकारी अधिकारी पंकज तिवारी ने संभागीय उड़नदस्ता के उपयुक्त विनोद रघुवंशी को एक खत भेजा। इसमें साफ कहा गया कि विभाग ने जिन टैंकों को सील किया था, सोम के स्टाफ ने उन टैंकों में पाइप डालकर उनसे स्प्रिट निकालने और उसकी मदद से देशी शराब बनाने का काम शुरू कर दिया है। खत में कहा गया कि इस काम को रोकने पर सोम के स्टाफ ने आबकारी विभाग के अमले को डरा-धमकाकर उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है।

● **कुमार राजेंद्र**

बिना अनुमति बने हैं टैंक

सोम डिस्टलरीज ने अपने परिसर में जो 19 टैंक बनवाए हैं, वे नियमों के विरूद्ध है। आबकारी आयुक्त कार्यालय ने भी माना है कि इन टैंकों के निर्माण में कंपनी ने कोई अनुमति नहीं ली है। सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन से प्राप्त पत्र क्रमांक/आब/मु.लि./वि.स./2020-21/367 दिनांक 10.02.2021 द्वारा भी अवगत कराया गया है कि खुले में स्थापित स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं स्टोरेज टैंक कब कितने टैंक बनाए हैं के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इकाई में प्रवर्धन एवं आधुनिकीकरण कार्य की अनुमति के संबंध में आबकारी आयुक्त कार्यालय में संग्रहित अभिलेखों के अवलोकन से भी खुले में स्थापित स्प्रिट रिसीवर टैंक एवं स्टोरेज टैंक बनाने संबंधी कोई अनुमति पत्र उपलब्ध नहीं है। अतः अब इस मामले की जांच के लिए आबकारी विभाग ने तीन सदस्यीय समिति बनाई है। जिसमें अपर आबकारी आयुक्त डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, सहायक आबकारी आयुक्त केसी अग्निहोत्री और सहायक आबकारी आयुक्त हर्षवर्धन राय शामिल किए गए हैं।

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव पर असमंजस का साया मंडरा रहा है। ये चुनाव कब होंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस का आरोप है कि संभावित हार को देखते हुए भाजपा चुनाव नहीं कराना चाहती है। उधर, चुनाव आयोग तैयारी में जुटा हुआ है।

हार का डर

मप्र में नगरीय निकायों का कार्यकाल खत्म हुए 10 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अगले चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। कोरोना संकट को आधार बनाकर ये चुनाव टाले जा रहे हैं। दिसंबर में भी तारीखों का ऐलान होने ही वाला था, कि कोरोना संकट का हवाला देकर राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे टाल दिया। प्रदेश के नगरीय निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2020 में खत्म हो चुका है।

कांग्रेस का कहना है कि सत्तारूढ़ भाजपा जानबूझ कर चुनाव टाल रही है। जिस तरह से केंद्र सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी भरी हुई है, उससे शिवराज सरकार डरी हुई है। उसे लग रहा है कि केंद्र की नाराजगी चुनावों में उसके खिलाफ जा सकती है। नाराजगी कई कारणों से है। किसान आंदोलन का असर राज्य के कई क्षेत्रों में दिख रहा है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम और बेरोजगारी से जनता परेशान हो चुकी है। इसलिए भाजपा को हार का डर है।

मप्र सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा सीधे आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार चुनाव से भाग रही है। वे कहते हैं, 'सरकार चुनाव की तारीखें घोषित नहीं कर रही है, क्योंकि वह जानती है कि पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जनता इनको वोट नहीं करेगी। भाजपा समझ रही है कि अगर अभी चुनाव कराए गए तो वे सभी नगर निगम सीटें हार जाएगी।' भाजपा इस तरह के आरोपों को खारिज करती है। पार्टी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल कहते हैं, 'कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए स्वयं चुनाव टाला और अब आरोप हम पर लगा रही है। इन्होंने ही मेयर का चुनाव परोक्ष रूप से कराने के लिए संशोधन किया था। इसका सीधा अर्थ यह है कि वे लोग सीधे चुनाव से बचना चाह रहे थे।' अग्रवाल के अनुसार भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य सरकार तो कोर्ट में भी कह चुकी है कि वह किसी भी समय चुनाव के लिए राजी है।

भाजपा ने निकाय चुनावों की तैयारियों के लिहाज से नवंबर-दिसंबर में मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठकें की थीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी निगमों का दौरा भी किया था। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सभी नगर निगमों का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी कई स्तरों पर स्वयं बैठकें कर चुके हैं। प्रदेश में पिछले नगरीय निकाय चुनाव 2015 में हुए थे, जिसमें भाजपा को बड़ी जीत मिली थी। प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों पर उसका कब्जा था। ज्यादातर निगमों की नगर परिषदों में भी भाजपा का ही बहुमत था। उस समय शिवराज सिंह की लोकप्रियता चरम पर थी। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन पिछले साल उसे गिराकर भाजपा फिर सत्ता में आ गई।

तैयारी में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे इलेक्शन मोड में आ जाएं। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान छोटी-छोटी खामियों को दूर कर लें। यदि छोटी सी गलती भी पाई जाती है, तो माफ नहीं किया जाएगा। आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी की है। आयुक्त बीपी सिंह ने नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों (जिला निर्वाचन अधिकारी) के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति, नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए स्थान का चयन, आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीसीटीवी और वीडियो कैमरे की व्यवस्था, मतदान के गठन के लिए सॉफ्टवेयर में एंट्री और जिला स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री की खरीदी तुरंत करें। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त स्पष्ट कर चुके हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के दौरान चुनाव नहीं कराए जाएंगे। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से 18 मई तक होंगी। इस हिसाब से देखें, तो चुनाव अप्रैल माह में होंगे या फिर मई के तीसरे सप्ताह में कराए जाएंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हार का डर भाजपा से ज्यादा शिवराज सिंह को सता रहा है। जिन परिस्थितियों में उनकी सत्ता वापसी हुई है, उसके चलते निकाय चुनावों में जीत का पिछला परिणाम दोहराना उनकी आवश्यकता है। उनको सत्ता में आए एक साल का समय हो गया है। इसका सीधा अर्थ है कि जनता उनके काम के आधार पर वोट देगी। ऐसे में यदि नतीजे पिछली बार की तुलना में खराब रहे तो यह बात उनके खिलाफ जाएगी। उनके विरोधियों को आवाज उठाने का मौका मिल जाएगा और वे ऐसा कोई मौका देना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले साल विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद शिवराज नगरीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी नगर निगमों का दौरा कर चुके हैं। सभी शहरों के 3 साल के विकास कार्यों की योजना बनवाकर उन पर अमल भी शुरू करवा चुके हैं। यह सब नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखकर ही किया जा रहा है।

भाजपा के लिए एक चुनौती सिंधिया के साथ आए नेता और मंत्री भी हैं। दरअसल, सिंधिया के साथ ही उनके समर्थक नेता भी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि उनके समर्थकों को निकाय और पंचायत चुनाव में टिकट मिले। इससे भाजपा में असंतोष बढ़ते जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण मुरैना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने आ चुका है। इसलिए भाजपा की कोशिश है कि जैसे भी हो नगरीय निकाय चुनाव को लंबा खींचा जाए।

● **राकेश ग्रोवर**

नहीं दिखा 96 का दम

सरकार जाने के बाद कांग्रेस में फिर गुटबाजी का पुराना रोग उभरकर सामने आ गया है। विधानसभा में विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के पास 96 विधायक हैं। यानी इस नाते कांग्रेस को मजबूत और सरकार को मजबूर करने वाले विपक्ष की भूमिका में नजर आना चाहिए लेकिन सदन के अंदर कांग्रेस बिखरी-बिखरी सी नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ हैं लेकिन वे भी सदन में कम नजर आ रहे हैं। उनकी गैरमौजूदगी में डॉ. गोविंद सिंह जैसे-तैसे कमान संभालते नजर आते हैं। चंद विधायकों को छोड़ दें तो बाकी में आक्रामकता ही नजर नहीं आती। सदन में सरकार को घेरने के बड़े-बड़े दावे करने वाली कांग्रेस के पास बड़े मुद्दे होने के बाद भी कोई रणनीति दिखाई नहीं दे रही।

सदन के अंदर कुछ विधायक जैसे कुणाल चौधरी, जीतू पटवारी, बाला बच्चन और विजयलक्ष्मी साधौ जैसे कुछ विधायक हैं जो सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। डॉ. गोविंद सिंह इनका साथ बखूबी निभाते नजर आते हैं। लेकिन **बाकी विधायक** इतने सक्रिय नजर नहीं आते। उनमें न धार नजर आ रही है और न ही आक्रामकता। कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक कहते हैं कि ये सवाल तो नेता से करना चाहिए, हम तो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। जिसको जैसा समझ में आता है वैसा करता है। इन्होंने नाम लिखने का तो मना किया लेकिन अपनी लाचारी और कांग्रेस की स्थिति बता दी। कुणाल चौधरी कहते हैं कि वे तो मुखरता से सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार उनके सवालों से बच रही है। कांग्रेस की स्थिति को टालते हुए डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि ये बजट सत्र है और आने वाले समय में हम सब संगठित होकर सरकार को घेरेंगे।

महंगाई, अपराध और सीधी बस हादसे जैसे बड़े मुद्दे होने के बाद भी कांग्रेस में सरकार को घेरने की रणनीति नजर नहीं आ रही। कांग्रेस में ये योजना ही बनती दिखाई नहीं दे रही कि किस तरह से महंगाई के मुद्दे पर सरकार को तेल पर टैक्स कम करने के लिए मजबूर करना है। सीधी बस हादसे पर स्थगन लाने वाली कांग्रेस सरकार पर सवाल ही खड़े नहीं कर पाई। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बड़े सहज तरीके से अपना जवाब दे गए। कांग्रेस ने कुछ मुद्दों पर वॉकआउट जरूर किया है लेकिन सदन के अंदर बहुत प्रभावी विरोध नजर नहीं आया। सीधी बस हादसे के स्थगन पर चर्चा के वक्त लंच के बाद कांग्रेस के नेता ही नदारद थे जिस पर संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस गंभीर ही नजर नहीं आ रही। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस अब दल नहीं दलदल हो गई है।

सदन के बाहर भी कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है। पार्टी में गुटबाजी फिर नजर आने लगी है। कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी एक मुद्दे पर एक सुर नहीं है। गोडसे की पूजा करने वाले हिंदू महासभा के बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस के दो खेमे कर दिए हैं। अरुण यादव ने विरोध का झंडा उठाया तो **कई नेता** उनके साथ आ गए। आधे नेता प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के फैसले के साथ हो गए। अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस सड़क से सदन तक टुकड़ों-टुकडों में बंट गई है। उसमें न तो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां दिखती हैं और न ही 2023 का रोडमैप।

पार्टी में अंदरूनी खींचतान के चलते ही कांग्रेस कई ऐसे फैसले लेती दिखती है, जिससे वह हिट विकेट हो जाती है। ऐसे ही फैसलों में शामिल है चौरसिया का कांग्रेस में आगमन। वह उसी ग्वालियर से आते हैं, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के भाजपा में आने से कांग्रेस कमजोर हुई है। तो क्या चौरसिया के आने से इसकी भरपाई हो सकेगी? उनके कद को समझने वाले इसे महज मजाक ही मानेंगे। ऐसा भी नहीं कि गोडसे को पूजने वाले दूसरे लोगों का कांग्रेस में रूझान बढ़ेगा। तो चौरसिया को कांग्रेस में लाने के क्या मायने हो सकते हैं? क्या ये कांग्रेस में नई लकीर खींचने की शुरुआत है या आलाकमान को खास संदेश देने कोशिश है।

ये प्रदेश अध्यक्ष पद और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की खींचतान से जोड़ने वाले उपचुनाव में कमलनाथ के बयान की याद दिलाते हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा की महिला प्रत्याशी को आइटम कह दिया था। इस पर राहुल गांधी ने खेद जताया, माफी मांगने को कहा, लेकिन कमलनाथ ने दो टूक जवाब दिया था कि जो कह दिया, सो कह दिया। उपचुनाव में प्रचार अभियान में प्रियंका गांधी को भी आना था, लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया था। उपचुनाव में कमलनाथ की मप्र में धूमिल उम्मीदों के बाद जब उन्होंने केंद्रीय संगठन की ओर रूख करने की कोशिश की तो राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने की सुगबुगाहट के बीच उन्होंने स्पष्ट किया था कि मप्र से वह कहीं नहीं जा रहे है। अब चौरसिया का आगमन है, तो इसके भी मायने जल्द ही स्पष्ट होने की उम्मीद की जा सकती है।

● **अरविंद नारद**

दोहरी विचारधारा और अंदरुनी खींचतान के भंवर में कांग्रेस

क्या महात्मा गांधी को लेकर कांग्रेस की दोहरी विचारधारा है? क्या पार्टी की ताकत बढ़ाने गोडसे प्रशंसक का साथ जरूरी हो चुका था? या मप्र में कमलनाथ को विदा करने की पटकथा लिखी जा चुकी है? ऐसे कई सवाल हैं, जिसका सामना कांग्रेस कर रही है, बाबूलाल चौरसिया को अपने साथ लेकर। चौरसिया का सियासी कद भले ही ग्वालियर के पूर्व पार्षद जैसा जमीनी हो, लेकिन उनकी पहचान गोडसे को पूजने वाले के रूप में रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस में शामिल किया, जिससे पार्टी खुद सवालों के घेरे में है। कांग्रेस खुद को महात्मा गांधी से जोड़कर ही पेश करती रही है। गांधीवाद के नाम पर उसके कई फैसले तुष्टीकरण की हद भी पार कर गए। गांधीवाद को ही आगे रखकर भाजपा को सांप्रदायिक, तो क्षेत्रीय पार्टियों को अवसरवादी ठहराया। हालांकि गठबंधन के दौर में इन्हीं क्षेत्रीय दलों के साथ सत्ता में भागीदार भी बनी, लेकिन जिस नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, उसे ही पूजने वाले का साथ पार्टी की दोहरी या कहें विपरीत विचारधारा दर्शाता है, जो सवाल खड़े करता है कि क्या कांग्रेस ने गोडसे को माफ कर दिया या गांधी को भुला दिया? दरअसल, चौरसिया का कांग्रेस में आना पार्टी में अंदरूनी खींचतान का हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश के हालात की झलक देखने को मिलती है। सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है। इस कारण प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। उधर, सरकार को विकास योजनाओं के लिए हर माह लगभग 1 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ रहा है।

कमाई से ज्यादा खर्च

जिस तरह घर को चलाने के लिए बजट की जरूरत होती है, उसी तरह सूबे या मुल्क की गाड़ी बेफिक्री से चलाने के लिए सरकार के खजाने में दौलत होनी चाहिए। लेकिन मप्र का राजकोष खाली है। कमाई से ज्यादा खर्च है, राज्य का इस साल का जितना बजट है, उससे ज्यादा कर्ज है, आय से ज्यादा कर्ज पर ब्याज का बोझ है। ऐसे में सबके जेहन में एक ही सवाल है कि 'कर्ज पर निर्भर मप्र' कैसे 'आत्मनिर्भर मप्र' बनेगा? यही इन दिनों चिंता का सबसे बड़ा सबब है। बता दें कि मप्र पर कर्ज का बोझ बढ़कर इस वित्तीय वर्ष में 2.52 लाख करोड़ से भी ऊपर जा पहुंचेगा, अभी यह कर्ज 2.31 लाख करोड़ है, जबकि साल 2021-22 का कुल बजट ही 2.41 करोड़ 375 करोड़ है, जबकि उसमें करीब 50,938 करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस की महंगाई की मार से कराह रही जनता को राहत तो दूर की कौड़ी रही, क्योंकि इसकी झलक तो बीते दिनों बजट के पेश होने के एक दिन पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में दिख गई थी, जिसने राज्य की कंगाली की तस्वीर को सामने लाकर रख दिया था।

बजट से एक दिन **पहले पेश राज्य के आर्थिक** सर्वे में बताया गया था कि कोरोनाकाल में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 3 हजार 288 रुपए से घटकर सालाना 98 हजार 418 रुपए रह गई है यानी प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी 4 हजार 870 रुपए घटी है। 2020 की स्थिति में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 30 लाख के करीब हो गई है। 10 लाख से ज्यादा छोटे, मझोले उद्योग-धंधे बंद हो गए। यह आंकड़ा तो एक साल पुराना है, जबकि कोरोनाकाल ने कितने लाख उद्योग-धंधों पर ताला डलवाया है, ये इस गिनती में शामिल नहीं है। राज्य की जीडीपी में 3.37 फीसदी और विकास दर में 3.9 फीसदी गिरावट की बात क्या करें, क्योंकि यह तकनीकी भाषा और गुणा-भाग आमआदमी नहीं समझता। सरकार की माली हालत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है, कि वह किसानों की फसल बीमा के करीब 180 करोड़ का भुगतान नहीं कर सकी है। हर महीने वेतन, पेंशन, ब्याज चुकाने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है।

जब हम गले-गले कर्ज में डूबे हों, तो विकास योजनाएं कैसे चलेंगी, कैसे मप्र आत्मनिर्भर बनेगा, यह एक बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए है कि राज्य की आमदनी 76,656 करोड़ है, लेकिन वेतन, पेंशन और ब्याज चुकाने के लिए सरकार को 85,499 करोड़ की जरूरत है। यानी इन कामों के लिए ही सरकार को कुल आय से 8 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम जुटानी होगी। खनिज हो या आबकारी, अधिकांश विभागों से मिलने वाले राजस्व में कमी आई है, सरकार को अकेले बिजली कंपनियों का 34 हजार करोड़ का कर्ज चुकाना है, जो वह नहीं दे रही है और बिजली कंपनियां अपनी कंगाली, खस्ताहाली को दूर करने के लिए आमआदमी के लिए बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मतलब साफ है कि **महंगाई की आग** में आम जनता को झुलसना है। अगर सरकार को गांव, गरीब, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, उद्योग सहित कोई भी योजना संचालित करना या कोई काम करना है, तो उसके लिए उसे केंद्र सरकार पर निर्भर रहना होगा, या बाजार से कर्ज लेना पड़ेगा। मप्र राज्य विधानसभा में बजट पर पिछले दो दिन से चर्चा हो रही है, सरकार तो अपनी सक्षमता को लेकर तमाम दलीलें पेश कर रही हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सब एक ही सवाल कर रहे हैं कि कर्ज पर निर्भर मप्र आत्मनिर्भर मप्र में कैसे तब्दील होगा। मसलन कांग्रेस के युवा नेता जयवर्धन सिंह ने बजट पर चर्चा में कहा कि सरकार को बजट घोषणाओं पर काम करने के लिए नए वित्तीय वर्ष में 50 हजार करोड़ का और कर्ज लेना पड़ेगा। इससे तो बजट से ज्यादा सरकार पर कुल कर्ज हो जाएगा। साफ है कि सरकार आत्मनिर्भर मप्र नहीं, बल्कि कर्ज निर्भर मप्र बना रही है। किसान कर्जमाफी की रकम भी पिछले बजट में रखी गई 8 हजार करोड़ से घटाकर मात्र 3 हजार करोड़ कर दी गई है। पूर्व वित्तमंत्री तरूण भानोट ने कहा कि केंद्र ने राज्यांश में 12 हजार करोड़ घटा दिए, लेकिन शिवराज सरकार कर्ज लिमिट बढ़ाए जाने से खुश है। इस साल 21 हजार करोड़ सिर्फ कर्ज पर ब्याज के चुकाए गए हैं, **यानी 60 करोड़ रुपए रोज** यानी ढाई करोड़ रुपए प्रति घंटे हम ब्याज दे रहे हैं, हर साल 30 से 40 हजार करोड़ का कर्ज सरकार पर बढ़ता जा रहा है, इसी अनुपात में ब्याज की रकम भी सालाना करीब 3 से 4 हजार करोड़ बढ़ती जा रही है।

● **जितेंद्र तिवारी**

11 महीनों में 23 हजार करोड़ कर्ज

कोरोनाकाल के 11 महीनों में मप्र सरकार 23 हजार करोड़ कर्ज ले चुकी है। साल 2018 के अंत में राज्य पर कुल कर्ज 1 लाख 80 हजार करोड़ था, जो अब बढ़कर 2 लाख 31 हजार करोड़ तक जा पहुंचा है और इस वित्त वर्ष की समाप्ति तक 2 लाख 52 हजार करोड़ हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि सरकार के पास केवल वेतन देने लायक पैसा ही बच पाता है। हर महीने ओव्हर ड्राफ्ट की स्थिति से बचने के लिए सरकार को बाजार अथवा केंद्र सरकार से कर्ज लेना पड़ता है। जितने बुरे हाल अभी हैं, ऐसी स्थिति 2003 में दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के अंतिम दिनों में पैदा हुई थी।

मप्र में डेढ़ हजार शौचालय गायब

मप्र के सरकारी स्कूलों में कहीं शिक्षक नहीं हैं तो कहीं शौचालय व बिजली कनेक्शन का अभाव है। ऐसे में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना मुश्किल है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। यहां के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। बता दें कि प्रदेश में करीब 1 लाख 20 हजार सरकारी स्कूल हैं। मूलभूत सुविधाओं में मप्र के स्कूल 17वें स्थान पर मप्र के 67 हजार प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में बिजली कनेक्शन तो 50 हजार में चारदीवारी नहीं है। 1900 स्कूलों का अपना भवन ही नहीं है। करीब 6 हजार स्कूल एक-दो कमरों में चल रहे हैं। इसका खुलासा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फरवरी में एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किया था। इसमें मप्र के स्कूलों को ग्रेड-2 में रखा गया था और मूलभूत सुविधाओं में देश में 17वें स्थान पर था। गोवा पहले, चंडीगढ़ दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर था।

प्रदेश के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में तीन साल पहले बालक-बालिका के लिए अलग-अलग शौचालयों का निमार्ण किया जाना था। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शौचालय बनाने के लिए राशि भी स्वीकृत की गई। अब विभाग को बालिकाओं के लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बने करीब डेढ़ हजार शौचालयों की जानकारी ही नहीं है। प्रदेश में पंचायती राज संचालनालय की स्वीकृति से सितंबर 2018 में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में बालकों के लिए 2285 एवं बालिकाओं के लिए 1591 शौचालय स्वीकृत किए गए थे, लेकिन बनने के तीन साल बाद भी 1591 बालिका शौचालयों के निर्माण के लिए एजेंसियों को भुगतान नहीं हुआ है। अब स्कूल शिक्षा विभाग यह पता कर रहा है कि यह शौचालय किस मद या योजना के तहत बनाए गए थे और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। जिससे बजट को तलाशकर निर्माण एजेंसियों को भुगतान किया जा सके।

राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त धनराजू एस ने इस पुरानी फाइल को निकालकर इस पर जिले के कलेक्टर्स से तीन दिन में जवाब मांगा है। अब राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टर्स को पत्र जारी करके इन शौचालयों के निर्माण, किस मद से, किस योजना के तहत बनाए गए। इसकी जानकारी मांगी है। मप्र में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं। शिक्षा के स्तर सकारात्मक बदलाव के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी और खुद मंत्री विदेशों के दौरे कर रहे हैं। लेकिन, प्रदेश के स्कूलों की तस्वीर कुछ और ही हकीकत बयां करती है। राजधानी भोपाल के शासकीय माध्यमिक शाला स्कूल में पिछले तीन साल से शौचालय नहीं है। शौचालय के लिए छात्र-छात्राओं को पास ही स्थित सुलभ कॉम्पलेक्स में जाना पड़ता है। छात्राएं स्कूल तो आना चाहती हैं, लेकिन स्कूल में शौचालय नहीं होना छात्राओं के लिए परेशानी का सबब बन रहा है।

राजधानी भोपाल जहां प्रदेश के तमाम मंत्री बैठते हैं। खुद शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के तमाम आला अधिकारी भी भोपाल में जमे रहते हैं। लेकिन, यहां के स्कूल की छात्राओं की जरूरत से अनजान बने हुए हैं। स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि शौचालय नहीं होने की वजह से बच्चियों को बहुत परेशानी होती है। हमें बच्चियों की सुरक्षा की भी चिंता होती है। शौच के लिए बाहर गई बच्चियों को लेकर हमेशा मन में डर बना रहता है कि कहीं अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। शिक्षिका ने बताया कि पिछली सरकार से लेकर तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री तक से गुहार लगा चुकी हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 'हम शिक्षिकाओं को भी सुलभ कॉम्पलेक्स में ही शौच के लिए जाना होता है। वहीं छात्राओं का कहना है कि स्कूल से सुलभ कॉम्पलेक्स तक यूनिफॉर्म में जाने पर शर्म आती है। सड़क पर आने-जाने वाले सभी लोगों की नजरें हम पर ही टिकी होती हैं।

पंचायती राज संचालनालय ने 2018 में बालकों के लिए 2285 एवं बालिकाओं के लिए 1591 शौचालय मिलाकर कुल 3 हजार 876 शौचालयों के लिए 52 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इन शौचालयों का निर्माण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना था। गांवों में शौचालयों के निर्माण के बाद बालकों के 2285 निर्माण के लिए तो राशि जारी हुई, लेकिन बालिका शौचालयों के लिए राशि जारी नहीं हुई। इस संबंध में 2019 में भी विभाग ने पता किया, लेकिन जानकारी नहीं मिल सकी।

● **नवीन रघुवंशी**

इन जिलों में बालक के लिए इतने शौचालय स्वीकृत किए गए

● आलीराजपुर	–	105
● बालाघाट	–	305
● सिंगरौली	–	171
● बैतूल	–	119
● बड़वानी	–	122
● श्योपुर	–	115
● उज्जैन	–	93
● मंदसौर	–	87
● गुना	–	149
● दमोह	–	88
● धार	–	94
● अनूपपुर	–	98
● अशोकनगर	–	84

इन जिलों में सबसे अधिक बालिकाओं के लिए स्वीकृत शौचालय

● बालाघाट	–	231
● सिंगरौली	–	192
● श्योपुर	–	137
● अशोकनगर	–	104
● गुना	–	95
● भिंड	–	94
● रीवा	–	94
● दमोह	–	89
● उज्जैन	–	86
● आलीराजपुर	–	40
● डिंडौरी	–	65
● खरगोन	–	77

कैसे पूरा होगा मेट्रो का सपना

सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक भोपाल और इंदौर में मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू करवा दे। लेकिन प्रदेश सरकार के बजट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार अभी मेट्रो ट्रेन चलाना नहीं चाहती। बजट में भोपाल और इंदौर मेट्रो के लिए कुल 262 करोड़ की राशि रखी गई है। इसे दोनों शहरों में आधी-आधी भी बांटें तो एक के हिस्से में 131 करोड़ रुपए आते हैं। इतनी कम राशि से 2030 तक भी प्रोजेक्ट का पूरा होना मुश्किल लगता है। भोपाल मेट्रो के लिए 6 हजार 941 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसमें से अब तक करीब 170 करोड़ रुपए एम्स से सुभाष नगर तक एलीवेटेड रूट बनाने में खर्च किए जा चुके हैं, जबकि यह राशि महज 6 किमी का रूट बनाने में खर्च हुई है। अब जो रूट बनाया जा रहा है, वह करीब 9 किमी से अधिक है। इसमें से दो किमी का रूट अंडरग्राउंड है। इसके चलते 300 करोड़ रुपए तो सिर्फ टेंडर में ही खर्च हो जाएंगे। इधर, मेट्रो के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। डिपो और स्टेशनों के टेंडर किए जाने हैं। इस तरह बजट में मिली राशि मेट्रो को गति देने के लिए काफी कम है। इधर, मेट्रो से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि सुभाष नगर फाटक के पास मेट्रो का डिपो बनाने के लिए 65 एकड़ जमीन आरक्षित है। वहीं मेट्रो के पहले रूट पर करीब 16 स्टेशन बनाए जाने हैं। इतना ही नहीं, मेट्रो का पर्पल रूट 12.99 किमी का है। भदभदा से रत्नागिरी तक बनाए जा रहे इस रूट का टेंडर भी जारी किया जाना है। इससे भी प्रोजेक्ट रुक-रुककर चलने की आशंका है।

इंदौर मेट्रो के पहले चरण का प्रोजेक्ट ही 31 किमी का है। उसमें भी पहला ट्रैक 5.29 किमी का है। पहले चरण की लागत है 7500.08 करोड़ रुपए। 2021-22 के बजट में यदि 131 करोड़ की राशि खर्च भी होती है तो यह पहले चरण की राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा भी नहीं है। यानी पहले 5 किमी का काम 2023 तक पूरा हो पाएगा, इसमें संशय है। ऐसे में पहला चरण 2030 तक पूरा होना भी मुश्किल है।

इंदौर में 27 महीने में 5.29 किमी ट्रैक तैयार होने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 26 माह गुजरने के बाद पिलर खड़े किए जाने का काम शुरू हुआ है। मेट्रो ट्रेन के कुल 31.55 किमी के रूट में से नवंबर 2018 में 5.29 किमी रूट का टेंडर और वर्कऑर्डर हुआ था, लेकिन ठेकेदार कंपनी दिलीप बिल्डकॉन और जनरल कंसल्टेंट के विवाद और अधिकारियों की सुस्ती के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई। इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को 4 साल हो गए हैं, लेकिन इसका काम 1 फीसदी भी नहीं हुआ। इसे बेपटरी करने के लिए जिम्मेदार हटाए गए टेक्निकल डायरेक्टर जितेंद्र दुबे की गलतियों के कारण प्रोजेक्ट अटक गया। सबसे पहले जनवरी 2018 में इंदौर मेट्रो के लिए जियो टेक्निकल सर्वे शुरू हुआ, इसे तकनीकी गड़बड़ी बताकर बीच में ही रोक दिया गया। इससे प्रोजेक्ट के अंडर ग्राउंड काम की रूपरेखा ही नहीं बन सकी। फिर इंदौर मेट्रो के लिए सिस्मिक जोन-2 से बढ़ाकर 3 किया और फिर जानबूझकर जोन 4 के हिसाब की प्लानिंग करवाई। एमपीएमआरसीएल का एक भी अफसर पदस्थ नहीं किया गया, जिससे जनरल कंसल्टेंट निरंकुश हो गए। उसके बाद दिलीप बिल्डकॉन द्वारा दी गई 127 ड्राइंग डिजाइन जीसी ने रोकी। इसमें टेक्निकल डायरेक्टर का जिम्मा था उसका समाधान करें। लॉकडाउन में पूरे देश में काम चला, इंदौर मेट्रो का काम कलेक्टर की अनुमति के बाद भी शुरू नहीं हुआ। फिर 29 स्टेशन में किसी की भी ड्राइंग या डिजाइन फाइनल नहीं हो सकी। मेट्रो के कोच का न अभी तक ऑर्डर दिया गया और न उनकी डिजाइन फाइनल हो सकी। इस कारण से चार साल में एक फीसदी भी काम नहीं हो पाया।

इंदौर शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम जैसे-तैसे दिसंबर-2020 के अंत में शुरू हुआ था, जो अब फिर बंद हो गया है। एमआर-10 ब्रिज के पास जिन दो पिलरों के निर्माण का काम पिछले साल शुरू हुआ था, वह दो महीने से ठप पड़ा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर न तो सरकार गंभीर है, न ठेकेदार कंपनी और न ही कंसल्टेंट फर्म। पहले सरकार के अफसरों ने सपने दिखाए थे कि इंदौर में 2023 तक मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, लेकिन मौजूदा स्थिति देखकर तो 2025 तक भी काम पूरा होता हुआ नहीं दिखता। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमिपूजन 14 सितंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 31.50 किमी है, जिसके निर्माण पर 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा के खर्च का अनुमान है। शहर का पहला मेट्रो कॉरिडोर एयरपोर्ट से सुपर कॉरिडोर, एमआर-10, रिंग रोड, कनाड़िया रोड, एमजी रोड, राजवाड़ा, बड़ा गणपति होते हुए फिर एयरपोर्ट पर मिलेगा। यह कॉरिडोर रिंग के रूप में रहेगा। काम की शुरुआत एमआर-10 से मुमताजबाग के बीच लगभग 5.27 किमी लंबे हिस्से में होना थी, लेकिन अब तक वहां पिलर भी नहीं बन पाए हैं। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि इंदौर के पहले कॉरिडोर के पहले हिस्से की लागत ही 237 करोड़ रुपए है। प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित राशि में भोपाल का भी हिस्सा शामिल है। ऐसे में काम कैसे होगा, कहना मुश्किल है।

अब तक मेट्रो प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंदौर में बेरिकेडिंग लगाने-हटाने के अलावा ज्यादा काम नहीं हुआ है। कुछ जगह डिवाइडर और उनमें लगे पेड़-पौधे जरूर हटाए गए हैं, लेकिन पिलर निर्माण ही बंद है। नगर निगम ने मेट्रो कॉरिडोर में बाधक रोटरियों और प्रतिमाओं की शिफ्टिंग भी अब तक नहीं की है। ठेकेदार कंपनी, कंसल्टेंट और सरकार के बीच समन्वय नहीं होने से यह स्थिति बनी है। पिछले महीने बिजली ट्रांसमिशन ने एमआर-10 से गुजर रही हाईटेंशन को शिफ्ट करने से पहले वैकल्पिक लाइन बिछाने का काम शुरू किया था, लेकिन इसकी गति भी बेहद धीमी है।

● **विकास दुबे**

उम्मीद... लोन की पहली किश्त की

मेट्रो बोर्ड का गठन पिछले साल दिसंबर में हो पाया है। इसमें केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं। केंद्र सरकार बोर्ड के गठन के बाद ही राशि देती है। आमतौर पर राज्य सरकार जितना प्रावधान करती है, लगभग उतना ही अनुदान केंद्र का होता है। इस हिसाब से 250 करोड़ रुपए तक केंद्र से मिल सकते हैं। साथ ही लोन की पहली किश्त भी मिल सकती है। यूरोपियन इंवेस्टमेंट बैंक हर निर्माण के हिसाब से सरकार के अनुदान के आधार पर लोन देगा।

गलतियों को सुधारने की पहल

मप्र में इन दिनों शहरों, नदी, नालों, सड़क, चौराहों का नाम बदलने की जैसे होड़ लगी हुई है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि ऐतिहासिक गलतियों को सुधारा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने का ऐलान किया है, तो उमा भारती चाहती हैं कि हलाली नदी का नाम बदला जाए। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने की दिशा में मप्र सरकार अब एक कदम और आगे बढ़ गई। गत दिनों मप्र विधानसभा में इस संबंध में अशासकीय संकल्प पेश किया गया। जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। सरकार के इस प्रस्ताव को विपक्ष का भी साथ मिल गया। विधानसभा में मंजूरी के बाद अब ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र से मंजूरी के बाद होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। इसी के साथ मप्र में अब नाम बदलने की राजनीति की औपचारिक शुरुआत हो गई।

मप्र में इन दिनों नाम बदलने की राजनीति चल रही है। घोषणाओं और मांग की शुरुआत तो गुरुपर्व के दिन से शुरू हो गई थी। अब इसकी औपचारिक और वैधानिक शुरुआत गत दिनों हो गई। सदन की मंजूरी के बाद सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजकर इस बात की मांग करेगी कि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाए। यह सच है कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के अनेक शहरों के नाम बदलकर इतिहास के साथ छेड़खानी की। इसके साथ उन्होंने यहां की संस्कृति और परंपराओं को भी प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश की। यह अलग बात है कि भारतीय समाज की जीवटता के कारण हमारी संस्कृति का अस्तित्व बचा रहा। कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेजों ने हमारे अस्तित्व को नए रंग में रंगने का प्रयास किया। इन थोपे गए नामों को बदलकर शहरों को उनकी पुरानी पहचान दिलाने का काम अब मप्र में भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समय की मांग और सियासी जरूरत को समझ चुके हैं। अब वह नाम बदलने को लेकर ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं।

हाल में मुख्यमंत्री ने नर्मदा किनारे बसे होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने की घोषणा की थी। इसके दो दिन बाद ही जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचे तो सभा में मौजूद जनसमुदाय की मांग पर तुरंत नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरुंदा करने की घोषणा कर दी। इन शहरों के नाम की कहानी भी दिलचस्प है। सबसे पहले बात होशंगाबाद की। नर्मदा किनारे बसे इस शहर का नाम पहले नर्मदापुर था। इतिहासकारों के मुताबिक मांडू का सुल्तान हुशंगशाह यहां आया था। तब उसने नर्मदापुर का नाम बदलकर होशंगाबाद रख दिया था। परमारकालीन ताम्रपत्र में भी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुर होने का उल्लेख मिलता है। 2009 में शिवराज सरकार ने जब होशंगाबाद को संभाग का दर्जा दिया तो स्थानीय लोगों की मांग पर संभाग का नाम नर्मदापुरम रख दिया, लेकिन शहर का नाम होशंगाबाद ही रहने से इसे ज्यादा पहचान नहीं मिली।

अब थोड़ी चर्चा नसरुल्लागंज की करते हैं। इस छोटे से शहर का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। इसका नाम भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान के बड़े भाई के नाम पर रखा गया था। इतिहासकार असर किदवई के मुताबिक भोपाल की नवाब सुल्तान जहां बेगम ने अपने सबसे बड़े बेटे नसरुल्ला खान को भोपाल रियासत में ही भेरुंदा नाम की जागीर दी थी। बाद में उन्हीं के नाम पर भेरुंदा का नाम नसरुल्लागंज कर दिया गया। कहा जाता है कि नसरुल्लागंज में जिस समाज का बाहुल्य था, उनके आराध्य भेरु भगवान थे, इसलिए नगर का नाम भेरुंदा रखा गया था। वैसे मप्र में कई अन्य शहरों के भी नाम बदलने को लेकर काफी दिनों से मांग की जा रही है। पहली मांग तो मप्र की राजधानी भोपाल की ही है। राजा भोज की नगरी का नाम भोजपाल किए जाने को लेकर कई दशकों से मांग उठ रही है।

इतिहासकार भी इससे सहमत हैं कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए। भोपाल से राजा भोज का नाम जोड़ने के लिए ही शिवराज ने कई वर्ष पहले भोजताल में राजा भोज की आदमकद प्रतिमा लगाई। गौरतलब है कि भोपाल में परमारवंशी राजाओं का शासन रहा है, जिन्होंने राजधानी के समीप भोजपुर मंदिर का भी निर्माण कराया था। इसके अलावा उज्जैन का नाम उज्जयनी करने की मांग भी की जा चुकी है। संस्कारधानी जबलपुर को भी महाकौशल के लोग जबालीपुरम का नामकरण चाहते हैं। नर्मदा तट पर बसे **इस शहर का नाम जबाली नामक एक ऋषि** के नाम पर पड़ा था। बाद में यह जबलपुर में तब्दील हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भोपाल के पास स्थित हलाली डैम का नाम बदलने की मांग भी पिछले दिनों की थी। वहीं विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रहे रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में ईदगाह हिल्स का नाम गुरुनानक टेकरी करने को लेकर लंबा अभियान चलाया। इसी तरह ओबेदुल्लागंज, बेगमगंज, गैरतगंज, शाहगंज, सुल्तानपुर, इस्लामपुरा सहित कई नाम ऐसे हैं जिन्हें बदलने की मांग भी उठ रही।

● **प्रवीण कुमार**

अहिल्या बाई महान या मंत्रीजी के दादाजी?

भाजपा के तमाम छोटे-बड़े नेता अपने-अपने इलाकों के नाम बदलकर नए नाम रखने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इस मुहिम के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और दलबदल कर शिवराज सरकार में मंत्री बने महेंद्र सिंह सिसौदिया ने गुना में तो देवी अहिल्या बाई होलकर के नाम से बने एक चौराहे का ही नाम बदलकर अपने दादाजी स्व. सागर सिंह सिसौदिया के नाम पर रखवा लिया। चौराहे के लिए जमीन दान करने वालों और स्थानीय लोगों ने जब बवाल काटा, तो चौराहे पर बदले हुए नाम का शिलालेख का फीता काटने अपने समर्थक मंत्री के साथ पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों को धमकाते हुए चेतावनी भी दे डाली कि शुभ कार्य में उठापटक ठीक नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ये चौराहा ही नहीं, बल्कि न्यू टेकरी सड़क भी मंत्रीजी के दादाजी के नाम से जानी जाएगी। सिंधिया ने न सिर्फ जमीन के दानकर्ताओं को फटकार लगाई, बल्कि गुना नगर पालिका परिषद से कहा कि यहां मंत्रीजी के दादाजी की प्रतिमा और उनकी इतिहास पट्टिका भी लगाई जाए।

3 साल में हर घर नल से जल

मप्र के 51 हजार से अधिक गांवों के हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम मिशन स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा-निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव की निगरानी में नल-जल योजना प्रगति पर है। सरकार की कोशिश है कि 3 साल में प्रदेश के सभी गांवों के सभी घरों में नल से जल पहुंच जाए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूर्ववर्ती शासनकाल में प्रदेश की शहरी आबादी को जरूरत का पानी मुहैया कराने के बाद अपनी चौथी पारी में ग्रामीण आबादी को नल से जल उपलब्ध कराने का प्लान बनाया है। मप्र के 52,557 गांवों में से अधिकांश गांवों में लोग नदी, तालाब, कुंआ अथवा बावड़ी से पानी भरते हैं। लेकिन सरकार ग्रामीण आबादी को नल से जल मुहैया करवाने की योजना पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से घोषणा की थी कि देश की समूची ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उनके घर पर ही नल कनेक्शन के जरिए दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की गाइडलाइन जारी की। मिशन के मुताबिक गांव के हर परिवार को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने पर होने वाले व्यय की 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी तथा 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार को वहन करना है।

नल जल मिशन को पूरा करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने जो प्रेजेंटेशन तैयार किया है, उसकी खूब सराहना हो रही है। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में मिशन को पूरा करने की एक-एक बारीकी का उल्लेख किया है। उनके प्रेजेंटेशन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि योजना समय पर पूरी हो जाएगी।

जल जीवन मिशन को समय पर पूरा करना लक्ष्य

मप्र के ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल से जल पहुंचाने के मिशन पर जिस तेजी से काम हो रहा है, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खूब प्रशंसा की है। प्रदेश में जल जीवन मिशन को समय पर साकार करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि प्रदेश में हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना तेजी से प्रगति कर रही है। प्रदेश सरकार भी श्रीवास्तव के काम से संतुष्ट है। उधर, एसीएस श्रीवास्तव का सबसे अधिक फोकस इस समय जल जीवन मिशन पर ही है। वे लगातार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं, जिससे यह मिशन तेजी से पूरा हो रहा है।

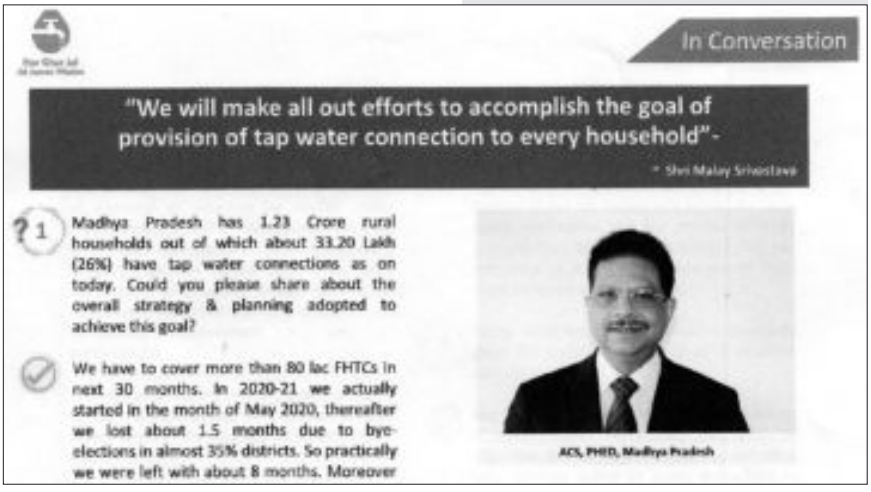

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की करीब सवा 5 करोड़ ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन के जरिए गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इससे प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को जल जीवन मिशन से मिली गति और ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन। मिशन के जरिए दिसंबर 2020 तक 30 लाख से ज्यादा नल कनेक्शन दिए गए हैं। इससे 1,473 ग्राम शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन युक्त हो चुके हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम प्रदेश के सभी ग्रामीण अंचल के हर परिवार तक नल कनेक्शन से जल पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाने के लिए 13 हजार 530 करोड़ की लागत की एकल और समूह जलप्रदाय योजनाओं पर कार्य जारी है।

देश के 7 बड़े राज्यों में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मप्र अग्रणी 3 राज्यों में शामिल है। प्रदेश में मिशन के क्रियान्वयन का लक्ष्य योजनाबद्ध और सामयिक अनुपात में निर्धारित किया गया है। ग्रामीण आबादी के अनुसार प्रत्येक 5 सदस्यीय परिवार को आधार मानकर 1 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन दिए जाना होंगे। वर्ष 2020-21 में 26 लाख 26 हजार, वर्ष 2021-22 में 33 लाख 74 हजार, वर्ष 2022-23 में 28 लाख 76 हजार तथा वर्ष 2023-24 के दिसंबर माह तक 14 लाख 75 हजार नल कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। मलय श्रीवास्तव कहते हैं कि हम समय पर मिशन को साकार कर देंगे।

● **लोकेंद्र शर्मा**

ठेकेदार पर मेहरबानी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ एक तरफ अपने उत्पादों को महंगा कर उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ डाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ संघ में वर्षों से मैन पावर सप्लाई करने वाले ठेकेदार को नियमों को ताक पर रख फायदा पहुंचा रहा है। अभी हाल ही में सांची का घी 25 रुपए महंगा कर दिया गया। इससे लोगों में आक्रोश है और उनका कहना है कि अगर संघ ठेकेदार को फायदा पहुंचाना बंद कर दे तो उत्पादों को महंगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ जो काम खुद कर सकता है, उसके लिए जबरन सालाना 10 करोड़ 80 लाख रुपए चुका रहा है। यह राशि मेसर्स गोपाल विश्वास लेबर कांट्रेक्टर नामक फर्म को दी जा रही है। फर्म संघ में 1100 से अधिक ठेका श्रमिक सप्लाई करती है। जिसे संघ सुविधा शुल्क के नाम पर यह राशि दे रहा है। संघ खुद श्रमिकों से काम लेने लगे तो सालाना 10 करोड़ 80 लाख रुपए की सीधी बचत होगी। महंगाई के दौर में इस राशि का फायदा सांची दूध व उत्पादों की कीमत कम करके उपभोक्ताओं को दी जा सकती है। साथ ही किसानों से खरीदे जाने वाली दूध की कीमत बढ़ाकर उन्हें भी राहत पहुंचाई जा सकती है। भोपाल सहकारी दुग्ध संघ रोजाना 3 लाख लीटर से अधिक दूध का कारोबार करता है। इसके लिए 1100 से अधिक ठेका श्रमिकों की सेवाएं ली जा रही हैं। संघ इन श्रमिकों को हर माह 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का मानदेय भुगतान करता है। यह राशि पहले निजी फर्म को दी जाती है और निजी फर्म उक्त राशि को श्रमिकों को भुगतान करता है। इसके बदले फर्म को सुविधा शुल्क का भुगतान संघ कर रहा है।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने एक ठेकेदार के ठेके की अवधि को बार-बार बढ़ाकर 66 करोड़ 8 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया है। यह फायदा 10 साल में पहुंचाया गया है। ठेका फर्म मेसर्स गोपाल विश्वास **लेबर कांट्रेक्टर** है जो संघ को श्रमिक सप्लाई करती है। उक्त फर्म को संघ ने यह राशि सेवा शुल्क के नाम पर भुगतान की है। अभी भी उक्त फर्म को सेवा शुल्क भुगतान किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि संघ ने अकेले सेवा शुल्क के नाम पर 66 करोड़ 8 लाख रुपए दिए हैं, श्रमिकों के वेतन भुगतान की राशि अलग है, जो अरबों रुपए में है। बता दें कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ रोजाना 3 लाख लीटर दूध का कारोबार करता है। यह दूध किसानों से खरीदकर संघ में लाता है और यहां प्रोसेसिंग करने के बाद पैकिंग करके उपभोक्ताओं को पहुंचाता है। इसके काम के लिए 1000 से अधिक श्रमिकों की जरूरत पड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि संघ यह काम खुद करे तो सेवा शुल्क में दी जाने वाली राशि बचेगी। इसका फायदा सांची दूध की कीमत कम करके उपभोक्ताओं को दे सकते हैं। किसानों से दूध खरीदी के दाम बढ़ा सकते हैं।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और सागर दुग्ध संघ से बचत करने के मामले में पीछे है। भोपाल संघ ठेका श्रमिक सप्लाई करने वाली मेसर्स गोपाल विश्वास लेबर कांट्रेक्टर फर्म को हर माह 10 फीसदी सेवा शुल्क चुका रहा है। यह तब है, जबकि इंदौर, जबलपुर, सागर दुग्ध सहकारी दुग्ध संघ इसी काम के लिए ठेकेदारों को सिर्फ 1 फीसदी और उज्जैन 1.5 फीसदी शुल्क देते हैं। दूसरे संघों की तुलना में भोपाल संघ 9 फीसदी अधिक सेवा शुल्क देकर ठेकेदार को फायदा पहुंचा रहा है। उक्त ठेका फर्म को श्रमिकों के कुल वेतन की राशि पर 10 फीसदी राशि देता है, जो हर माह 10.50 लाख रुपए से अधिक होती है। इसका असर भोपाल समेत आसपास के तीन लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर पड़ रहा हैं। संघ बचत की राशि बेहिसाब खर्च कर रहा है और मुनाफे के लिए हर बार घाटा होने और लागत बढ़ने का हवाला देकर सांची दूध की कीमत बढ़ा देता है। संघ बचत करने लगे तो सांची दूध की कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने शुरुआत में फर्म से कुछ सालों के लिए अनुबंध किया था जो खत्म होने के बाद दोबारा ठेका दे दिया गया। साल 2018 में ठेका खत्म हो चुका है। अब उसे हर माह बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि निजी फर्म ने रजिस्ट्रार को-आपरेटिव सोसायटी से स्थगन लाया है जिसे खारिज करने के लिए भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने भोपाल संभागायुक्त कवींद्र कियावत के निर्देशन में प्रक्रिया शुरू कर दी है। संघ चाहता तो पूर्व में भी स्टे को खारिज करने के लिए ऊपरी अदालत जा सकता था जो कि नहीं गया।

दरअसल इंदौर, उज्जैन समेत दूसरे संघों में ठेका श्रमिक सप्लाई करने वाली फर्म को सुविधा शुल्क नाम मात्र का दिया जा रहा है। वहीं भोपाल संघ मनमर्जी से करोड़ों रुपए भुगतान कर रहा है। सूत्रों की माने तो **निजी फर्म** कुछ ठेका श्रमिकों को तय मानदेय से कम राशि भुगतान करती है। साथ ही और रिकार्ड में बराबर राशि दिखाई जा रही है। विरोध करने वाले कुछ ठेकाकर्मियों को निकाला जा चुका है। उक्त फर्म का ग्वालियर में भी ठेका होना बताया जा रहा है जहां ठेकाकर्मियों के शोषण के प्रकरण सामने आते रहे हैं। सूत्रों की माने तो उक्त फर्म को संघ के एक अधिकारी द्वारा संरक्षण प्राप्त होना बताया जा रहा है। सांची दूध की कीमत बीते साल बढ़ी थी। अब दोबारा बढ़ाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जबकि संघ सहकारी दुग्ध संघ है जिसका मकसद अनावश्यक खर्च कम करके उपभोक्ताओं को राहत देना होता है। सरकार की भी यही मंशा रही है। यही वजह है कि पूर्व में सरकार संघों को करोड़ों रुपए के नुकसान की भरपाई करती रही है।

● **सुनील सिंह**

किसानों को फायदा नहीं

संघ के पूर्व संचालक बलराम बारंगे का कहना है कि संघ घाटा बताकर किसानों से जब चाहे तब दूध खरीदी बंद कर देता है। वहीं निजी फर्मों को जबरन करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया जा रहा है। यह ठीक नहीं है। यदि सालाना सुविधा शुल्क के नाम पर ठेका श्रमिक सप्लाई करने वाली फर्म को दिए जाने वाले 10 करोड़ 80 लाख रुपए बचाकर उसका फायदा किसानों को दे तो वे समृद्ध होंगे। उपभोक्ताओं को भी कीमत में राहत देनी ही चाहिए।

बीहड़ में माफिया की खेती

कभी बागियों के लिए कुख्यात रहे बीहड़ (ग्वालियर-चंबल क्षेत्र) में इन दिनों माफिया की खेती हो रही है। रेत माफिया, पत्थर माफिया, शराब माफिया के साथ ही यहां ड्रग्स और दूध माफिया तेजी से पनप रहे हैं। अब तो यहां अवैध रूप से अफीम की खेती भी होने लगी है। गौरतलब है कि बीहड़ के दूध माफिया ने तो पूरे देशभर में जानलेवा नकली दूध, पनीर का कोरोबार ऐसा फैला दिया है कि उससे पार पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ग्वालियर-चंबल के कई जिलों में जानलेवा दूध और पनीर बनाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि प्रशासन ने कास्टिक सोडा, माल्टो डेक्सट्रिन पावडर, लिक्विड डिटरजेंट व खराब क्वालिटी के पॉम ऑयल के परिवहन व बिक्री को प्रतिबंधित नहीं किया है, इसलिए मिलावट पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। दूध माफिया ने अपने कारोबार का तरीका बदल लिया है। पुलिस व खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए आरएम केमिकल, माल्टो डेक्सट्रिन पावडर, स्किम्ड मिल्क पावडर, कास्टिक सोडा, लिक्विड डिटरजेंट, कमानी ब्रांड पॉम ऑयल सहित अन्य केमिकल को गोदाम विशेष में न रखकर अब ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग जगह छुपाकर रखा जा रहा है। केमिकल नहीं पकड़ा जाए, इसलिए कारोबारी अब केमिकल का घोल तैयार कर सीधे उसे बेच रहे हैं। दूध खरीद के काम में लिप्त लोग इस केमिकल घोल को केन में डालकर उसी में सपरेटा दूध भर लेते हैं।

परिवहन के दौरान केमिकल का घोल और सरपेटा दूध मिलकर अच्छी फैट का दूध बन जाता है। फैट चेककर इसी दूध को कंपनियां खरीद रही हैं। ऐसे ही **मामले में पोरसा** पुलिस ने 28 जनवरी को गंगाराम गली में रहने वाले दूध कारोबारी संतोष जैन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घोल व दूध से भरी केन जब्त की थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल प्रताप परिहार ने घोल व दूध के सैंपल लेकर उनकी जांच कराई तो दोनों सैंपल फेल पाए गए। घोल की जांच के बारे में भोपाल लैब के खाद्य विश्लेषक सिर्फ इतना बता पाए कि यह रिफाइंड ऑयल व बूरा मिश्रित घोल है। घोल में क्या-क्या केमिकल मिलाए गए, जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं है।

सबलगढ़ क्षेत्र में चंबल नदी के किनारे बीहड़ों विगत दिनों मुरैना जिले के सबलगढ़ में पुलिस ने अफीम की लहलहाती फसल पकड़ी है। ढाई से चार बीघा जमीन पर अफीम की खेती हो रही थी और इस फसल की ओट के लिए आसपास की जमीन में सरसों व गेहूं की फसल कर रखी थी। पुलिस ने अफीम के पौधों को काटकर जब्त कर लिया है। जिस हालत में फसल मिली है उसे देखकर लग रहा है कि आरोपित इससे पहले भी अफीम की खेती यहां कर चुके हैं। पुलिस के अनुसार 60 क्विंटल अफीम के पौधे मिले हैं। जिनकी कीमत 10 करोड़ बताई गई है।

एसपी एसके पांडेय को फोन पर एक ग्रामीण ने सूचना दी कि सबलगढ़ क्षेत्र के बटेश्वरा-चौकपुरा के बीहड़ों में अफीम की खेती हो रही है। यह क्षेत्र राजस्थान की सीमा व चंबल नदी किनारे दूरस्थ इलाके में है। सबलगढ़ थाने की एक टीम ग्रामीणों की वेशभूषा में भेजकर इसकी सत्यता परखी तो शिकातय को सही पाया गया। इसके बाद शाम को चार थानों की पुलिस टीम को बटेश्वरा-चौकपुरा के बीहड़ों में जगह-जगह अफीम की खेती लहलहाती मिली। अफीम के पौधे दो फीट से ज्यादा लंबे हो चुके थे और फूलों के साथ उनमें अफीम के डोंडे भी आने लगे थे। कुछ ही दिन में चीरा लगाकर अफीम निकालने का काम शुरू हो जाता, उससे पहले ही पुलिस ने इसे पकड़ लिया।

पुलिस के अनुसार इसका बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बीहड़ की जिस जमीन पर यह खेती हो रही थी, वह सरकारी थी, लेकिन इस पर चोखपुरा गांव के चार किसानों का कब्जा था। तहसील के रिकार्ड पर इनकी पहचान की गई और उसके बाद पुलिस ने कल्ला पुत्र हरीसिंह मल्लाह, मुन्ना पुत्र हरीसिंह मल्लाह, मुंशी पुत्र हरीसिंह मल्लाह और महेंद्र पुत्र छत्तू मल्लाह पर एफआईआर दर्ज की है। सबसे ज्यादा 3 बीघा में अफीम महेंद्र मल्लाह के खेतों में हो रही थी, इसलिए पुलिस नशे की इस खेती का मास्टर माइंड महेंद्र मल्लाह को मान रही है। अफीम की इस खेती में पुलिस को राजस्थान के अलावा दूसरी जगहों के कुछ तस्करों के शामिल होने का पूरा संदेह है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर खेती तभी हो सकती है जब इस खेती के कटने के बाद भारी मात्रा में होने वाली अफीम का कोई खरीदार हो। पुलिस को संदेह है कि यह लोग पहले भी इस तरह की खेती कर चुके हैं। सबलगढ़ टीआई नरेंद्र शर्मा ने कहा कि चारों आरोपी फरार हो गए हैं, इनके पकड़ में आने के बाद ही इन सवालों के सही जवाब मिलेंगे। टीआई शर्मा ने कहा कि इस अपराध में जो-जो शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी।

● **बृजेश साहू**

पहले तस्कर थे, फिर खेती ही शुरू कर दी

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार जिन लोगों के नाम अफीम की खेती में आए हैं, वह राजस्थान के कोटा से गांजा व अफीम की तस्करी करके क्षेत्र में बेचा करते थे। उसके बाद इन्होंने गांजा की खेती भी की, लेकिन गांजे से ज्यादा कमाई अफीम की खेती में दिखी, इसलिए रतलाम-मंदसौर क्षेत्र से अफीम बीजों की जुगाड़ की और फिर ऐसे बीहड़ों को चुना जहां कोई आता-जाता नहीं, इसलिए यहां खेती शुरू कर दी। बीहड़ के जिस इलाके में अफीम की खेती हो रही थी वह इतना दुर्गम व दूरस्थ है कि वहां पुलिस टीम को करीब डेढ़ किमी पैदल चलना पड़ा। ट्रैक्टर-ट्रॉली भी बमुश्किल अंदर पहुंच पाई। मजदूरों को बुलाकर पुलिसकर्मियों ने एक किमी तक अफीम के पौधों को ढोया और फिर ट्रॉलियों में भरा।

आदिवासी शादी में शराबबंदी

झाबुआ-आलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल जिलों में कई दशकों से चली आ रही कुप्रथाओं के खिलाफ अब समाज ही खड़ा होने लगा है। अब समाजजन ही आगे आकर शादी में शराब परोसने की बुरी प्रथा को बंद करवा रहे हैं। झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के 12 गांवों में यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी आदिवासी परिवार अपने यहां होने वाली शादी में शराब और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा। ऐसा करने वालों पर 50 हजार रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आदिवासी शादियों में भोज के साथ शराब भी अनिवार्य रूप से परोसी जाती है।

मालवा-निमाड़ के कुछ जिलों के साथ मप्र की सीमा से सटे गुजरात के इलाकों में यह कुप्रथा प्रचलित है। मेहनत-मजदूरी करने वाला आदिवासी समुदाय शराब से आवभगत करने के लिए या तो कर्ज लेता है या फिर चांदी के आभूषण और जमीन आदि गिरवी रखता है। कर्ज चुकाने के लिए पूरा परिवार कई वर्षों तक मजदूरी करता रहता है। बीते सालों में कई संगठनों ने आदिवासी समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने के लिए प्रयास किए लेकिन सफलता कम मिली। समाज के कुछ जागरूक युवा जिले के अन्य क्षेत्र के आदिवासियों को भी इसके लिए एकजुट कर रहे हैं।

आदिवासी बहुल क्षेत्र पेटलावद के 12 गांवों में बीते दिनों सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने के लिए रखी गई ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित कर शादी में डीजे, शराब आदि पर पाबंदी लगा दी गई है। कोदली गांव के तड़वी (ग्राम प्रधान) काना मेड़ा ने बताया कि शादी समारोह, अन्य कार्यक्रमों में ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) बजाने के दौरान हालात बिगड़ते हुए देखे गए हैं। इससे सबक लेते हुए ग्रामसभा आयोजित कर सभी से विचार-विमर्श कर पाबंदी लगाने की सहमति बन गई। मोईवागेली के तड़वी सकरिया निनामा ने बताया कि यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि गांव में कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हैं और गलियों में घूमते रहते हैं। इसकी वजह से जहां आर्थिक नुकसान होता है, वहीं आपसी भाईचारे में भी दरार आती है।

कुरीतियों को दूर करने के लिए पिछले दिनों पेटलावद की कृषि उपज मंडी में ग्राम प्रमुखों (तड़वी-पटेल) की बैठक जनजाति विकास मंच ने रखी थी। सभी ने अपनी तरफ से इन कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए विचार रखे। इसके बाद गांवों में ग्रामसभा का आयोजन कर इन कुरीतियों पर रोक लगाने की पैरवी सभी ने की थी और अब इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। पेटलावद में गत दिनों विकासखंड स्तरीय तड़वी-पटेल महासम्मेलन हुआ। इसमें तहसील के 215 गांवों की 78 पंचायतों के सैकड़ों तड़वी-पटेल, गांव के वरिष्ठ नागरिक शाामिल हुए। जनजाति विकास मंच के पदाधिकारी राजेश डावर ने कहा कि सभी पंचायतें जल्द निर्णय लें कि शादी-विवाह, जन्मदिन, अन्य कार्यक्रमों में आतिशबाजी व ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे और बाल विवाह, दहेज, शराब, मतांतरण आदि कुरीतियों पर भी रोक लगाई जाए।

प्रदेश के ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाकों में कच्ची शराब (लाहन) बनाने और बेचने का गोरखधंधा चल रहा है। शराब को ज्यादा नशीला बनाने के लिए उसमें यूरिया, धूतरा, बेसरमबेल की पत्ती और **ऑक्सीटॉसिन** जैसे घातक पदार्थ तक मिलाए जा रहे हैं। इनकी मात्रा ज्यादा होने से शराब जहरीली बनकर लोगों की जान ले सकती है। उज्जैन और मुरैना में जहरीली शराब के सेवन से मौतों के बाद आदिवासी समाज जागृत हो रहा है। आदिवासी कच्ची शराब में मुख्य रूप से महुआ का उपयोग होता है। यह एक तरह का जंगली फल है जो नौरादेही अभयारण्य से लगे गावों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। महुआ को गुड़ में मिलाकर पहले उसे सड़ने के लिए रखा जाता है। इसके बाद खाली बर्तन या पीका में इसे भट्‌टी पर पकने के लिए रखा जाता है। एक नली के जरिए भाप को बॉटल उतारा जाता है। भाप ठंडी होने पर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। यही कच्ची शराब है। जिसे लाहन भी कहते हैं। यहां तक शराब जहरीली नहीं होती। जब लगता है कि शराब में नशा कम है तो फिर शुरू होता है खतरे का खेल। इसमें यूरिया, ऑक्सीटॉसिन, बेसरमबेल का उपयोग किया जाता है। इन पदार्थों को मिलाने का कोई मापदंड नहीं रहता। जिससे शराब जहरीली होने का खतरा बना रहता है।

● **रजनीकांत पारे**

अब कोई नहीं पीता शराब

आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार की तमाम योजनाएं संचालित हैं जिसका उन्हें फायदा भी मिल रहा है, परंतु कुछ ऐसे गांव भी हैं जो स्वयं स्वावलंबी बनना चाहते हैं इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर शहपुरा जनपद के अंतर्गत आने वाली आदिवासी ग्राम पंचायत देवरी नवीन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां के आदिवासी महिला-पुरुषों द्वारा ऐसा काम करके दिखाया गया, जिसकी प्रशंसा प्रदेश के मुखिया तक कर चुके हैं। इस पंचायत में सालों पहले तक घर-घर में शराब बनती थी और बड़े-बूढ़ों से लेकर सभी इसका सेवन करते थे। शराब की वजह से घर-गांव में रोजाना झगड़े होने लगे जिसे देखकर कुछ महिला और पुरुषों ने तय किया कि गांव में शराब को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। गांव में न कभी शराब बनेगी और न कोई सेवन करेगा। ग्राम पंचायत देवरी नवीन पर यदि किसी के शराब पीने की शिकायत मिलती है तो उस पर 10 हजार रुपए जुर्माना और गाली-गलौच करने पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाता है। पंचायत में इस तरह का फॉर्मूला लागू होने पर घरों के साथ आपसी विवाद कभी नहीं होते हैं। गांव के पूर्व सरपंच रामकुमार सैय्याम बताते हैं कि ग्राम पंचायत देवरी नवीन के साथ तिन्हेटा और बाड़ीबारा गांव में शराब पीने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने का नियम है। यह सब वहां की महिलाओं के संकल्प से हुआ है। महिलाएं आगे आकर खुद शराब पीने वाले व्यक्ति का नाम बताती हैं।

उम्रदराज हाइड्रल पावर प्लांट बीमार

प्रदेश के जल विद्युत गृह उम्रदराज हो चुके हैं। औसत उम्र पार करने के बाद भी इनकी देखभाल नहीं हुई। नतीजा एक के बाद एक पावर प्लांट दम तोड़ने लगे। तकनीकी खामियों से बिजली का उत्पादन कम हुआ, वहीं आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। अब कंपनी प्रबंधन प्लांट की उम्र के हिसाब से उनकी आंतरिक स्थिति का पता लगाने जा रही है। इसमें पावर प्लांट और कितने वक्त जिंदा रह पाएंगे ये पता लगाया जाएगा।

मप्र पावर जनरेशन कंपनी के पावर प्लांट में हाइड्रल में सबसे ज्यादा तकनीकी खराबी आ रही है। खराबी के पीछे कंपनी प्रबंधन प्लांट की उम्र अधिक होना बताया जा रहा है जबकि असलियत ये है कि प्रबंधन ने सिर्फ उत्पादन पर जोर दिया लेकिन इनका मेंटेनेंस सहीं ढंग से नहीं किया। इसमें गांधी सागर पावर प्लांट की उम्र तो 60 साल हो चुकी है वहीं पेंच सिवनी के पावर प्लांट का संचालन 34 साल से किया जा रहा है। ऐसे में गांधीसागर, पेंच, बरगी और सिरमौर के पावर प्लांट में कई बार तकनीकी खामी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है।

पावर प्लांट की उम्र कितनी बाकी है और उसमें आगे क्या खामियां आएगी, इसकी पूरी जांच मप्र पावर जनरेशन कंपनी करवाने जा रही है। इसे रिमेनिंग लाइफ एसेसमेंट कहा जाता है। कायदे से प्लांट की आधी उम्र पार करने के बाद प्रबंधन को ये टेस्ट करवा देना था ताकि खराबी को पहले ही पता लगाकर उसे सुधारा जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कंपनी बरगी, पेंच और टोंस के पावर प्लांट की जांच के लिए कंपनियों को बुला रही है। इसके लिए निविदा भी कंपनी ने जारी कर दी है।

मप्र पावर जनरेशन कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, 115 मेगावाट की गांधी सागर योजना 1960 में बनी है। इस परियोजना को बने करीब 61 साल हो गए हैं। उसी तरह 160 मेगावाट का पेंच पावर प्लांट 1986 में, 90 मेगावाट का बरगी पावर प्लांट 1988, 315 मेगावाट बाणसागर पावर प्लांट 1992 और 45 मेगावाट का राजघाट पावर प्लांट 1999 में बना है। टोंस और पेंच के पावर प्लांट में एक-एक मशीन से उत्पादन बंद है। इससे करीब 185 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। हाइड्रल मप्र पावर जनरेशन कंपनी के मुख्य अभियंता एससी शुक्ला के अनुसार पेंच में पिछले दिनों अर्थ फॉल्ट आया था। जिस वजह से खराबी आई। इसके अलावा गांधीसागर में सितंबर 2019 में बाढ़ की वजह से तकनीकी खराबी आई थी। अभी दो मशीनों से उत्पादन शुरू हो गया है। एक मशीन 40 मेगावाट की जल्द उत्पादन के लिए तैयार होने की उम्मीद जाहिर की गई है।

प्रदेश के ज्यादातर हाइड्रल पावर प्लांट उम्र को पार कर चुके हैं जिसमें खराबी संभव है। कंपनी के अनुसार 30 साल के लिए पावर प्लांट को डिजाइन किया गया है, अब आयोग ने 35 साल प्लांट की उम्र तय की हुई है। इनका मेंटेनेंस पहले से शुरू हो जाना था जो नहीं कराया गया है। इसलिए एकाएक सभी प्लांट में बिजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मनजीत सिंह ने कहा कि हाइड्रल पावर प्लांट उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। इसलिए उनमें तकनीकी खराबी आ रही है। प्लांट की उम्र और खराबी को पता लगाने के लिए रिनेमिंग लाइफ एसेसमेंट टेस्ट कराया जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी हो चुका है। इसमें हाइड्रल पावर प्लांट की उम्र का पता लगाकर उसमें सुधार किया जाएगा।

लॉकडाउन के नाम पर 3 महीने अप्रैल 2020 से जून 2020 तक इकाई में उत्पादन को बंद रखा गया, जिससे प्रदेश को हर महीने मिलने वाली 1320 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति नहीं हो सकी। इसके एवज में सरकार ने निजी क्षेत्र से महंगी दर पर बिजली खरीदी। इस पूरे मामले में विधानसभा में चर्चा की अनुमति होना चाहिए। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा है कि सिंगाजी ताप परियोजना की इकाई 3 और 4 की टरबाइन टूटने का हवाला दिया गया और उसके बाद उत्पादन बंद कर दिया गया। ये इकाई 6600 करोड़ रुपए में बनाई गई थी। पटवारी का आरोप है कि ये उत्पादन ठप करने की साजिश थी। कांग्रेस विधायक ने निजी क्षेत्र से बिजली खरीदी में 100 से 200 करोड़ रुपए के लेनदेन का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि पावर प्लांट की इकाई में उत्पादन को बंद कर निजी क्षेत्र से 14 प्रति यूनिट की दर पर बिजली खरीदी गई है। इसका बोझ आम जनता की जेब पर पड़ा है।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

साजिशन सिंगाजी पावर प्लांट बंद किया गया

सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट को बंद कर निजी क्षेत्र से बिजली खरीदने का मामला तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि साजिशन उस प्लांट की दो इकाई बंद कर निजी क्षेत्र से महंगी दर पर बिजली खरीदी गई। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और नियम 52 के तहत सदन में चर्चा कराने की मांग की है। जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा है कि निजी बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सिंगाजी पावर प्लांट की इकाई बंद की गई और महंगी दर पर बिजली खरीदकर भारी भ्रष्टाचार किया गया। जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है। उनकी इस मांग का कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी और विशाल जगदीश पटेल ने समर्थन किया है। जीतू पटवारी ने ये भी आरोप लगाया कि बिजली के क्षेत्र में अधिकारियों और निजी कंपनियों की मिलीभगत के कारण बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने इस पर सरकार से जवाब मांगा है कि सिंगाजी पावर प्लांट के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है। विधानसभा में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब को कांग्रेस विधायक ने अधूरा बताया। इस बात की शिकायत भी विधानसभा अध्यक्ष से की है कि पूरे मामले में तथ्यों को छुपाया गया है।

अब मप्र बना गेहूं प्रदेश

अभी तक सोया प्रदेश के रूप में ख्यात मप्र अब गेहूं प्रदेश भी बन गया है। प्रदेश में न केवल गेहूं की बंपर पैदवार हो रही है, बल्कि समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक खरीदी भी हो रही है। इस वर्ष प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह मप्र में साकार होता दिख रहा है। यहां किसान प्रदेश सरकार की योजनाओं का सहारा लेकर अपने खेतों में सोना उगा रहा है। उधर, प्रदेश सरकार किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदकर उन्हें मालामाल कर रही है। इस बार मप्र के किसानों के खेतों में गेहूं की बंपर पैदावार होने की संभावना है। इससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। उधर, सरकार ने समर्थन मूल्य पर किसान का गेहूं खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। मप्र में इस बार सरकार कुछ जिलों में 27 मार्च को तो कुछ में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेगी। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन 1975 रुपए प्रति क्विंटल है। कृषि विभाग के अनुमान मप्र में इस बार गेहूं के बंपर उत्पादन का अनुमान है। प्रदेश में इस साल 336 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे अधिक फोकस खेती-किसानी पर है। इसलिए उन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प लिया है, जो अब मप्र में साकार होगा दिख रहा है। प्रदेश में पिछले एक दशक से लगातार गेहूं सहित अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। वहीं शिवराज सरकार की कोशिश रही है कि वह किसानों की अधिक से अधिक उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदे। विगत वर्ष गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में मप्र ने देश में सारे रिकार्ड तोड़कर 1 करोड़ 29 लाख 28 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की। वहीं गेहूं खरीदी के लिए 14.48 लाख किसानों को 27,000 करोड़ का भुगतान भी किया। इस बार भी मप्र में गेहूं की बंपर पैदावार होने की संभावना है।

देशभर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार ने अनुमान जताया है कि मौजूदा खरीद वर्ष में पिछले साल (389.93 लाख मीट्रिक टन) की अपेक्षा 9.56 फीसदी अधिक गेहूं की खरीदी होगी। इस बार भी सबसे ज्यादा गेहूं की खरीदी मप्र से होने का अनुमान है। जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब होगा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार आगामी रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान कुल 427.363 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया गया है जो रबी विपणन सीजन 2020-21 के दौरान हुई 389.93 लाख मीट्रिक टन से 9.56 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन 1,975 रुपए प्रति क्विंटल है। मप्र में गेहूं की खरीद कुछ जिलों में 27 मार्च तो कुछ में 1 अप्रैल से शुरु होगी, जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मार्च तक हो गए हैं। इस साल सबसे ज्यादा मप्र में 135 लाख मीट्रिक टन, दूसरे नंबर पर पंजाब 130 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा से 80 लाख मीट्रिक टन और उप्र में 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मप्र में गेहूं किसानों को मालामाल कर रहा है। पिछले 5 साल में किसानों का रुझान काफी हद तक गेहूं की खेती की ओर बढ़ा है। यही कारण है कि साल-दर-साल इसकी पैदावार में भी बढ़ोतरी हो रही है। विगत वर्ष गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में मप्र ने देश में तोड़े सारे रिकार्ड 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की। इससे पहले सर्वाधिक गेहूं खरीदी का रिकार्ड पंजाब के नाम था। अब रबी विपणन सीजन 2021-22 में मप्र ने सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। इस साल मप्र में करीब 336 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन संभावित है। दरअसल, मप्र में शिवराज सरकार ने किसानों के लिए जितनी योजनाएं संचालित कर रखी हैं, किसान उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इस कारण पिछले एक दशक में यहां गेहूं सहित अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। मप्र के कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं कि मप्र सरकार किसानों के साथ हमेशा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद किसान हैं। इसलिए वे खेती-किसानी की आवश्यकताओं और समस्याओं को समझते हैं। इसलिए यहां के किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनी हैं जिससे किसान लाभांवित हो रहे हैं।

● **कुमार विनोद**

देश की पैदावार का एक तिहाई गेहूं मप्र के खेतों में

गत वर्ष की तरह मप्र में इस बार गेहूं के बंपर उत्पादन का अनुमान है। प्रदेश में इस साल 336 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान है जो देश के उत्पादन का एक तिहाई (करीब 31.58 फीसदी) है। कृषि विभाग का अनुमान है कि स्थितियां सामान्य रहीं तो पिछले साल की अपेक्षा अधिक उत्पादन होगा। कृषि वैज्ञानिक सतीश शर्मा के मुताबिक पिछले मानसून सीजन में प्रदेश में लगातार बारिश के कारण जमीन देर तक गीली रही और सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मिला। इससे उत्पादकता भी बढ़ी। प्रदेश में गेहूं पैदावार का जो अनुमान है, उसके हिसाब से देश में होने वाले उत्पादन में मप्र का योगदान 31.58 प्रतिशत रहेगा। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल गेहूं का उत्पादन और अधिक होता, लेकिन इस बार गेहूं और चने की फसल जलवायु के विपरीत प्रभाव (फोर्स मेच्युरिटी) का शिकार हो गई है। इस वजह से न सिर्फ गेहूं और चने का दाना कमजोर है, बल्कि उत्पादन पर भी असर पड़ा है। इसे बच्चे के जन्म के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे 9 महीने के पहले जन्म लेने वाला बच्चा प्री-मेच्योर और थोड़ा कमजोर माना जाता है, बिल्कुल वैसे ही फसल चक्र पूरा होने के पहले ही फसल पकने की वजह से दाना कमजोर हो गया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि उत्पादन 10 फीसदी कम होगा, जबकि किसान कह रहे हैं इस बार 25 फीसदी उत्पादन कम होने की संभावना है। कृषि विज्ञानियों का मत है कि अचानक से तीव्र गर्मी पड़ने के कारण गेहूं का दाना पकने की जगह सूख रहा है, क्योंकि गेहूं की फसल को ठंडक चाहिए होती है।

बढ़ते वन्यजीव, घटते जंगल

मप्र में मानव और वन्यप्राणियों के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण सीधी के संजय डुबरी पार्क के पास हैंकी गांव में पिछले माह हुई वो घटना है, जिसमें उत्पात पर उतारू 7 हाथियों के हिंसक झुंड ने दादा और उसके दो पोतों को कुचल डाला। घटना के बाद आक्रोशित लोगों की भीड़ ने रात में ही हाथियों को खदेड़े जाने की मांग को लेकर सड़क पर जाम कर दिया। यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी अनूपपुर के मझौली गांव में खेत में काम करते हुए तीन मजदूरों को हाथी रौंद चुके हैं और सुई डांड गांव में खेत में सो रहे किसान को सूंड से उठाकर चट्टान पर फेंक चुके हैं। अभी तक शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की जान यह हाथियों के हिंसक झुंड ले चुके हैं और पिछले 3 साल से वे फसलें तबाह कर रहे हैं, घरों को रौंद रहे हैं।

समस्या ये है कि मप्र सरकार के पास छत्तीसगढ़, झारखंड से आए इन हिंसक हाथियों को वापस भेजने की कोई योजना नहीं है। वन विभाग की बेबसी यह है कि हाथियों के लिए उसके पास कोई फंड नहीं है। एलिफेंट प्रोजेक्ट फाइलों में अटका है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इन हाथियों को यहां रहते लंबा अरसा हो चुका है, इसलिए इनकी वापसी बेहद मुश्किल है। इन हालातों में संकट से जूझ रहे लोगों और हाथियों के बीच संघर्ष छिड़ने का खतरा पैदा हो गया है।

बता दें कि मप्र में वन्यजीवों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उन्हें यहां की जैव विविधता रास आ रही है। यह बात हमें खुश कर सकती है, लेकिन विरोधाभास यह है कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई के चलते उनके रहने की जगह कम होती जा रही है। कहीं अलग-अलग परियोजनाओं के काम की वजह से, तो कहीं इमारतों की शक्ल में सीमेंट का जंगल खड़ा करने के स्वार्थ में ये जंगल काटे जा रहे हैं। नतीजा बाघों के बीच टेरेटरी को लेकर संघर्ष, तेंदुओं, हाथियों के रहवासी इलाकों मे घुसने और हिंसक होने के रूप में सामने आ रहा है। जब उनके सामने भूख होगी और सामने कोई विकल्प नहीं होगा, तो ये वन्यप्राणी रहवासी इलाकों में ही घुसेंगे और कहां जाएंगे।

कहने को देश में बाघ के बाद सर्वाधिक तेंदुए मप्र में हैं, राज्य में इनकी संख्या 3421 है, लेकिन तेंदुओं की सालभर में 48 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इसी प्रकार करीब 3 दर्जन बाघ मारे जा चुके हैं। यह मौतें राज्य में बढ़ते वन्यजीवों के शिकार और मानव-तेंदुए के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण हो रही हैं। आजकल शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है, जब मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की खबर सुनने को नहीं मिलती। कहीं कोई वन्यप्राणी हिंसक होकर बस्ती में घुस जाता है, तो कहीं लोग ऐसे जानवर को मार देते हैं। यह संघर्ष हालिया वर्षों में काफी बढ़ गया है।

विभाग के पास कोई ठोस योजना नहीं

3 साल से छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगली हाथियों ने मप्र में डेरा डाल रखा है। 30 हाथियों का झुंड अब 54 से ज्यादा का हो चुका है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को जंगली हाथियों ने कॉरिडोर बना लिया है। इन हाथियों को हटाने के लिए प्रोजेक्ट ऐलिफेंट फाइलों में अटका है, प्रोजेक्ट को अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए इको डेवलपमेंट कमेटी बनाकर लोगों को वन्यजीवों के हमले से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतने के बारे में समझाया जा सकता है, लेकिन अधिकांश कमेटियां कागजों पर चल रही हैं या फंड और संसाधनों की कमी से जूझ रही हैं।

जहां तक हाथियों का सवाल है, तो शहडोल जिले के ब्यौहारी ब्लॉक को ही लें। यहां के दर्जनभर से ज्यादा गांवों में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। यह इलाका जंगल और नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। हालत यह है कि 30 से ज्यादा हाथियों का झुंड कहीं फसलें, उजाड़ देता है, तो कहीं घरों में तोड़फोड़ करता है। इन दर्जनभर गांवों के लोग हाथियों के तांडव के डर से रात को चैन की नींद नहीं सो सकते। कोई खेत की रखवाली कर रहा है तो कोई आग जलाकर घरों के नजदीक हैं। इसके बाद भी हाथियों का झुंड नुकसान पहुंचा रहा है। बता दें कि झारखंड, छत्तीसगढ़ से पहुंचे 30-40 हाथियों के इस झुंड ने लंबे समय से बांधवगढ़ में डेरा डाल रखा है और वापस लौटने का नाम नहीं ले रहा।

बांधवगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाघों के बीच जंगली हाथी हैं। ये हाथी अब गांवों में भी पहुंच रहे हैं। इससे जहां एक ओर इंसानों को खतरा है, वहीं दूसरी ओर हाथियों को भी खतरा है, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, वह हाथियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके साथ संघर्ष छिड़ सकता है। ह्यूमन डाइमेंशन्स ऑफ वाइल्ड लाइफ शोध पत्रिका के मुताबिक देशभर में 32 वन्यजीवों की प्रजातियां ऐसी हैं, जो अभयारण्यों के आसपास रहने वाले लोगों के जान-माल को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं। मप्र में हम देखें तो हाथी, नीलगाय, जंगली सूअर, बाघ, तेंदुए समेत वन्यजीवों के आतंक से लोग परेशान रहते हैं। वन्यजीवों के मुद्दे पर काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक हाथियों सहित अन्य वन्यप्राणियों के मानव संघर्ष से निजात पाने के लिए मप्र सरकार और वन विभाग के पास कोई ठोस योजना है ही नहीं। मप्र में हाथियों के विचरण के लिए जगह नहीं है, इसलिए वह गांवों में घुस रहे हैं, फसलें नष्ट कर रहे हैं, लोगों को कुचल रहे हैं। ब्यौहारी और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास वाले गांवों में दर्जनों हाथियों का घुसकर आतंक मचाना, जान-माल को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं तो एकदम ताजा है, जो इंगित करती हैं कि मानव-वन्यजीवों के बीच किस कदर संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

'बुंदेलखंड की भागीरथी'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जब बुंदेलखंड की बेटी बबीता और उनके साथ की महिलाओं की तारीफ की तो पूरे देश ने उन्हें बुंदेलखंड की भागीरथी का नाम दे दिया। मप्र के छतरपुर जिले के छोटे से गांव अगरौठा में रहने वाली बबीता राजपूत और दूसरी स्थानीय महिलाएं अचानक एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। दूर-दूर से लोग उन्हें बधाइयां देने पहुंच रहे हैं। उनका जगह-जगह सम्मान हो रहा है। दरअसल जल संरक्षण के लिए काम करने वाली बबीता ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर 107 फीट की बड़ी नहर बना दी वो भी पहाड़ काटकर। आज बबीता और उनके साथियों के चेहरे पर अलग मुस्कान है। वो बात करते हुए अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही हैं। 19 साल की बबीता राजपूत खिलखिलाते हुए कहती हैं, 'प्रधानमंत्री ने उनके काम को सराहा, उनकी तारीफ की, ये हमारे लिए गर्व की बात है।' बबीता का कहना है कि जो लोग कल तक उनके इस काम का विरोध कर रहे थे वही आज बधाई देने आ रहे हैं।

बबीता बतातीं हैं, 'हमारे गांव में पानी की इतनी किल्लत है कि लड़कियां जब 5-6 साल की होती हैं, तब से वो छोटे-छोटे बर्तन उठाकर पानी भरने में लग जाती हैं। मैंने खुद भी 8 साल की उम्र से पानी भरना शुरू कर दिया था।' लेकिन आज बहुत हद तक पानी की समस्या में कमी आई है, गांव में जो हैंडपंप में उसका वाटर लेवल भी कम हुआ है। हालांकि आने वाली गर्मी में गांव को **जल संकट का सामना** करना पड़ेगा क्योंकि पूरा बुंदेलखंड इलाका ही कम बारिश की वजह से पानी के लिए जूझता है।

बबीता और उनके गांव की महिलाओं ने अपनी मेहनत के दम पर पहाड़ को पस्त कर दिया। बबीता बताती है, ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। अगरौठा गांव और आसपास के इलाके का ज्यादातर हिस्सा पठारी क्षेत्र है। यहां लगभग 100 फीट की गहराई पर पानी मिलता है। परमार्थ समाज सेवी संस्था से जुड़े मानवेंद्र बबीता राजपूत और जल सहेलियों की तारीफ मन की बात में होने से बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि ये काम काफी मुश्किल था, बुंदेलखंड पैकेज के तहत इस गांव में 40 एकड़ का एक तालाब बनाया गया था, जो जंगल क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस तालाब में पानी आने का कोई रास्ता नहीं था। जबकि जंगल क्षेत्र के एक बड़े भूभाग का पानी बछेड़ी नदी से होकर निकल जाता था। अब सवाल ये था कि जंगल का पानी किसी तरह इस तालाब तक आ जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। काफी समय तक विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि फिलहाल ऐसा किया जाए कि अभी जितना पानी पहाड़ पर आता है, उसे ही कम से कम तालाब तक लेकर आया जाए और फिर लोगों ने खुद अपने स्तर पर तालाब तक पानी लाने का जिम्मा उठाया और ये कर दिखाया।

आज बबीता और उसके साथ की जल सहेलियों की चर्चा पूरे देश और इलाके में हो रही है। लेकिन इसके पहले इन्होंने 6 महीने के पहले जो संघर्ष किया उसका अंदाजा किसी को नहीं होगा। क्योंकि दुनिया सिर्फ कामयाबी का मेहराब पहने हुए इमारत को देखती है, लेकिन जिस नींव पर इमारत टिकी होती है उसका बोझ कोई नहीं देखता है। बबीता और उनके साथ की महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया, हाड़-तोड़ मेहनत की। घरों में झगड़े किए, पतियों के ताने सुने, बच्चों को धूप में अपने साथ रखा। नाजुक कही जाने वाली कलाइयों ने गेतियां चलाईं, तसले उठाए और काट दिया पहाड़। लेकिन काम इतना आसान नहीं जितना नजर आता है, ये एक दिन की मेहनत भी नहीं है। ये लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। ये सामाजिक चेतना की मिसाल है। ये चेतना, ये चमक एक दिन में नहीं आती है। औरतों को एकजुट करने का काम परमार्थ समाज सेवी संस्था ने किया। ये संस्था जल जन जोड़ो अभियान के तरह परमार्थ संस्था बुंदेलखंड के गांवों में जल स्त्रोतों को जिंदा करने का काम कर रही है। इसमें स्थानीय महिलाओं को शामिल किया जाता है। संस्था गांव में 20 या 25 महिलाओं की एक पानी पंचायत बनाती है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होते हैं। पानी पंचायत की सदस्य महिलाएं फिर गांव की बाकी महिलाओं को पानी के लिए जागरूक करती हैं, उन्हें समझाती हैं। फिर बनाई जाती हैं जल सहेलियां। इन्हीं जल सहेलियों ने पहाड़ काटा और पास के तालाब को एक तरह से जिंदा किया है। इसके पहले गांव में छोटे-छोटे चैक डेम, स्टाप डेम बनाए गए। धीरे-धीरे करके गांव का वाटर लेवल बढ़ गया।

जल संकट के जूझ रहे बुंदेलखड के लिए इस तरह की जन जागरूकता चेतना बहुत जरूरी है और फिर बात जीवनदायिनी की हो तो ये पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो जाता है कि हम पानी को बर्बाद ही ना करें बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए पानी का इंतजाम करते हुए जाएं। क्योंकि जल नहीं तो कुछ नहीं हैं। फिलहाल हमारी तरफ से भी बबीता राजपूत और उनकी जल सहेलियों को बहुत-बहुत मुबारकबाद।

● **सिद्धार्थ पांडे**

जिला प्रशासन करेगा मदद

छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बबीता राजपूत को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारे जिले ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है। शीलेंद्र सिंह खुद जल संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। वो कहते हैं कि छतरपुर समेत पूरा बुंदेलखंड जल संकट से जूझ रहा है। अगरौठा गांव की महिलाओं ने जो काम किया वो सराहनीय है। बबीता जिले के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी रोल मॉडल हैं। आने वाले गर्मियों के सीजन में इलाके को पानी के लिए परेशान ना होना पड़े इसके लिए कलेक्टर खुद जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। वो कहते हैं कि हम सूखे पड़े जल स्त्रोतों को जिंदा करने की कोशिश में हैं। ताकि महिलाओं को पानी के लिए मीलों का सफर ना तय करना पड़े। जिला प्रशासन जल संरक्षण के लिए खास योजना पर काम कर रहा है साथ ही लोगों को भी जल संरक्षण के लिए जागरूक होना पड़ेगा।

5 राज्यों में होगी अग्निपरीक्षा

5 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 27 मार्च से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और मतगणना 2 मई को होगी। चुनावी मैदान में पार्टियां और नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस अग्निपरीक्षा में कौन सफल होगा यह तो 2 मई को ही पता चलेगा। अभी भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी, एआईएडीएमके, डीएमके सहित कई पार्टियां चुनावी मैदान में पसीना बहा रही हैं।

● राजेंद्र आगाल

नए दशक के शुरुआती वर्ष यानी 2021 की पहली छमाही में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के साथ ही टीएमसी, एआईएडीएमके और डीएमके सहित कई पार्टियों की अग्निपरीक्षा होगी। यह अग्निपरीक्षा पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने जा रही है। इन 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर 18.68 करोड़ मतदाता 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर अपना मतदान कर पार्टियों और नेताओं की किस्मत तय करेंगे। इन चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पनालीस्वामी और पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी की भी अग्निपरीक्षा होनी है।

पश्चिम बंगाल में जहां भाजपा को सत्ता में आने की चुनौती है, वहीं असम में उसे अपनी सत्ता बचानी है। दक्षिण भारत में कांग्रेस के लिए केरल में इस बार सत्ता में आना एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं लेफ्ट पार्टी को अपने एकमात्र गढ़ को बचाना भी जरूरी है। पुडुचेरी में ताजा राजनीतिक हालात को देखते हुए चुनाव बेहद जरूरी है। वहीं, जयललिता और करुणानिधि की अनुपस्थिति में इस बार तमिलनाडु में एआईएडीएमके और डीएमके आमने-सामने हैं। यानी ये चुनाव किसी एक पार्टी के वर्चस्व की जंग नहीं है, बल्कि हर राज्य की स्थिति-परिस्थिति के अनुसार पार्टियों की भी स्थिति है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उनमें से पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां का चुनाव सबसे रोचक होने वाला है। इस राज्य में साम, दाम, दंड, भेद सबकुछ आजमाया जा रहा है।

मोदी मैजिक की परीक्षा

2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद से ही लगभग हर चुनाव में भाजपा का एक ही नारा रहता है कि वह मोदी मैजिक पर सवार होकर जीत हासिल कर रही है। लेकिन इस बार 5 राज्यों के चुनाव में मोदी मैजिक की असली परीक्षा है। और इस परीक्षा का केंद्र बिंदु है पश्चिम बंगाल। बंगाल में भगवा सरकार बनाने के लिए भाजपा पिछले 5 साल से लगातार तैयारी कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने और भाजपा को मजबूत करने की रणनीति में जुटे रहे। वहीं उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह खड़े रहे। जिसका परिणाम यह हुआ है कि भाजपा ने टीएमसी के करीब 2 दर्जन विधायक तोड़ लिए हैं। लेकिन इसके बाद भी पश्चिम बंगाल में भाजपा अभी भी दूसरे पायदान पर नजर आ रही है।

दरअसल, पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने ही बनाए जाल में फंस गई है। यह सच है कि

जाति-धर्म से परे बंगाल

बंगाल पूरे भारत में अकेला ऐसा प्रांत है, जहां न धर्म ऊपर है, न जाति, न कोई समुदाय। वहां सबसे ऊपर है बंग भाषा और बंग संस्कृति। चूंकि भाषा, उत्पादन के साधन और क्षेत्र-विशेष के लोगों की आस्था से ही संस्कृति का विकास होता है, इसलिए बंग संस्कृति की जड़ें पूरे बंगाली समाज में बहुत गहरी हैं। क्योंकि यह बंगाल ही था, जहां शुरू से श्रम को महत्व मिला। बुनकर संस्कृति बंगाल की ही देन है। बंगाल में कोई काम हड़बड़ी में नहीं होता बल्कि उसको खूब मनोयोग से पूरा किया जाता है। कपड़ा बुनने में बंगाल ने इतनी प्रगति की, कि ढाका की मलमल की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। जब बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ली तो पहला काम ही यह किया कि यहां के पूरे कपड़ा उद्योग को ही नष्ट कर दिया। हजारों बुनकरों के हाथ काट दिए, ताकि उनकी लंका शायर की मिलों में बना कपड़ा भारत में बाजार पा सके। लेकिन अंग्रेजों ने यहां जितने अत्याचार किए, उतना ही बंगाल को उन्होंने आधुनिकता की तरफ ढकेला भी।

बंगाल में धार्मिक उन्माद कभी नहीं रहा, लेकिन इस बार भाजपा ने बंगाल को धार्मिक और जातीय गोलबंदी में कैद कर दिया है। यह गोलबंदी जितना बंगाल को नुकसान पहुंचाएगी, उससे कहीं अधिक भाजपा और उसके परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी। इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। क्योंकि उन्माद को फैलाकर आप चुनाव तो जीत सकते हैं किंतु राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति का मूल सिद्धांत राजनय है। अर्थात् राज चलाने की नीति। भाजपा राजनीति के क्षरण को न्यौत रही है। वह राजनीति के बुनियादी सिद्धांतों को ही खत्म कर रही है। जब ये सिद्धांत ही नहीं बचेंगे तो सिवाय उन्माद, हिंसा, खून-खराबे और असहमति के स्वर को कुचल देने के सिवाय क्या बचेगा!

दीदी की दमदारी

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वहां की रग-रग में छाई हुई हैं। भाजपा उनके राज को उखाड़ फेंकने का भरपूर दावा कर रही है, लेकिन राजनीति की माहिर खिलाड़ी दीदी भाजपा को उसी की भाषा में जवाब दे रही हैं। जब विकास की बात आती है तो वे मोदी सरकार से अपने राज्य के विकास की तुलना करने लगती हैं। जब धर्म की बात आती है तो वे भी धार्मिक हो जाती हैं। जब छल-कपट की बात आती है तो वे उसमें भी बाजी मार लेती हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने माकपा को शिकस्त देने के लिए जो तुरुप का पत्ता फेंका था, उस पत्ते को खेलने में भाजपा सबसे आगे है। यही कारण है कि केंद्र में जब से भाजपा की सरकार आई तब से लगातार उन्हें घेरने की कोशिश की जाती रही है। कभी राज्यपाल के जरिए तो कभी किसी जांच के नाम पर, तो कभी सार्वजनिक तौर पर उन्हें अपमानित करने के प्रयास किए जाते हैं। मगर ममता इन सभी विघ्न-बाधाओं को पार कर भाजपा को अच्छी तुर्की-ब-तुर्की जवाब दे रही हैं। जिस हिंसा की परम्परा को

ममता ने शुरू किया था, उसे आगे तक ले जाने में भाजपा हर तरह से अव्वल है। उन्माद फैलाने और समुदायों को विभक्त करने में ममता उसकी बराबरी नहीं कर सकतीं। यही कारण है कि धर्म और जाति-भेद से दूर पश्चिम बंगाल में अब धार्मिक नारे गूंज रहे हैं। हालांकि मंच पर चंडी पाठ कर ममता ने भाजपा को उसके ही पाले में घेर लिया है। क्या भाजपा अब मंच से रावण संहिता का पाठ कर सकती है। इसके अतिरिक्त ममता बनर्जी के साथ जो हिंसा हुई है, वह बंगाल के भद्र-लोक को भी नागवार गुजरी है। एक स्त्री पर हमला, ऐसा बंगाल में कभी सोचा नहीं जा सकता। बंगाल में स्त्री की प्रतिष्ठा इधर के बंगाल में ही नहीं उधर के बंगाल में भी है। शेख हसीना वाजेद वहां की प्रधानमंत्री हैं और उनके पहले खालिदा जिया थीं। यह है बंगाल कि सार्वभौमिकता और इसी के बूते ममता बनर्जी पूरी टक्कर दे रही हैं। बंगाल में वाकई खेला होबो!

तमिलनाडु में विरासत की लड़ाई

तमिलनाडु में मुकाबला इस बार डीएमके और एआईएडीएमके के बीच हो रहा है। पिछली बार की तरह इस बार लेफ्ट और छोटे दलों का कोई अलग मोर्चा नहीं बना है। कांग्रेस जहां विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कर रही डीएमके के साथ है वहीं भाजपा का सत्ताधारी एआईएडीएमके के साथ चुनावी समझौता हुआ है। असल में तमिलनाडु में दोनों ही गठबंधनों के बीच विरासत की लड़ाई होने जा रही है और उसमें भी सत्ताधारी गठबंधन में हिस्सेदारी जताने जेल से छूट कर वीके शशिकला भी आ धमकी हैं। मौजूदा स्थिति देखें तो भाजपा के मुकाबले कांग्रेस बेहतर स्थिति में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में जिस तरीके से एमजीआर और के कामराज की विरासत पर भाजपा ने दावा जताने की कोशिश की है, सिर्फ डीएमके की कौन कहे, जयललिता के लोग भी बेचैन हो उठे हैं। डीएमके और एआईएडीएमके की बरसों पुरानी जंग में तमिलनाडु में ये पहला विधानसभा चुनाव है, जो पुराने दिग्गजों एम करुणानिधि और जे जयललिता की गैरमौजूदगी में होने जा रहा है। चुनाव के लिहाज से देखें तो इन दोनों ही नेताओं के बगैर 2019 का आम चुनाव पहला रहा और अब ये दूसरा चुनाव होगा। 2016 में विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीने बाद जयललिता बीमार पड़ीं और फिर अस्पताल में ही उनका निधन हो गया। दो साल बाद 2018 में एम करुणानिधि भी चल बसे। और इस हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक विरासत की असली जंग अब शुरू होने जा रही है, जिसमें एक तरफ तो करुणानिधि के बेटे डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के नेतृत्व में जयललिता की राजनीतिक विरासत के दावेदार खड़े हैं। ये लड़ाई भी पारिवारिक राजनीतिक विरासत बनाम एक स्वाभाविक विरासत की लड़ाई है। सत्ताधारी एआईएडीएमके के पाले में खड़े होकर भाजपा के लिए फैमिली पॉलिटिक्स पर हमला बोलना आसान हो जा रहा है, क्योंकि पारिवारिक राजनीतिक की सबसे बड़ी मिसाल कांग्रेस भी डीएमके के साथ ही चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो तमिलनाडु दौरे में एक ही साथ दोनों को निशाना बना लिया।

कांग्रेस की नई टीम का इम्तिहान

5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। कांग्रेस प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे पार्टी के नए अध्यक्ष की राह तय करेंगे। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो राहुल गांधी के लिए अध्यक्ष पद पर वापसी की राह आसान होगी। वहीं, प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा तो पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को नेतृत्व पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस से ज्यादा राहुल गांधी की नई टीम का इम्तिहान है। राहुल की साख 5 राज्यों के प्रभारियों के प्रदर्शन पर निर्भर है, क्योंकि सभी चुनावी राज्यों के प्रभारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के भरोसेमंद माने जाते हैं। इन चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहता है, तो बिहार की तरह पार्टी से नाराज चल रहे असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस नेतृत्व और उनकी टीम के सदस्यों पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद तमिलनाडु से है। तमिलनाडु और पुडुचेरी का प्रभार दिनेश गुंडुराव के पास है। वह राहुल की नई टीम का हिस्सा हैं। केरल के वायनाड से राहुल खुद सांसद हैं। वर्ष 2019 में उनका यहां से चुनाव लड़ना फायदेमंद साबित हुआ और पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पर निकाय चुनाव में एलडीएफ को मिले समर्थन ने यूडीएफ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केरल में 1980 के बाद कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है। ऐसे में एलडीएफ सत्ता में वापसी करता है तो यह पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। तारिक अनवर लोकसभा चुनाव से पहले ही एनसीपी से कांग्रेस में आए हैं। केरल के प्रभारी के तौर पर संगठन में उनकी पहली जिम्मेदारी है। ऐसे में यूडीएफ सत्ता में वापसी नहीं करता है तो उन्हें प्रदेश प्रभारी बनाने के फैसले पर भी सवाल उठेंगे। पश्चिम बंगाल का प्रभार पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के पास है। वह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं, पर पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में जितिन प्रसाद के सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती है। असम का प्रभार भी राहुल की टीम के सदस्य जितेंद्र सिंह संभाल रहे। उनके सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती होगी।

असम में क्षेत्रीय पार्टियों का दम

असम में भाजपा और कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय पार्टियों का दम दिखेगा। भाजपा का मानना है कि राज्य में उनका कांग्रेस से नहीं बल्कि बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से कड़ा मुकाबला है। असम के कैबिनेट मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा टक्कर नहीं दे सकती हैं लेकिन अजमल हमेशा एक फैक्टर बने रहे हैं। वहीं सरमा ने यह भी कहा कि चुनावों में भाजपा और कांग्रेस-एआईयूडीएफ के बीच टक्कर होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। अजमल हमेशा से असम के एक इलाके के लिए फैक्टर रहे हैं। वह संस्कृति और सभ्यता के लिए खतरा हैं। इस बीच, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और असम के पार्टी प्रभारी बैजयंत जय पांडा ने कहा, 'अब कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ समझौता कर लिया है और यह पहचान की राजनीति की बात करती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने खुद के अस्तित्व की बात कर रही है। उन्हें कांग्रेस बचाओ में ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि असम बचाओ में। भाजपा भारतीयता के लिए खड़ी है और हम राइट साइड हैं।' गौरतलब है कि प्रदेश की 126 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए तीन चरणों में 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव का परिणाम 2 मई को घोषित किया जाएगा। राज्य में इस बार सत्तारूढ़ भाजपा के कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। असम में 33 हजार मतदान केंद्र होंगे। राज्य में पिछले चुनावों की तुलना में करीब 30 फीसदी मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। गौरतलब है कि भाजपा असम में 2016 के विधानसभा चुनाव में कुल 126 सीटों में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 60 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 122 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 26 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। एजीपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 14 पर सफलता हासिल की थी। वहीं बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ ने 74 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई और 13 सीटों पर सफलता मिली। बीओपीएफ ने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 12 पर उसके उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे। विधानसभा चुनाव में सीपीआई 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन खाता नहीं खुला।

केरल में कमजोर विपक्ष

केरल में विधानसभा चुनाव में यूं तो लड़ाई यूडीएफ और एलडीएफ गठबंधन के बीच मानी जा रही है लेकिन इनके अलावा भाजपा भी अपना पूरा जोर लगाने में जुटी है। दक्षिणी राज्य केरल में अपनी जमीन तलाश रही भगवा पार्टी इस बार राज्य के 125 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 375 करोड़ रुपए के एसएनसी लावलिन घोटाले और सोने की तस्करी में शामिल होने के आरोप झेलने के बावजूद केरल की वाम मोर्चा सरकार यदि विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ती दिखाई दे रही है तो इसकी बड़ी वजह विपक्ष का कमजोर होना है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुनाव के दौरान वरिष्ठ नेता पीसी चाको के इस्तीफे से और कमजोर हुई है। 50 वर्ष कांग्रेस में बिताने के बाद इस्तीफे में चाको ने आरोप लगाया कि पार्टी नेता विपक्षी दल रमेश चेन्निथला और पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के खेमों में बंटी है। चाको के मुताबिक कांग्रेस के सभी उम्मीदवार या तो चांडी खेमे के हैं या चेन्निथला खेमे के। ऐसे में उनके या पूर्व रक्षामंत्री एके एंटनी जैसे निष्पक्ष नेताओं के लिए पार्टी में जगह नहीं बची है। यही वजह है कि केरल के इतिहास में 1997 के बाद दूसरी बार सत्ताधारी गठबंधन चुनाव में जीत हासिल कर सकता है। पिछले वर्ष दिसंबर में हुए पंचायत चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करने वाले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व पर राज्य की जनता मुहर लगा चुकी है।

बड़ा चुनावी मुद्दा बना सीएए

देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में नागरिकता कानून (सीएए) मुद्दा अहम बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गत दिनों असम में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान राहुल ने कहा कि अवैध घुसपैठ एक मुद्दा है, लेकिन असम के लोगों में वो क्षमता है कि इस मुद्दे को वो खुद सुलझा सकते हैं। साथ ही कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होने देंगे। वहीं, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने भी कहा कि सीएए को हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने बीते साल 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन विधेयक संसद से पास करा लिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून भी बन गया। हालांकि, एक साल बाद भी इस कानून को अमलीजामा पहनाने के नियम सरकार नहीं बना पाई है। अब जबकि असम और पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो सीएए मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे को अपनी-अपनी तरह से चुनावी हथियार बनाने में जुटे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एक रैली में कहा कि कोरोना वैक्सीन जब देश में सबको मिल जाएगी तो उसके बाद नागरिकता कानून को जमीन पर उतारा जाएगा। शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों का ध्यान रखते हुए नागरिकता कानून लाई थी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी लगातार सीएए का विरोध कर रही हैं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेता तक बंगाल में सीएए के मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं और लागू करने का भरोसा भी दिला रहे हैं।

अगली पीढ़ी की अग्निपरीक्षा

5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में सियासी चेहरों की बढ़ी अहमियत के साथ ही अधिकांश सूबों में नई या अगली पीढ़ी के नेताओं का नेतृत्व कसौटी पर है। तमिलनाडु में स्टालिन, केरल में रमेश चेन्निथला हों या असम में गौरव गोगोई, हिमंत बिस्व सरमा या फिर बंगाल में भाजपा के नए पोस्टर बॉय शुभेंदु अधिकारी, अगली पीढ़ी के इन नेताओं के लिए ये चुनाव सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा है। 5 चुनावी राज्यों में ममता बनर्जी के अलावा मुख्यमंत्री पद की होड़ में शामिल सभी दलों के संभावित दावेदारों को नेतृत्व की काबिलियत साबित करनी है। असम में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल 5 साल का अपना

कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, मगर राज्य में पार्टी के राजनीतिक नफा-नुकसान का आंकलन करने के बाद भाजपा ने उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया है। भाजपा की इस रणनीति में पूर्वोत्तर में पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभरे हिमंत बिस्व सरमा के लिए नेतृत्व का रास्ता खुला रखने का संकेत देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जमीन मजबूत करने में बीते कुछ साल में कामयाब रहे हिमंत के लिए यह चुनाव असम का नेतृत्व संभालने के लिहाज से सबसे निर्णायक है।

नेतृत्व निखारने की चुनौती

असम में नागरिकता संशोधन कानून से बढ़ी भाजपा की सिरदर्दी, गठबंधन के सहारे कांग्रेस की मजबूत हुई चुनौती और मौजूदा मुख्यमंत्री सोनोवाल की दावेदारी के बीच हिमंत के सामने अपने नेतृत्व को निखारने की चुनौती है। असम में दिग्गज नेता तरुण गोगोई के निधन के बाद कांग्रेस में भी अगली पीढ़ी के नेतृत्व का पूरा मैदान खाली है। लिहाजा स्वाभाविक रूप से यहां होड़ भी ज्यादा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगाई अपने पिता तरुण गोगोई की जगह राज्य में पार्टी के सबसे बड़े छत्रप के रूप में उभरने के लिए जोर लगा रहे हैं। राज्य में जमीनी पकड़ रखने वाले सांसद प्रदीप बोरदोलोई इस दौड़ में गौरव को तगड़ी टक्कर दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा भी कांग्रेस के नेतृत्व के चेहरे की रेस से बाहर नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस में इन तीनों में आपसी प्रतिस्पर्धा तो है ही, साथ ही जनता की कसौटी पर खुद को दमदार साबित करने की दोहरी चुनौती भी है।

शुभेंदु को बचानी होगी साख

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का नेतृत्व निर्विवाद है, मगर इस चुनाव को महा-मुकाबला बना चुकी भाजपा के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना चुनौती बनी हुई है। हालांकि नंदीग्राम में ममता और शुभेंदु की सीधी जंग के बीच भाजपा ने अपनी सियासी ताकत को जिस तरह शुभेंदु अधिकारी के इर्दगिर्द केंद्रित कर दिया है उससे साफ संकेत है कि पार्टी उनमें प्रदेश का अपना नेतृत्व देख रही है। ममता की 10 साल की सत्ता और ढाई दशक से भी अधिक की जमीनी सियासी पकड़ के बीच शुभेंदु के लिए अगली पीढ़ी के नेतृत्व को बंगाल में स्थापित करना आसान चुनौती नहीं है। तमिलनाडु में जयललिता और करुणानिधि के दौर के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। स्वाभाविक रूप से द्रमुक नेता स्टालिन के पास खुद को राज्य के नए सियासी छत्रप के रूप में साबित करने का मौका है।

पलानीस्वामी की दोहरी परीक्षा

जयललिता के अवसान के बाद केंद्र और भाजपा की राजनीतिक सरपरस्ती में अपना कुनबा बिखरने से बचाने में कामयाब रही अन्नाद्रमुक की चुनौती को स्टालिन फिलहाल हल्के में नहीं ले सकते। इसी तरह, अन्नाद्रमुक में जयललिता के बाद नेतृत्व की लड़ाई में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने भले ही उपमुख्यमंत्री पनीरसेल्वम को मात दे दी हो, मगर यह चुनाव ही जनता के बीच उनके नेतृत्व की विश्वसनीयता और लोकप्रियता दोनों को तय करेगा। वहीं केरल में वामपंथी गठबंधन के पास मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का आजमाया हुआ नेतृत्व है, मगर कांग्रेस में एके एंटनी और ओमन चांडी जैसे दिग्गजों के बाद रमेश चेन्निथला के लिए जनता की कसौटी पर खुद को साबित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव के दरम्यान केरल में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के असंतोष और अंदरूनी उठापटक की बातें रमेश की इस चुनौती को कहीं ज्यादा बढ़ाती दिख रही हैं।

चुनावी राज्यों में पार्टियों की वर्तमान स्थिति

देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो गया है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में 27 मार्च, 1, 6, 10, 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। सभी राज्यों में सभी सीटों के लिए वोटों की गिनती 2 मई को होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 30 मई को पूरा हो रहा है। ऐसे में 30 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। पिछले 10 साल से ममता बनर्जी यहां मुख्यमंत्री हैं। 140 सीटों वाली केरल विधानसभा का कार्यकाल एक जून को खत्म हो रहा है। राज्य में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 91 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिनरई विजयन राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस की अगुवाई वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दूसरे नंबर पर रहा था। 126 सीटों वाली असम विधानसभा का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है। 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में 15 साल से सत्तासीन कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंका था। 2016 के चुनाव में भाजपा को 86 सीटें मिलीं और सर्वानंद सोनोवाल राज्य के मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा के लिए 2016 में हुए चुनाव में जयललिता की अगुवाई में एआईएडीएमके ने जीत हासिल की थी। 5 दिसंबर 2016 को जयललिता के निधन के बाद ओ पनीरसेल्वम राज्य के मुख्यमंत्री बने लेकिन केवल 73 दिनों तक ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रह सके। 16 दिसंबर 2017 को ई पलानीस्वामी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा का कार्यकाल 8 जून को खत्म हो रहा है। 30 सीटों वाली पुडुचेरी विधानसभा के लिए 2016 में हुए चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। यूपीए को कुल 17 सीटों पर जीत मिली जिनमें कांग्रेस को अकेले 15 सीटें हासिल हुई थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस के सीनियर नेता वी नारायणस्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने थे।

महामारी में भी बढ़ी अरबपतियों की संख्या

आमतौर पर साल का यह समय ऐसा होता है, जब हर कोई दुनिया के नए अरबपतियों के बारे में जानना चाहता है, वह यह जानना चाहता है कि इस साल पुराने धनकुबेरों की कितनी बढ़ी और फिर उसके बाद असमानता पर वही पुरानी बहस शुरू हो जाती है। हालांकि इस दौर में संपत्ति की कोई भी लिस्ट हमें परेशान कर रही है। यही वह समय होता है जब गैर-लाभकारी संगठन ऑक्सफेम की असमानता पर रिपोर्ट जारी होती है और इन्हीं दिनों विश्व आर्थिक फोरम का आयोजन होता है। हालांकि यह समय सामान्य नहीं है। दुनिया अभी भी महामारी की चपेट में है, अभी तक किसी देश की ग्रोथ में बढ़त दर्ज नहीं हुई है और विश्व अर्थव्यवस्था में इतनी विषमता की आशंका जताई जा रही है, जितनी पहले कभी नहीं की गई। इसके साथ ही 2019 की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट के संकेत हैं।

विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक, महामारी के चलते दुनियाभर में इस साल के अंत तक लगभग 15 करोड़ लोग महागरीब की श्रेणी में जुड़ जाएंगे, यह पूरी तरह तय है। इन सबके बीच हर कोई यह जानने को उत्सुक होगा कि महामारी का दुनिया के अमीरों पर क्या असर पड़ा। क्या उन्होंने भी कुछ खोया? दी हुरुन ग्लोबल रिच की जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में भारत के अरबपतियों की लिस्ट में 40 नए नाम जुड़े हैं। लिस्ट में मुकेश अंबानी देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 83 बिलियन (अरब) डॉलर है। उनकी संपत्ति में पिछले साल 24 फीसदी का इजाफा हुआ। लिस्ट के मुताबिक, हम गर्व कर सकते हैं कि जिस साल दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, उस साल दुनिया ने हर सप्ताह 8 नए अरबपति तैयार किए।

स्टेटिस्टासडॉटकाम के मुताबिक, दुनिया के प्रमुख अरबपतियों ने कोविड-19 के दौरान अपनी कुल संपत्ति में एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति जोड़ी। तो खबर यही है कि इतनी बड़ी महामारी के दौरान भी बिना किसी अपवाद के इस साल भी नए अरबपतियों का उभरना, खिलना जारी रहा। इससे उस पुरानी मान्यता को भी बल मिलता है, जिसमें कहा गया कि 'अमीर और अमीर होंगे, जबकि गरीब और गरीब बनेंगे।' अगर अतीत को वर्तमान का संकेतक माना जाए तो संपत्ति में असमानता अब आर्थिक तरक्की का आवश्यक उत्पाद है। हम जिस तरह से पूंजीवाद के खात्मे और मुक्त बाजार के मॉडल पर बहस करते आ रहे हैं, उसमें 2008 की वैश्विक मंदी इस तथ्य का एक सूचक है।

2018 में 2008 की मंदी के 10 साल पूरे हुए थे और उसी साल ऑक्सफेम ने रिपोर्ट दी थी कि तब अरबपतियों की तादाद 2008 से लगभग दोगुनी हो चुकी थी। संपत्ति के वितरण से जुड़ी इसकी एक वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, इसी बीच दुनिया के 3 अरब 80 करोड़ लोगों की संपत्ति 11 फीसदी कम हो गई। इससे भी आगे की बात यह है कि इन धनकुबेरों से टैक्स का केवल चार फीसदी जमा होता है। जिससे ट्रिकल डाउन थ्योरी को झटका लगता है, जिसमें माना जाता है कि अमीर और अमीर होगा तो उसके खर्च करने से गरीब को भी लाभ मिलेगा और गरीब, अमीर बन सकेगा। यहां तक कि ब्राजील और यूके जैसे कुछ देशों में जहां टैक्स, आय के अलावा उपभोग (वैल्यू एडेड टैक्स या वैट) पर भी, दोनों पर लिया जाता है, वहां दस फीसदी अमीरों से ज्यादा टैक्स दस फीसदी गरीब चुकाते हैं।

वास्तव में 'सुपर रिच', टैक्स अधिकारियों से लगभग 7.6 खरब डॉलर छिपा जाते हैं। ऑक्सफेम के मुताबिक, 'अर्थव्यवस्था का कोई ऐसा नियम नहीं, जो यह कहता हो कि अमीरों को तब भी और अमीर बनते रहना चाहिए, जब लोग गरीबी में दवाईयों के अभाव में मर रहे हों। कुछ लोगों के हाथों में इतनी दौलत होने का कोई मतलब नहीं, जबकि उस दौलत से मिलने वाले संसाधनों से पूरी मानवता की मदद की जा सकती हो। असमानता दरअसल एक राजनीतिक और नीतिगत चयन है।' अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड लिप्टन ने अपने ब्लॉग (हालांकि इस पर विवाद भी हुआ) में लिखा था कि विकसित और विकासशील देशों के वोटर वैश्वीकरण में 'भरोसा' खो रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया में इतनी ताकत है, जिससे इंटरनेशनल ऑर्डर (जिसे वैश्वीकरण पढ़ा जाना चाहिए), ढह सकता है। उनका यह ईमानदार आंकलन है, हालांकि हमें उनके तर्क की गहराई में जाना चाहिए। उनका इशारा उन लोगों की ओर है, जिन्हें 2008 की मंदी से पहले ही लाभ पहुंच चुका है। उन्होंने लिखा था, 'इस बार की नाराजगी टैक्सदाताओं के लिए और भारी पड़ेगी। उनके टैक्स से अगली मंदी के लिए बैंकों को मजबूत बनाया जाएगा। अगर भविष्य की मंदी केवल साधारण मजदूरों और छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाएगी तो राज्यों पर उनकी आर्थिक मदद के लिए उस तरह से दबाव नहीं होगा, जैसा 2008 में बैंकों की मदद के लिए था। इससे पब्लिक सेक्टर पर कर्ज का बोझ ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा।'

● **राजेश बोरकर**

महामारी आगे भी असमानता को बढ़ाएगी

संपत्ति में असमानता तो पहले से रही है, लेकिन महामारी जैसे भयंकर समय में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि शायद असामनता कुछ कम हो। हालांकि हुआ इसके ठीक उलट। अलायंज की अर्थशास्त्री पैट्रिशिया पेलायो रोमेरो के मुताबिक, 'यह वाकई चिंता की बात है कि अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता ने कोविड-19 के पहले से दुनिया को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। चूंकि ऐसी आशंका है कि महामारी आगे भी असमानता को बढ़ाएगी, तो यह न केवल वैश्वीकरण को झटका है, बल्कि यह खासकर निम्न आय वाले देशों में शिक्षा और स्वस्थ्य सेवाओं पर भी बुरा असर डालेगी। इसी से यह सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकारें इस संकट से उबारने में लोगों की मदद कर रही हैं और अर्थव्यवस्था ढह रही है, तो कुछ मुट्ठीभर लोग इस नियति से बचे रहकर आगे कैसे बढ़ रहे हैं? ऑक्सफेम ने पहले कहा था, 'महामारी के दौरान अंबानी ने एक घंटे में जितना पैसा कमाया, उतना कमाने में एक अकुशल मजदूर को दस हजार साल लगेंगे और अंबानी ने एक सेकंड में जितना कमाया, उतना कमाने में उसे तीन साल लगेंगे।' संपत्ति से जुड़ी एक दूसरी रिपोर्ट, 'अलायंज ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020' ने 2020 को अमीरों का साल बताया है।

मौके पर चौका

मौके को परख कर जो चाल चले वह सफल राजनेता बनता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। किस मौके पर कौन सा कदम उठाना है वे बेहतर जानते हैं। इसलिए उनके दांव कारगर होते हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का घमासान चरम पर है। भाजपा और टीएमसी के लिए मैदानी और जुबानी जंग चरम पर है। भाजपा राज्य में भगवा फहराने के लिए टीएमसी में लगातार तोड़-फोड़ कर रही है। 8 मार्च को 5 और टीएमसी विधायक भाजपा में शामिल हुए। इसके बावजूद टीएमसी का दावा है कि वह प्रदेश में सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। जबकि भाजपा 200 सीटों का टारगेट लेकर काम कर रही है। भाजपा की ओर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेश मैदान पर प्रधानमंत्री ने रैली को संबोंधित करते हुए बंगाल की परंपरा, संस्कृति की जमकर तारीफ की। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन के लिए लोगों ने ममता दीदी पर भरोसा किया था। लेकिन दीदी ने ये भरोसा तोड़ दिया। इन लोगों ने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया। यहां की बहन-बेटियों पर अत्याचार किया लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद कभी नहीं तोड़ पाए। उधर उसी दिन ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पैदल मार्च निकालकर मोदी सरकार को करारा जवाब दिया।

दरअसल, भाजपा की कोशिश है कि वह किसी भी तरह बंगाल में अपनी सरकार बनाए। इसके लिए भाजपा वह हर काम कर रही है जिससे प्रदेश का हिंदू मतदाता ममता बनर्जी से कट जाए। पश्चिम बंगाल में भाजपा हिंदुत्व के आधार पर हिंदू ध्रुवीकरण का दांव चलकर तृणमूल कांग्रेस के किले को फतह करना चाहती है। इसके लिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास, सुशासन और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उतारने की योजना बना रही है। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी नेता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हिंदी प्रेम का प्रचार करना शुरू कर दिया है। यह इसलिए कि राज्य में हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों की एक बड़ी तादाद है, और भाजपा का सबसे बड़ा फोकस इस समूह को एकमुश्त अपने साथ जोड़ना है। मोदी के हिंदुत्व के जवाब में ममता का हिंदी कार्ड कितना कामयाब होगा इसका पता विधानसभा चुनावों के नतीजों से ही चलेगा।

भाजपा के हिंदुत्व की काट के लिए बंगाली अस्मिता के साथ-साथ ममता के रणनीतिकारों ने उत्तर भारतीय हिंदी भाषियों के बीच हिंदी कार्ड का दांव भी चला है। ममता बनर्जी की कविताओं के संग्रह 'मां माटी मानुष' का हिंदी अनुवाद इन दिनों उत्तर भारतीयों के बीच बंट रहा है। ममता बनर्जी ने इस पुस्तक को हिंदी भाषियों को समर्पित करते हुए इसके प्रारंभ में लिखा है समर्पित मेरे हिंदी भाषी भाई-बहनों को। कवि की कलम के शीर्षक से लिखी किताब की भूमिका की शुरुआत करते हुए ममता लिखती हैं कि कई भाषाओं की जन्मभूमि भारतवर्ष से जितना मुझे प्रेम है उतना ही प्रेम है इस पुण्यभूमि की सारी भाषाओं से भी। इन भाषाओं में हिंदी मुझे विशेष प्रिय है। संसदीय राजनीति में मेरे कदम रखने के वर्षों पहले ही इस भाषा का मेरा परिचय और संबंध दोनों स्थापित हो चुका था। केवल किसी विशेष प्रयोजन से यह भाषा सीखने के लिए मैं बाध्य नहीं हुई बल्कि बिना किसी प्रयोजन के विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से यह भाषा मेरे काम आई, इसी कारण ये भाषा मेरी प्रिय भाषा बन गई।

इस तरह ममता बनर्जी अपने हिंदी प्रेम के जरिए पश्चिम बंगाल के हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों के बीच अपनी पैठ बना रही हैं। इस पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व सांसद विवेक गुप्ता कहते हैं कि यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है बल्कि हिंदी और हिंदी भाषियों के प्रति दीदी का लगाव भी बहुत पुराना है। गुप्ता बताते हैं कि बंगाल में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना और छठ पर्व पर राज्य में दो दिन की सरकारी छुट्टी इसका एक उदाहरण है।

इसी साल अप्रैल में संभावित पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत भाजपा के सभी शीर्ष नेता इन दिनों सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर ही दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जिस तरह राज्य की कुल 42 में 18 सीटें जीतकर भाजपा ने न सिर्फ सबको चौंकाया बल्कि ममता बनर्जी के किले को भी हिला दिया, उससे राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान पर है। उसके बाद से ही एक-एक करके कई तृणमूल नेता पाला बदलकर भाजपा की छतरी के नीचे जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के नेता और ममता बनर्जी के करीबी लोग यह दावा कर रहे हैं कि भाजपा कुछ भी कर ले, ममता दीदी अपनी सरकार की हैट्रिक लगाने जा रही हैं।

ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तो

मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने से डरी भाजपा

एक तरफ भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वह मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करने से डरी हुई है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन का कहना है कि भाजपा अगर मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी तो भगदड़ मच जाएगी। भाजपा पार्टी में असंतोष बढ़ने से डरती है। वह कहते हैं कि 'मैं अमित शाह और मोदी को चुनौती देना चाहता हूं कि वे मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करें। वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यदि आप ए को घोषित करते हैं तो बी, सी, डी नाराज हो जाएंगे। यदि आप सी कहते हैं तो ए, बी और डी नाराज हो जाएंगे। वह कहते हैं कि चुनाव बाद भाजपा में बड़ी टूट देखने को मिलेगी। क्योंकि भाजपा नेता सत्ता का ख्वाब दिखाकर दूसरी पार्टियों में सेंध लगा रहे हैं।

ममता और शुभेंदु के लिए नाक का सवाल है नंदीग्राम

कहा जाता है कि 35 साल तक वाम दलों का अजेय किला रहे पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के सहारे ही ढहाया था। पश्चिम बंगाल के उस चुनावी संग्राम में ममता के सारथी शुभेंदु अधिकारी थे। महाभारत के कृष्ण की तरह शुभेंदु अधिकारी ने वाम दलों के खिलाफ अर्जुन बनी ममता की राह में आने वाले हर रोड़े को हटाया। साथ ही उन्हें पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज भी कराया। अब पश्चिम बंगाल के सियासी रण में योद्धाओं के नाम सामने आने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक साथ 291 उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए साफ कर दिया है कि वह केवल नंदीग्राम विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। भाजपा ने भी पहले और दूसरे चरण के लिए 57 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगाई है। इस स्थिति में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नंदीग्राम की सीट पश्चिम बंगाल के सियासी रण का कुरुक्षेत्र बन गई है। नंदीग्राम ने ही ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी कुर्सी तक पहुंचाया था। इस वजह से यह उनके लिए काफी भाग्यशाली रहा है। लेकिन, नंदीग्राम के जरिए ममता को सत्ता दिलाने में शुभेंदु अधिकारी की अहम भूमिका थी। 2007 में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में अधिकारी परिवार ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस अधिग्रहण के खिलाफ बनी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी में शुभेंदु अधिकारी का किरदार अहम था।

भाजपा को दहाई संख्या से ज्यादा पार करने की खुली चुनौती देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर भाजपा विधानसभा चुनावों में दहाई का आंकड़े से ज्यादा सीटें जीत जाए यानी 99 से ज्यादा सीटें जीत ले तो वह चुनाव रणनीतिकार का अपना काम छोड़ देंगे। उनकी इस चुनौती के दो मायने हैं। पहला ये कि प्रशांत किशोर को पूरा आत्मविश्वास है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और तृणमूल कांग्रेस फिर अपनी सरकार बनाएगी भले ही उसकी सीटें पिछली बार से कुछ कम रह जाएं। साथ ही, इसके दूसरे मायने ये भी हैं कि पिछले चुनाव में महज 5 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार भले ही सरकार न बना पाए लेकिन अगर 100 से कुछ कम सीटें भी जीत लेती है, तो वह तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। इससे एक बात तो साबित है कि ममता बनर्जी के रणनीतिकार भी मानते हैं कि भाजपा की चुनौती को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

तृणमूल के ही एक अन्य नेता ने अनौपचारिक बातचीत में नाम न छापने की शर्त पर माना कि भले ही इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार राज्य में बन जाएगी, लेकिन भाजपा भी 75 से 100 के बीच सीटें अगर जीतती है तो अगली सरकार का सहजता से काम करना मुमकिन नहीं होगा। इस तृणमूल नेता के मुताबिक जो भाजपा अभी पैसे और भय के बल पर तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को तोड़कर ममता सरकार को परेशान करने और असहज करने की कोशिश लगातार कर रही है, अगर चुनाव बाद विधानसभा में उसकी तादाद सैकड़े के आसपास पहुंच गई तो अपने धन और केंद्रीय सत्ता के बल पर भाजपा ममता सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश करेगी।

इस तृणमूल नेता के मुताबिक अगर भाजपा 100 के आसपास सीटें जीत जाती है तो फिर कर्नाटक और मप्र मॉडल पर पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस बार भी पश्चिम बंगाल की जनता को यह तय करना है कि अगर उसे राज्य की अस्मिता और हित में ममता बनर्जी की मजबूत सरकार चाहिए तो वह तृणमूल कांग्रेस को पिछली बार की ही तरह सवा दो सौ सीटों से ज्यादा का बहुमत दे।

भाजपा ने 2014 के बाद से ही ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे को गरम करके हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर रखी है। यहां तक कि ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्त साबित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। अपने प्रचार तंत्र के जरिए भाजपा ने लगातार ममता के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का माहौल लगातार बनाया है। दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन का मुद्दा हो या ममता को चिढ़ाने के लिए लगातार उनके सामने जय श्रीराम का नारा अपने कार्यकर्ताओं से लगवाना और फिर उसे मीडिया में मुद्दा बनाकर ममता को घेरना, भाजपा हिंदुत्व के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है।

इसके साथ ही भाजपा ने ममता के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा भी गरम किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कथित रूप से ममता समर्थकों के हमले को भी भाजपा ने बेहद धारदार मुद्दा बनाया है। हिंदुत्व के जरिए भाजपा सबसे ज्यादा उन उत्तर भारतीयों को अपने साथ लेना चाहती है जो उसे अपनी पार्टी मानते हैं और जिन्हें अयोध्या के राम मंदिर और जय श्रीराम का नारा बेहद आत्मीय लगता है। लेकिन **महज उनसे बात नहीं बनेगी** और बंगाल में देवी की पूजा घर-घर होती है, इसलिए दुर्गा पूजा के अवसर पर मूर्ति विसर्जन की राजनीति उसे आम बंगाली को हिंदुत्व के छाते के नीचे लाने के लिए जरूरी लगती है। जबकि सुशासन और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर भाजपा चाहती है कि विकास और सुशासन के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस और ममता सरकार को घेर सके। वहीं एक सधी हुई रणनीति के तहत किश्तों में तृणमूल मंत्रियों, विधायकों एवं अन्य नेताओं को भाजपा में पाला बदल करवाकर भाजपा राज्य के भीतर-बाहर ममता खेमें में भगदड़ का माहौल भी बना रही है।

भाजपा के इन सारे तीरों की काट के लिए ममता बनर्जी ने भी अपने तरकश से बाण चलाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा के हिंदुत्व की काट के लिए उन्होंने बेहद आक्रामक तरीके से बंगाली अस्मिता का दांव चल दिया है। तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि आजादी के बाद से ही पश्चिम बंगाल की जनता ने राष्ट्रीय दलों की और उनके नेताओं की तुलना में बंगाल के नेतृत्व को ही चुना है। कांग्रेस के जमाने में विधान चंद्र राय, फिर वाम मोर्चे के ज्योति बसु और अब ममता बनर्जी इसके उदाहरण हैं। करीब 34 सालों तक पहले ज्योति बसु और फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में माकपा नेतृत्व वाली वाम मोर्चे की सरकार रही और पिछले दस साल से ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल की सरकार है। भाजपा बहुत कोशिश के बावजूद अभी तक ममता से बड़ा क्या उनके बराबर का भी कोई बंगाली नेतृत्व विकसित नहीं कर पाई है। इसलिए ममता बनर्जी ने न सिर्फ बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दे को गरम किया है बल्कि अब वह बंगाली अस्मिता से जुड़े हर मुद्दे को उठा रही हैं।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

हार से निकलेगी जीत

कांग्रेस की मुश्किलें और महाजन का कर्ज ये दोनों ही अब एक दूसरे के पर्यायवाची बनते जा रहे हैं। न महाजन का दिया कर्ज कभी खत्म होता है और न कांग्रेस की मुश्किलें खत्म हो रही हैं। कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बगावत करने वाले जी-23 नेताओं का समूह 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से पार्टी पर जुबानी हमले करने में जुट गया है।

5 प्रदेशों में चुनावी सरगर्मियां दिनों दिन तेज हो रही हैं। इस बार कमोबेश सारे दल अंदरूनी द्वंद्व और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनमें केरल, तमिलनाडु तथा बंगाल ऐसे हैं, जिनमें दोनों राष्ट्रीय शिखर पार्टियां मुख्य भूमिका में नहीं हैं। वहां क्षेत्रीय दलों ने दशकों से अपने पैर मजबूती से टिकाए हुए हैं। केंद्र में अपने बूते पहली बार बहुमत में आई भाजपा को इन प्रदेशों में अपने अंकुरण को पालना-पोसना है तो कांग्रेस को खिसकता जनाधार रोकना है। इन कोशिशों में दोनों दलों ने लोकतंत्र के इस सबसे बड़े अनुष्ठान में कुछ स्याह आहुतियां भी डाली हैं। इसी तरह क्षेत्रीय पार्टियों के नेतृत्व पहली बार कड़ी अग्निपरीक्षा से गुजरेंगे। यह चुनाव इस जनतांत्रिक अनुष्ठान का भी अलग ढंग से इम्तिहान ले रहा है। अपने कार्यों के आधार पर नहीं, बल्कि चुनाव दर चुनाव तिकड़मों के जरिए बहुमत जुटाने का हुनर हुक्मरानों ने अमल में लाना शुरू कर दिया है। इससे संसदीय निर्वाचन प्रणाली भी कई मुश्किलों का सामना करती दिखाई देती है, यानी लोकतंत्र के ये घटक अपने-अपने ढंग से एक जैसे सवालों का सामना कर रहे हैं।

कांग्रेस के लिए इन 5 राज्यों में खोने के लिए कुछ नहीं है। एक पुदुचेरी में सरकार बची थी। वह भी चली गई। इसलिए उसके नजरिए से तो सारी इबारत एकदम साफ-साफ लिखी हुई है। चुनाव दर चुनाव उसका जनाधार खिसकता जा रहा है। सीटें कम होती जा रही हैं। अपने दम पर वह किसी भी राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अकेले पुदुचेरी में उसकी सीटें 15 और वोट 30 फीसदी थे। इसके ऊपर जाने की कोई सूरत नजर नहीं आती। इसे ही पार्टी बचा ले तो बड़ी बात है। केरल में उसके 22 विधायक चुने गए थे और मतों का प्रतिशत 22 था। असम में अलबत्ता 31 फीसदी वोटों के साथ 26 सीटों पर उसे कामयाबी मिली थी। तमिलनाडु में लगभग **साढ़े छह प्रतिशत मतों** के ढेर पर वह खड़ी है। इस बार द्रमुक के आसार बेहतर हैं तो वह अवश्य कुछ हासिल कर सकती है। बंगाल में पिछली बार की तरह उसने फिर वाम दलों के साथ जाने का अदूरदर्शी फैसला लिया है। पिछली बार उसने 12 प्रतिशत मत के साथ 44 स्थानों पर जीत हासिल की थी। यह वाम दलों से बारह सीट ज्यादा थी। इस बार अधीर रंजन चौधरी के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। वे कितना जनाधार बढ़ा सकते हैं। सीटों में तो कोई बहुत बढ़ोत्री के आसार फिलहाल नहीं लगते।

जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे एक पत्र में, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग की किताब से ली गई एक कहानी का जिक्र किया था। कहानी दक्षिण भारत के एक व्यक्ति के बारे में थी जो बिहार के वर्तमान

तमिलनाडु में आपसी खेमेबाजी में फंसी कांग्रेस

तमिलनाडु में प्रदेश कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के चलते असंतोष भरा पड़ा है। कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन पर असमंजस बरकरार है। राहुल गांधी के तमिलनाडु पहुंचने पर चुनाव प्रचार अभियान ने जोर पकड़ा था। लेकिन, उनके जाते ही फिर से गुटबाजी हावी होने लगी है। तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष केएस अलागिरी को लेकर कार्यकर्ताओं समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में नाराजगी की बात सामने आई है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा प्रदेश टीम की घोषणा करते समय भी कार्ति चिदंबरम ने इसका विरोध किया था। कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने फैसले करने से पहले प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से बात नहीं की थी। वहीं पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ गलबहियां कर चुनाव लड़ने जा रही कांग्रेस केरल में उन्हीं के खिलाफ खड़ी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। पिनराई विजयन ने ट्वीट कर राहुल गांधी के बंगाल चुनाव से दूर रहने और केरल में ही ध्यान लगाने पर सवाल उठाए थे। पुदुचेरी में कांग्रेस की स्थिति जगजाहिर है। राहुल गांधी का दौरा खत्म होने के दूसरे ही दिन राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। इस स्थिति में कहा जा सकता है कि कांग्रेस की मुश्किलें अभी खत्म होती नहीं दिख रही हैं।

भागलपुर के पास कर्णसुवर्ण नामक एक शहर में आया था। उसने अपनी कमर के चारों ओर ताम्र पट्टिका लपेट रखी थी और उसके सिर पर एक मशाल लगी हुई थी। जब लोग उससे इस अजीबोगरीब पहनावे के बारे में पूछते, तो वह उन्हें बताता कि वह इतना बुद्धिमान है कि उसे डर है कि पट्टिका लपेटकर नहीं रखने पर कहीं उसका पेट न फट जाए। और उसने मशाल इसलिए लगा रखी है क्योंकि उसे अपने आसपास मौजूद अज्ञानियों पर तरस आता है, जो कि अंधकार में पड़े हैं।

नेहरू ने इंदिरा को बताया कि ह्वेन त्सांग की किताब में वर्णित अभिमानी व्यक्ति के विपरीत, उनके पास सीमित ज्ञान है और इसलिए वह **बुद्धिमान व्यक्ति बनकर उपदेश नहीं देंगे।** उन्होंने लिखा कि सही और गलत का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है बातचीत और चर्चा करना है, न कि उपदेश। तब नेहरू ने कल्पना नहीं की होगी कि उनके वंशज विश्व इतिहास की झलक में उनके पत्रों को पढ़ेंगे और इस कहानी का कोई अलग अर्थ निकालेंगे। उनके पत्र लिखने के लगभग 90 साल बाद, ऐसा लगता है मानो गांधी परिवार ने अपनी कमर में टाइटेनियम की पट्टिका लगा ली है। मशाल के बजाय, उनके पास नाइट विजन वाले चश्मे हैं, जिनके सहारे वे अंधेरे में भी देख लेते हैं जबकि कांग्रेस के बाकी सदस्य और आम लोग अंधेरे में पड़े हुए हैं। इसके अलावा, राहुल गांधी के लिए अच्छी बात ये है कि वह दक्षिण भारत से सांसद हैं, न कि उत्तर (यानि कर्णसुवर्ण) से।

कांग्रेस के बागी जी-23 नेता भले ही पार्टी के 'कमजोर पड़ने' के बारे में लगातार शोर मचा रहे हों, लेकिन गांधी परिवार अभी भी आत्मविश्वास से लबरेज है- प्रियंका गांधी तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने का वादा कर रही हैं, जबकि राहुल गांधी नागरिकता (संशोधन) कानून को असम में लागू नहीं करने की कसमें खा रहे हैं। उनकी राजनीति भी व्यवस्थित नजर आती है। मशरूम बिरयानी खाना और तमिलनाडु के ग्रामीणों के साथ जलीकट्टू देखना, केरल के कोल्लम में मछुआरों के साथ तैरना और तमिल क्लासिक कहे जाने वाले तिरुक्कुरल को पढ़ना जिसे राहुल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोलकर देखा तक नहीं होगा।

जी-23 द्वारा सोनिया गांधी को विवादित पत्र लिखे जाने के 6 महीने बाद, अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट है- गांधी परिवार ज्ञान से इतना परिपूर्ण है (ह्वेन त्सांग की किताब में वर्णित व्यक्ति की तरह) कि उसे पार्टी चलाने के बारे में दूसरों की सलाह की कोई जरूरत नहीं। वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिवार के अलावा किसी और को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा जैसा कि असंतुष्ट समूह कांग्रेस कार्यसमिति और चुनाव समिति के लिए चुनाव की मांग के जरिए हासिल करना चाहता है। लेकिन गत दिनों जम्मू में असंतुष्टों के भाषणों के सुर और लहजे से स्पष्ट लगा कि जी-23 सदस्य हार मानने को तैयार नहीं हैं।

मोटे तौर पर ऐसे तीन तत्व हैं जो किसी राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता को पार्टी विशेष से बांधे रखते हैं वैचारिक प्रतिबद्धताओं या किसी बड़े उद्देश्य या आंदोलन का हिस्सा होने की वजह से उत्पन्न परस्पर लगाव की भावना, चुनावी सफलताएं दिला सकने वाले एक लोकप्रिय और करिश्माई नेता के तहत भविष्य की संभावनाएं और संसाधनों की उपलब्धता।

वर्तमान कांग्रेस के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। जी-23 के अधिकांश सदस्य और अनेकों दूसरे भी कांग्रेस पार्टी की उस विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसे कि वे दशकों से जानते समझते आए हैं। लेकिन आज वे पार्टी नेतृत्व को पूरी तरह से भ्रमित पा रहे हैं, बात धर्मनिरपेक्षता और नरम हिंदुत्व के बीच झूलने की हो या राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भ्रामक प्रतिक्रियाएं देने की। और, ये तो बस दो मुद्दे हैं। किसी आंदोलन या उद्देश्य से जुड़ाव का मुद्दा अब आम लोगों से संबंधित नहीं है, यह अब गांधी परिवार के हितों का मामला लगता है। जहां तक करिश्माई नेतृत्व की बात है, तो ज्यादातर कांग्रेसियों को आज राहुल गांधी के चुनाव जीतने की क्षमता पर उतना ही भरोसा है जितना कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह को। और, राजनीति जारी रखने के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता के बारे में आप हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवारों से पूछें या सिर्फ गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल से बात करके देखें, जिनका कहना है कि हाल के नगरपालिका चुनावों में पार्टी उम्मीदवारों को अपने पैसे खर्च करने पड़े और वह खुद के लिए **फेसबुक लाइव** करने में असमर्थ हैं क्योंकि वह 7 हजार रुपए का कैमरा नहीं ले सकते।

सोनिया या राहुल की हैसियत इंदिरा गांधी वाली नहीं है। इंदिरा ने 1969 और 1978 में, कांग्रेस के दिग्गजों को चुनौती दी थी और पार्टी को विभाजित कर दिया था। दोनों अवसरों पर, उन्होंने मूल पार्टी को छोड़ते हुए अपने धड़े को असली कांग्रेस के रूप में स्थापित करने का काम किया था। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा और ब्रह्मानंद रेड्डी विरोधी खेमे में थे जिन्होंने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। सोनिया गांधी को पता है कि राहुल या प्रियंका के पास अपनी दादी वाला करिश्मा नहीं है कि अगर उन्हें पार्टी छोड़नी पड़े या इंदिरा गांधी की तरह उन्हें निष्कासित कर दिया जाए तो वे कांग्रेसियों के बहुमत का समर्थन हासिल कर पाएंगे। इसलिए सोनिया कांग्रेस की बागडोर नहीं छोड़ेंगी। यदि स्थिति और बिगड़ती है, तो अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए सोनिया उनके खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं हिचकेंगी।

● **इन्द्र कुमार**

चुनावी राज्यों में कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं जी-23 नेता

पश्चिम बंगाल में भी अब कांग्रेस नेता इन असंतुष्टों पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जी-23 नेता में से एक आनंद शर्मा ने हाल ही में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के साथ कांग्रेस करे गठबंधन पर सवाल खड़े किए थे। शर्मा ने इस गठबंधन को पार्टी की गांधीवादी और नेहरूवादी मूल विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया था। आनंद शर्मा ने इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा करने की बात के साथ प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की भी आलोचना की थी। इसके जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) के साथ गठबंधन के फैसले का बचाव किया और शीर्ष नेतृत्व को इसकी जानकारी होने की बात भी कही।

कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल

देश में इन दिनों कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल चर्चा में है। दरअसल, कांग्रेस असम में छत्तीसगढ़ मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी को उम्मीद है कि इस मॉडल पर चुनाव लड़ने से राज्य में पार्टी सत्ता में वापस आ जाएगी। 5 साल बाद असम में सत्ता की वापसी चाह रही कांग्रेस, वहां भी विधानसभा चुनाव में बूथ मैनेजमेंट के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी को लगता है कि जिस मॉडल के जरिए छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 साल पुरानी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंका था, वही असम में भी उसे वापस कुर्सी दिलाएगा। इस छत्तीसगढ़ी मॉडल की कमान एक तरह से खुद वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों में है, जो पार्टी ऑब्जर्वर के तौर पर आए दिन रायपुर से गुवाहाटी के लिए उड़ान भर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि अभी करीब दो हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं में इससे नई जान फूंकी जा चुकी है और उनका मनोबल चरम पर पहुंच चुका है।

साल 2018 के आखिर में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी चुनावी पंडितों का गुना-गणित बिगाड़ दिया था और भारी बहुमत से वहां रमन सिंह की सरकार को हटाकर कुर्सी पर काबिज हुई थी। पार्टी वहां पर विधानसभा की 90 सीटों में से 68 सीटें जीत गई थी और बाद में हुए उपचुनाव में दो और जगहों पर सफलता पाकर अपनी सीटों का आंकड़ा 70 तक पहुंचा चुकी है। करीब महीनेभर से बाहर से असम में आकर काम कर रहे पार्टी के एक नेता ने बताया है कि जब से छत्तीसगढ़ से आई टीम ने जमीन पर उतरकर काम करना शुरू किया है, यहां के कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ गया है।

असम में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में तब से ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, जबसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विधानसभा चुनावों के लिए असम में पार्टी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके बाद पार्टी के अंदर तेजी से एक सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। पार्टी के एक नेता ने अपना नाम नहीं जाहिर होने देने की शर्त पर कहा कि 'पिछले 15-20 दिनों में पूरा माहौल ही बदल गया है और अब कायाकल्प के बाद कांग्रेस भाजपा और उसके सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक प्रचार कर रही है। अब पार्टी को पूरा भरोसा है कि वह सत्ताधारी एनडीए को कड़ी टक्कर देगी।' 14 फरवरी को जब राहुल गांधी ने राज्य में पार्टी के चुनाव मुहिम की शुरुआत की थी तो बघेल उनके पास ही मौजूद थे। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार पूर्वोत्तर के इस राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी के उस पदाधिकारी ने कांग्रेस की रणनीति का थोड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो टीम असम में कैंप कर रही है, उसका पूरा जोर माइक्रो-लेवल बूथ मैनेजमेंट पर है, जिसने 2018 में उनके राज्य में भाजपा को हराने में कामयाबी दिलाई थी। उनके मुताबिक, 'करीब 15 स्पेशल ट्रेनरों ने 1 फरवरी से लेकर अब तक करीब 100 विधानसभा क्षेत्रों में 100 ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया है। अगले दो-तीन दिनों में हम असम की सभी 126 विधानसभा सीटों को कवर कर लेंगे।' पहले चरण के बाद पार्टी के **वरिष्ठ नेता** हर विधानसभा में जाएंगे और जमीनी हालातों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद फिर से दूसरे और तीसरे राउंड की ट्रेनिंग अलग-अलग तरह के ट्रेनर तब तक देते रहेंगे, जब तक चुनाव खत्म नहीं होते।

कांग्रेस नेता के मुताबिक 'भाजपा हर पोलिंग बूथ पर पृष्ठ प्रमुख या पन्ना प्रभारी को मतदाताओं को मैनेज करने के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। हालांकि, छत्तीसगढ़ में हमने उनका मॉडल फेल करते देखा है, क्योंकि उसमें साइक्लॉजिकल गेम प्लान पर ज्यादा जोर रहता है। हम शुद्ध रूप से विज्ञान और गणित के आधार पर काम कर रहे हैं।' जब कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के पॉलिटिकल एडवाइजर विनोद वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 'मुद्दे और नेता महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सिर्फ प्रभावी और बारीक बूथ मैनेजमेंट से ही चुनावों में पार्टी को जीत मिल सकती है।' पत्रकार से पॉलिटिकल स्ट्रैटजिस्ट बने वर्मा वहां मौजूद छत्तीसगढ़ की टीम और असम के पार्टी कार्यकर्ताओं के **बीच कोऑर्डिनेटर** का काम कर रहे हैं और चुनाव परिणाम आने तक वहीं रहेंगे।

कांग्रेस 2001 से 2016 तक लगातार 15 वर्षों तक असम की सत्ता में थी। इस बार उसने एआईयूडीएफ, सीपीआई, सीपीएम और आंचलिक गण मोर्चा के साथ महागठबंधन (महाजोत) बनाया है। यहां बाकी चार राज्यों के साथ ही मार्च-अप्रैल में चुनाव होने की संभावना है। 2016 के चुनाव में भाजपा 60 सीटें लेकर 126 सदस्यों वाली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जबकि, इसकी सहयोगियों असम गण परिषद को 13 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को 11 सीटें मिली थीं। सरकार को एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन हासिल है। वहीं कांग्रेस के पास अभी सिर्फ 19 विधायक हैं, जबकि इत्र के कारोबारी और मुस्लिम नेता बदरुद्दीन अजमल की पार्टी (एआईयूडीएफ) के 14 विधायक जीते थे।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

युवाओं को लुभाने की पूरी कोशिश

राज्य में इस बार कांग्रेस की ओर से प्रचार समिति के प्रमुख छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस रणनीतिकारों का दावा है कि उनका कैंपेन लोगों से सीधे तौर पर जुड़ रहा है और जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसका असर दिखने लगेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय अपनी टीम के साथ पिछले करीब दो महीने से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की 15 वर्ष पुरानी डॉ. रमन सिंह की सरकार को पराजित किया था। पार्टी के अहम रणनीतिकार ने कहा कि इस बार पूरी तरह सकारात्मक प्रचार की योजना बनी है और समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के लिए लंबा होमवर्क किया गया है। रणनीतिकार के अनुसार तरुण गोगोई के बाद पार्टी के पास न उस कद का न उतना सर्वमान्य नेता कोई था, अतः पार्टी ने संगठित एप्रोच से साथ मिलकर रणनीति बनाई। इसके लिए सभी नेताओं को एक साथ बसों में घुमाया गया। फिर आम लोगों के बीच अपनी बात ले जाने के लिए असम बचाओ कैंपेन चलाया गया, जिसमें युवाओं को प्रतियोगिता जीतने पर आईफोन तक दिए गए।

मराठा आरक्षण में फंसा पेंच

महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल, मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने विगत दिनों वर्चुअल सुनवाई शुरू की है। यह सुनवाई 18 मार्च तक जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान संवैधानिक बेंच ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। कई राज्यों में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे राज्य सरकारों का तर्क जानना चाह रहा है। बेंच ने कहा कि हम सहमत हैं कि मामले का असर सभी राज्यों पर पड़ेगा। उन्हें भी सुनना जरूरी है। बेंच ने 15 मार्च से मराठा आरक्षण और इससे जुड़े संवैधानिक प्रश्नों पर सुनवाई शुरू की है। सुनवाई के दौरान पूछा गया है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाया जा सकता है?

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने कहा, अलग-अलग राज्यों के मिलते-जुलते कानूनों की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामले में आर्टिकल 342 ए की व्याख्या भी शामिल है। जो सभी राज्यों को प्रभावित करेगा। इसलिए इस मामले में सभी राज्यों को सुनना चाहिए। सभी राज्यों को सुने बिना इस मामले में फैसला नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, सुनवाई में विलंब से हम पर असर होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा रखी है।

वर्चुअल सुनवाई के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह लगातार मांग की गई थी कि मामले की सुनवाई इन पर्सन हो। राज्य सरकार के वकील ने दलील दी थी कि मामले से संबंधित कागजात काफी ज्यादा हैं, ये 30-40 वाल्यूम में है, जिनको प्रिंट भी किया जाना होगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि यदि कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू होती है तो पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से दलीलें दे सकते हैं। जिसके बाद यह माना जा रहा था कि मराठा आरक्षण पर प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन मामले पर सुनवाई से पहले अदालत ने वर्चुअल सुनवाई का फैसला दिया। माना जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते केस की वजह से अदालत ने यह फैसला लिया है।

आरक्षण मामले में मुख्य हस्तक्षेपकर्ता राजेंद्र दाते पाटिल ने कहा कि यह मामला इंदिरा साहनी मामले से संबंधित है, जिस पर 11 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था। इसलिए 8 मार्च को मसले पर होने वाली सुनवाई के दौरान मराठा आरक्षण को भी 11 जजों की पीठ के समक्ष भेजने की मांग रखी गई थी। उन्होंने कहा कि यह भी मांग रखी गई थी कि मराठा एसईबीसी आरक्षण मसला गायत्री बनाम तमिलनाडु इस केस के साथ टैग करके बड़ी बेंच इस पर सुनवाई करे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है और मराठा एसईबीसी आरक्षण के चलते राज्य में भी आरक्षण का प्रतिशत 65 तक बढ़ जाएगा। इसलिए प्रारंभिक मुद्दों को सबसे पहले सुना जाना चाहिए।

देश की अदालतों में लॉकडाउन के बाद से वर्चुअल माध्यम से ही सुनवाई हो रही है। चूंकि कुछ दिनों से कोरोना का कहर कम होने के चलते वकीलों और पक्षकारों द्वारा भी कोर्ट रूम में सुनवाई की मांग की जा रही है। इस बीच देशभर की सभी अदालतों और अधिकरणों में मामलों की सुनवाई प्रत्यक्ष तरीके से बहाल करने की मांग को लेकर 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में ऑनलाइन सुनवाई शुरू करने का भी अनुरोध किया गया है। वकील एमएल शर्मा ने यह याचिका दायर की है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष मार्च से मामले की ऑनलाइन सुनवाई कर रहा है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एक दशक से मांग हो रही थी कि मराठा को आरक्षण मिले। 2018 में इसके लिए राज्य सरकार ने कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियों और शिक्षा में 16 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12 प्रतिशत और नौकरियों में 13 प्रतिशत आरक्षण फिक्स किया। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो इंदिरा साहनी केस या मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए 3 जजों की बैंच ने इस पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि इस मामले में बड़ी बैंच बनाए जाने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि देश में आरक्षण को लेकर तरह-तरह की स्थितियां हैं। जहां केंद्र की तरफ से अपनी आरक्षण नीति है, वहीं राज्यों की अपनी नीति है। इस कारण आरक्षण का मामला गड़बड़ा गया है। आज देश में भले ही आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आरक्षण को लेकर राजनीति चरम पर है।

● **बिन्दु माथुर**

क्या है इंदिरा साहनी केस, जिससे तय होता है कोटा?

1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया था। इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दी थी। इस केस में 9 जजों की बैंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों, स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया है। तब से यह कानून ही बन गया। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता है।

भाजपा में घमासान

राजस्थान भाजपा में इन दिनों गुटबाजी चरम पर है। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया गुटों में भाजपा संगठन साफ बंटा हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच शक्ति प्रदर्शन की अनोखी जंग चल रही है। दोनों नेता धार्मिक स्थलों की यात्रा की आड़ में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सतीश पूनिया पिछले कुछ दिनों से लाव-लश्कर के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 8 मार्च को अपना जन्मदिन ब्रज चौरीसी की परिक्रमा यानी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा से मनाया। इसके साथ ही भरतपुर संभाग में तमाम धार्मिक स्थलों की यात्रा पर राजे लाव लश्कर के साथ निकली। इस बीच राजे की धार्मिक सियासी यात्रा को लेकर भाजपा की अंदरूनी सियासत को गरमा ही रही है। वहीं आखिर भरतपुर संभाग को चुनने की वजह क्या है इसको लेकर भी सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। राजस्थान की सियासत में मौजूदा हालात में देखें तो भरतपुर संभाग में भाजपा संगठन सबसे कमजोर है, वहीं कांग्रेस के लिहाज से पायलट सबसे अधिक मजबूत भरतपुर संभाग में ही हैं।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की धार्मिक यात्राओं ने सियासी तूल पकड़ लिया है। धर्म के सहारे सियासत साधने के लग रहे आरोपों के बीच अब भाजपा और कांग्रेस में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा को बेहद निजी यात्रा करार दिया, तो वहीं साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे खुद इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दूसरी ओर सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने वसुंधरा की धार्मिक यात्रा पर यह कहते हुए निशाना साधा है कि धार्मिक यात्राएं तो मोक्ष के लिए निकाली जाती हैं, इसके लिए उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण भी दे डाला और कहा उन्होंने भी अपने गुजरने से 2 महीने पहले सन् 1984 में राजस्थान के माउंट आबू में एक गुप्त रुद्राभिषेक किया था।

राजस्थान में दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया तीसरी बार फिर से अपना सियासी धरातल तलाशने में जुटी हैं और हर बार की तरह इस बार भी वसुंधरा राजे देव दर्शन यात्रा करने जा रही हैं। जिसकी शुरुआत उन्होंने विभिन्न मंदिरों में देव दर्शन से कर दी है। गोविंद देवजी मंदिर से इसकी शुरुआत भी हो गई है। वसुंधरा राजे ब्रज चौरासी क्षेत्र से देव दर्शन कर बड़ी यात्रा निकाल रही हैं। गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र में वसुंधरा राजे के पूर्व मुख्यमंत्री काल में काफी विकास हुआ था। ऐसे में वसुंधरा को उम्मीद है कि वहां की धार्मिक यात्रा से उन्हें जो अपार जन समर्थन मिलेगा, उससे जनाधार भी पार्टी आलाकमान और वरिष्ठ नेताओं को दिख जाएगा। वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ का कहना है कि देव दर्शन हमारी संस्कृति है, हम सब लोग देवताओं के दर्शन करते हैं। ये यात्रा वसुंधरा राजे का निजी कार्यक्रम है और किसी भी व्यक्ति को अपना निजी कार्यक्रम करने का पूरा हक है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले में चुटकी लेते हुए कहा 'यह भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन अब चाहे वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा करें या जेपी नड्डा आएं, कुछ नहीं होने वाला।' भाजपा राजस्थान में आपसी खींचतान के चलते ही सतीश पूनिया को भी भाजपा आलाकमान ने तलब कर दिया है। राजस्थान में फिर से कांग्रेस की ही सरकार आएगी। प्रदेश के काबीना मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने भी वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा को लेकर कहा कि मुझे नहीं पता वसुंधरा राजे किस प्रयोजन से यह यात्रा कर रही हैं। वैसे धार्मिक यात्राएं आध्यात्मिक लाभ और मोक्ष के लिए होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक यात्राएं तो गुप्त रखी जाती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राजस्थान में ही माउंट आबू में सन् 1984 में उनके गुजरने से 2 महीने पहले गुप्त रूप से रुद्राभिषेक किया था। बहुत कम लोगों को ही इसकी जानकारी होगी। वहीं वसुंधरा की देव दर्शन यात्रा को लेकर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा, यह पहली बार है कि वसुंधरा चुनाव से पहले ही सक्रिय हो गई हैं। इससे पहले के 2 चुनाव में वह हार के बाद दिखती नहीं थीं। भाजपा हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से इनकार किया है। उसके बाद अब वह अपनी साख बचाने यात्रा पर निकल रही हैं।

करीब 3 माह का ब्रेक लेने के बाद वसुंधरा राजे वापस राजस्थान लौट आई हैं और 'तरोताजा' होकर राज्य की सक्रिय राजनीति में वापसी के लिए तैयार नजर आ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान की सियासत में उनकी कम भूमिका और राज्य भाजपा प्रमुख सतीश पूनिया के साथ उनकी अनबन चर्चा का विषय रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गत दिनों सड़क मार्ग से दिल्ली से जयपुर लौटीं, यह यात्रा उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन गई क्योंकि समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनके समर्थन में नारे लगाए।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

विधानसभा चुनाव पर नजर

राजस्थान लौटने से पहले वसुंधरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। हालांकि वसुंधरा राज्य से बाहर थीं लेकिन समर्थक खुले तौर पर राजस्थान भाजपा में उनके लिए अधिक सक्रिय भूमिका की मांग कर रहे थे। उनके किसी भी 'वफादार' को संगठन में भूमिका नहीं दी गई है। यह 'अनबन' सार्वजनिक भी हो गई है। पिछले सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री के वफादार माने जाने वाले 20 विधायकों ने राज्य भाजपा प्रमुख सतीश पूनिया को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उन्हें विधानसभा में मुद्दे उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस लेटर के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के वफादारों की बैठक दो सप्ताह पहले कोटा में हुई। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और प्रहलाद गुंजाल ने राज्य में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में वसुंधरा को मुख्यमंत्री प्रत्याशी के रूप में पेश करने की मांग की।

प्रियंका गांधी के हाथों में पतवार

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उप्र की सियासी गंगा में कांग्रेस की तीन दशक से जर्जर हो चुकी नाव की पतवार संभालकर नाव को मझधार में उतार दिया है। उन्हें अगले 10-11 महीनों में पार्टी की इस नाव को उस मुकाम तक पहुंचाना है, जहां से देश के सबसे बड़े और सबसे अहम सियासी राज्य की सत्ता का सिंहासन है। चुनौती बड़ी है और यह चुनौती कांग्रेस से ज्यादा खुद प्रियंका के लिए है, क्योंकि इस सियासी अग्निपरीक्षा से ही कांग्रेस महासचिव के लिए सियासत के किले का वह बंद दरवाजा खुलेगा, जो उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा सकता है, जो कभी उनकी दादी ने कांग्रेस के भीतर और बाहर संघर्ष करके अपने लिए बनाया था। जहां तक प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस का सवाल है तो 1989 से अब तक कांग्रेस हर विधानसभा चुनाव में इतना हारी है कि अब हारने के बाद उसके नेताओं के पास रोने के आंसू तक नहीं बचे हैं, इसलिए अगर 2022 भी हार गई तो पार्टी के थक चुके और छके नेताओं की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन प्रियंका गांधी के सियासी सफर पर जरूर ग्रहण लग जाएगा। हालांकि यह कहा जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रियंका के करिश्मे का इम्तिहान हो चुका है क्योंकि कांग्रेस ने बड़ी उम्मीदों और दावों के साथ उनको मैदान में उतारा था। लेकिन 2019 का मुकाबला प्रियंका का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच था, जिसमें मोदी ने बाजी मारी और राहुल विफल रहे।

प्रियंका उस चुनाव में महज राहुल की सहायक थीं और जब नायक असफल होता है तो पूरी टीम असफल होती है। लेकिन इस बार 2022 में उप्र में राहुल के नहीं प्रियंका के हाथों में कमान है और मुकाबला उनके, अखिलेश, मायवाती और योगी आदित्यनाथ के बीच होगा। अभी तक योगी आदित्यनाथ सवा तीन सौ से ज्यादा विधायकों के प्रचंड बहुमत के साथ उस भाजपा के रथ पर सवार हैं जिसके पास राज्य की सत्ता, केंद्र की सत्ता, संघ का पूरा संगठन तंत्र, जिसमें सभी अनुषांगिक संगठन शामिल हैं, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ भगवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री के हिंदुत्व का बल समेत नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता, अमित शाह जैसा रणनीतिकार और जेपी नड्डा जैसा सक्रिय पार्टी अध्यक्ष है। जबकि अखिलेश यादव उस समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हैं, जिसके पास धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की दशकों की संचित सियासी पूंजी, जातीय और सामाजिक समीकरणों की ताकत, चार बार राज्य में सरकार बनाने और चलाने का अनुभव और अपनी पिछली सरकार के समय के विकास कार्यों की थाती है। वहीं बसपा के हाथी पर सवार बहुजन आंदोलन की सियासी उपज मायावती के पास चार बार मुख्यमंत्री बनने और धमक के साथ सरकार चलाने का तजुर्बा, अपराधियों पर लगाम लगाने का रिकार्ड और दलित अस्मिता की पूंजी है।

कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती

अब उप्र कांग्रेस की वही टूटी-फूटी नाव लेकर उसकी पतवार संभालकर प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। हालांकि प्रियंका को उप्र की जिम्मेदारी 2019 से ही मिल गई थी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने आधे राज्य की चुनावी जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद पूरे राज्य की प्रभारी बनाई गईं। लेकिन उनकी सक्रियता अब बढ़ी है। हालांकि इसके पहले लोकसभा चुनावों के बाद सोनभद्र में आदिवासियों की जमीन को लेकर हुए हिंसक संघर्ष के मुद्दे पर धरना दिया और हाथरस कांड में उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई। 2020 का पूरा साल कोविड प्रतिबंधों की भेंट चढ़ गया। लेकिन इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जरूर लगातार जिलों में धरने-प्रदर्शन और गिरफ्तारियों के जरिए कांग्रेस को सक्रिय बनाए रखा। लेकिन उप्र जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में लल्लू की भी सीमाएं हैं, इसलिए अब जब विधानसभा चुनावों को एक साल ही बचा है, प्रियंका को खुद आगे आकर कमान संभालनी पड़ी है।

इन तीन ताकतवर प्रतिद्वंदियों से मुकाबले के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के पास प्रदेश कांग्रेस की वह टूटी-फूटी नाव है, जो पिछले 30 साल से रेत में फंसी हुई है और कई खेवनहार आए लेकिन मझधार पार नहीं करा सके। पिछले 30 सालों के दौरान उप्र कांग्रेस की इस नाव में कई सुराख हो गए हैं और यह नाव नदी में बहने से पहले ही डूबने लगती है। 1989 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की नाव में पहला सुराख विश्वनाथ प्रताप सिंह की बगावत से हुआ। 1991 के विधानसभा चुनावों में अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव की सरकार को समर्थन देकर बचाने से दूसरा सुराख हुआ। 1993 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की नैया में भाजपा की राम लहर और सपा-बसपा के गठबंधन से दो सुराख हुए। फिर 1996 के विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर हुए पार्टी के विभाजन से जूझती कांग्रेस ने बसपा के सामने समर्पण गठबंधन करके अपनी नाव के पटरे ही तोड़ दिए। तब राज्य की तत्कालीन 425 विधानसभा सीटों में से 300 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे और यहां उसके कार्यकर्ताओं को या तो घर बैठना पड़ा या फिर सपा, बसपा और भाजपा में जाकर अपनी राजनीतिक पिपासा शांत करनी पड़ी। यही हाल उसके समर्थक जनाधार वर्ग का भी हुआ। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपने प्रदेश नेताओं के झगड़ों में इस कदर उलझी कि उसकी नाव में अनगिनत सुराख हो गए। 2012 का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी की कमान में कांग्रेस ने बहुत जुझारू तरीके से लड़ा, लेकिन जिस तरह सिकंदर के सामने पोरस को अपने हाथियों की भगदड़ के कारण हारना पड़ा था, कुछ उसी तरह कांग्रेस के दिग्गजों ने ऐसी भगदड़ मचाई कि राहुल गांधी की तमाम आक्रामकता और मेहनत के बावजूद कांग्रेस की नाव फिर मझधार में डूब गई। 2017 में लगा कि कांग्रेस इस बार नए तरीके से चुनाव लड़ेगी और अगर जीत नहीं सकी तो भी अपनी वापसी प्रभावशाली तरीके से कर सकेगी। लेकिन तभी उरी में आतंकवादियों के ठिकानों पर सेना द्वारा की गई पहली सर्जिकल स्ट्राइक ने माहौल बदल दिया। किसानों-नौजवानों के मुद्दे हवा हो गए और सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहा कि पहली बार आतंकवादियों को सेना ने सबक सिखाया। इस राष्ट्रवादी ज्वार को पहचानने में कांग्रेस और उसके रणनीतिकार नाकामयाब रहे।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से ही सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर पंचायत चुनाव पर है। राज्य की पंचायतों में कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जमावट भी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ जदयू-भाजपा की कोशिश है कि वह अधिक से अधिक पंचायतों में अपना दबदबा बनाए। इसलिए पार्टी के रणनीतिकार रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।

अब गांव की सरकार पर नजर

बिहार के कई राजनीतिक दल अब गांव तक अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए 'गांव की सरकार' में अपना वर्चस्व बनाने के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके तहत पार्टियां पंचायत चुनाव के मैदान में उतरे अपने कार्यकर्ताओं को मदद देने की रणनीति पर काम कर रही हैं। वैसे बिहार में पंचायत चुनाव पार्टियों के आधार पर नहीं होते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि यदि भाजपा कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में किसी भी पद पर चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें भाजपा की ओर से उन्हें पूरी मदद दी जाएगी। भाजपा के एक नेता कहते हैं कि इसके लिए निचले स्तर तक के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। सभी स्तर के कार्यकर्ताओं को कहा कि वे हर स्तर के चुनाव में खड़े हो और अधिक से अधिक संख्या में सीटें जीतने के लिए पुरजोर कोशिश करें।

इधर, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने भी नई रणनीति बनाई है और इस पर जोरदार तरीके से काम भी कर रही है। आरजेडी के एक नेता की मानें तो पार्टी जल्दी ही इस बारे में औपचारिक तौर पर निर्देश भी जारी करने जा रही है कि राज्य में होने वाली पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनते समय पार्टी के कैडर आपस में तालमेल बनाकर चुनावी मैदान में उतरें। कहा गया है कि कार्यकर्ता एक-दूसरे के सामने चुनावी मैदान में न उतरें जिससे आरजेडी का कब्जा अधिक से अधिक सीटों पर हो सके। सूत्रों का कहना है कि पार्टी जिसे समर्थन देने की घोषणा करे उसके समर्थन में संबंधित पंचायत या वार्ड के नेता और कार्यकर्ता भी आएं, जिससे पार्टी की पंचायती राज संस्थाओं पर भी मजबूत पकड़ हो सके। आरजेडी नेताओं का दावा है कि पिछले पंचायत चुनाव में अधिकतर पंचायती राज संस्थाओं पर आरजेडी का कब्जा रहा है। इस विषय में हालांकि आरजेडी द्वारा अभी तक कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी कहते हैं कि आरजेडी का संगठन बिहार में सबसे मजबूत है। बिहार में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में कार्यकर्ता उतरते हैं। ऐसे में पार्टी की रणनीति होगी कि उसके कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में जीते। बिहार में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई में संभावित है।

त्रिस्तरीय बिहार पंचायत चुनाव 2021 में करीब 10 लाख उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए अपना भाग्य आजमाएंगे। गौरतलब है कि इस बार 6 पदों के लिए जिनमें मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पद शामिल हैं, के लिए चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने सभी 6 पदों के लिए 129 चुनाव चिन्ह भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने 14 चुनाव चिन्ह सुरक्षित भी रखे हैं ताकि उम्मीदवारों द्वारा चुनाव चिन्ह बदले जाने का आग्रह किए जाने के बाद बदला जा सके। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में इस बार कुल 2 लाख 59 हजार 260 पदों पर निर्वाचन होना है। इसमें मुखिया के 8,387 पद, सरपंच के 8,387 पद, वार्ड सदस्य के 1 लाख 14 हजार 667 पद, पंचायत समिति सदस्य के लिए 11 हजार 491 पद, जिला परिषद सदस्य के 1161 और पंच के 1 लाख 14 हजार 667 पदों के लिए चुनाव होना है।

बिहार पंचायत चुनाव 2021 के तहत जिला परिषद के सदस्य के पद के लिए नामांकन शुल्क 2 हजार रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं मुखिया सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य के पद के लिए उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क के रूप में 1 हजार रुपए जमा कराना होगा। जबकि पंच और वार्ड सदस्य के लिए मात्र 250 नामांकन शुल्क जमा कराना होगा। यानी पेट्रोल के वर्तमान कीमत के अनुसार पंच और वार्ड सदस्य के लिए नामांकन पत्र भरने वाले उम्मीदवार लगभग 3 लीटर पेट्रोल के दाम पर पंच या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए नामांकन शुल्क में महिला एससी-एसटी और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 50 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार पंचायत चुनाव 2021 में एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है। उसे अलग-अलग पदों पर चुनाव लड़ने के लिए अलग-अलग नामांकन पत्र भरने के लिए नामांकन शुल्क कोषागार में चालान के द्वारा या नकद जमा करा सकेंगे। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा।

● **विनोद बक्सरी**

इस बार कुल 2,59,260 पदों के लिए चुनाव चिन्ह

बिहार में अप्रैल-मई में 2 लाख 59 हजार 260 पदों पर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह का ऐलान कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 श्रेणी के पदों के लिए कुल 129 चुनाव चिन्ह घोषित किया है जिनमें सबसे अधिक 36 चुनाव चिन्ह मुखिया पद प्रत्याशियों के लिए जारी किए गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 20, ग्राम कचहरी पंच के लिए 10, सरपंच के लिए 21, पंचायत समिति सदस्य 10 और जिला परिषद सदस्य पद के 20 के अलावा 14 सुरक्षित चुनाव चिन्ह की सूची भेजी है। जिनमें कोट, जोड़ा हिरण, अलमीरा, अंगूठी, शंख, ब्रीफकेस, मुर्गा, लिफाफा, हैंगर, तुरही, कछुआ और गुब्बारा चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखा गया है।

संघर्ष विराम कितना स्थायी

पिछले साल पाकिस्तान द्वारा सीमा पर 5,000 बार से भी अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने और भारत द्वारा उनका उतना ही करारा जवाब देने की पृष्ठभूमि में नियंत्रण रेखा पर भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम समझौता व्यापक संदेश है। इसे सिर्फ वर्ष 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते की तरफ लौटने के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस संघर्ष विराम समझौते ने यह दिखाया है कि हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान न केवल चीन और पाकिस्तान द्वारा पेश की चुनौतियों का मुकाबला करने की क्षमता रखता है, बल्कि यह इन दोनों उद्दंड पड़ोसियों के साथ समझौता कर पाने में भी सक्षम है। देश के सीमाई विवादों के इतिहास के बीच यह एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले दिनों जिस तरह चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से हटने का फैसला लिया, यह अलग बात है कि इस पर कैसे अमल किया गया, उसी तरह भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स) ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम समझौते पर पूरी तरह अमल करने का ऐलान किया, और यह विगत 24-25 फरवरी की मध्य रात्रि से लागू भी हो गया।

इस सफलता का श्रेय निश्चय ही हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान में सुरक्षा मामलों पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सहायक मोइद यूसुफ के साथ पर्दे के पीछे की उनकी कूटनीति को जाता है, हालांकि यूसुफ ने डोवाल के साथ ऐसी किसी मुलाकात से इनकार किया है। अलबत्ता यह घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि पहले की तरह इस बार भी समझौते को भी भारत को सतर्कता से लेना चाहिए। पाक सत्ता प्रतिष्ठान हमेशा ही सैन्य मामले में भारत की बराबरी करने की कोशिश में गर्व का एहसास करता है, और अपने लोगों को बताता रहा है कि भारत के साथ स्थायी शांति तभी संभव है, जब भारत कश्मीर में उसका दावा स्वीकारे। ऐसे में, आश्चर्य नहीं है कि 2019 से ही, जब हमारी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाया, पाकिस्तान ने एक तरफ भारत के खिलाफ कूटनीतिक अभियान शुरू किया, जिसका उसे कोई लाभ नहीं मिला, वहीं सीमा पर संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन भी जारी रखा, जहां हमारी सेना ने इसका करारा जवाब दिया।

वर्ष 2019-20 में 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा लगातार सुर्खियों में रही, क्योंकि पाकिस्तान ने वहां से अपने प्रशिक्षित आतंकवादियों को इस पार भेजने के लिए तमाम तरीके अपनाए। पर जब भारतीय सेना की जवाबी गोलीबारी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने लगी, तब पाक सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने भारत के प्रति अपने रुख में नरमी दिखानी शुरू की। बालाकोट पर हवाई हमले के बाद से ही बाजवा का भारत के प्रति यह रुख रहा, और विगत दो फरवरी को उन्होंने कहा, यह समय सभी दिशाओं से दोस्ती का हाथ बढ़ाने का है। हैरानी की बात तो यह थी कि विगत पांच फरवरी को कश्मीर एकता दिवस के अवसर पर भी इस्लामाबाद ने पहले जैसी आक्रामकता के बजाय भारत के प्रति नर्म रुख दिखाया। इसी से साफ हो गया था कि पाकिस्तान फिलहाल भारत के प्रति आक्रामकता का परिचय नहीं देना चाहता। अलबत्ता इससे पाकिस्तान के प्रति भारत का यह रुख नहीं बदला है कि पड़ोसी देश को पहले आतंकवाद को संरक्षण देने की नीति खत्म करनी होगी।

इसके बावजूद नियंत्रण रेखा तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित मुद्दों को सुलझाए बिना ही, हालांकि पाकिस्तान के मामले में नियंत्रण रेखा को ही सीमा मान ली गई है। पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने का एक अवसर हमारी सेना को मिला है। दोनों तरफ के डीजीएमओ द्वारा सीमा पर संघर्ष विराम की घोषणा का विचार शायद पाकिस्तान का था। पाकिस्तान की ताकतवर सेना, जिसके ज्यादातर निर्देश और फैसले गोपनीय होते थे, शायद अब दोतरफा रिश्तों में सुधार से जुड़े भविष्य के फैसलों को सार्वजनिक तौर पर अपने हाथ में लेना चाहती है, क्योंकि इमरान सरकार की पाकिस्तान में कोई साख नहीं है।

अगर ऐसा है, तो यह अच्छा ही है, क्योंकि कश्मीर मुद्दा, परमाणु मुद्दा तथा पड़ोसी देशों सहित अमेरिका से संबंधित मुद्दों पर फैसले वहां की सेना ही लेती है। पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्षविराम समझौता अगर इतने लंबे समय तक टिका हुआ है, तो इसकी एक ही वजह है कि इस पर पाक सेना ने दस्तखत किया था। सिंधु जल समझौते को तो जनरल अयूब खान ने लागू करवाया था। तथ्य यह है कि पाक सेना अगर किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करती, तो उस समझौते का पालन भी नहीं करती। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल से हुए लाहौर समझौते का हश्र हमने देखा ही है। पाकिस्तान ने उसका पालन इसलिए नहीं किया, क्योंकि सेना ने दस्तखत नहीं किया था। दूसरी तरफ, हमारी सेना को नियंत्रण रेखा और जम्मू-कश्मीर में भी कार्रवाई की छूट मिलने के बावजूद राजनीतिक नियंत्रण में काम करना पड़ता है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

नियंत्रण रेखा पर संयम की परीक्षा

अगर पाकिस्तान के डीजीएमओ नियंत्रण रेखा पर अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे तथा हमेशा की तरह पाक सेना तथा आतंकियों की मिलीभगत का नमूना वहां देखने को न मिले, तो भारत की तरफ से यह आश्वासन मिलना कठिन नहीं है कि नियंत्रण रेखा पर पाक उकसावे के बावजूद इस तरफ से कमोबेश संयम का परिचय दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारी सेना जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान छोड़ देगी। बल्कि जरूरत पड़ने पर नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाने का काम भी जारी रहेगा। दोनों ओर के डीजीएमओ द्वारा मुलाकात करने के पहले के विचार पर अब अमल करने की बात कही गई है, जो व्यावहारिक है। बेशक हॉटलाइन के फायदे हैं, पर व्यक्तिगत मुलाकात से बेहतर कुछ नहीं है। बल्कि हमें नियंत्रण रेखा पर तनाव और तनातनी खत्म करने के लिए डीजीएमओ स्तर की हॉटलाइन व्यवस्था से आगे निकलते हुए दोनों तरफ के ब्रिगेड, डिविजन और कॉर्प्स कमांडर स्तर पर टेलीफोन व्यवस्था के बारे में तत्काल सोचना चाहिए।

बाइडन का सुरक्षा प्लान

हमारे दौर की गंभीरता का इसी बात से अंदाजा लग जाता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति को शपथ लेने के लगभग डेढ़ महीने में ही राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर अंतरिम निर्देश जारी करना पड़ गया। जो बाइडन के मामले में यह चौतरफा घिरी हुई एक सरकार द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और नस्लीय आधारों पर विभाजित लोगों को मतभेदों को परे रखकर आगे बढ़ने के लिए एकजुट करने की कोशिश मानी जाएगी। यह मुश्किल हो सकता है। इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो न केवल रिपब्लिकन पार्टी वालों को, बल्कि अमेरिकी लोगों के कुछ तबकों को भी नाखुश करेगा। इस दस्तावेज में ऐसा भी बहुत कुछ है जिसमें भारत की दिलचस्पी हो सकती है। और चेतावनी के ऐसे कुछ संकेत भी हैं जिन पर नई दिल्ली ध्यान देना चाहेगी।

इस बेहद असामान्य 'अंतरिम' रणनीति के पक्ष में यह तर्क अक्सर दोहराया जा चुका है कि अमेरिका को पूरी दुनिया से रफ्त-जफ्त बढ़ाकर फिर से अपनी जगह हासिल करनी है। लेकिन, इस रणनीति के बहाने अमेरिकी लोगों को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि रफ्त-जफ्त बढ़ाने की जरूरत इसलिए है कि 'विश्व का नेतृत्व करना ऐसा प्रयास नहीं है कि हम अपने बारे में ही अच्छा महसूस करें। यह अमेरिकी लोगों को शांति, सुरक्षा, और समृद्धि के साथ जीने की व्यवस्था करने का प्रयास है। यह हमारे अपने हित के लिए है, जिससे हमें कोई इनकार नहीं कर सकता।' यह उस जनता को समझाने की कोशिश है जो यह मानती है कि जिन संस्थाओं में चीन और उसके मित्र देशों का वर्चस्व है उनसे बाहर हो जाने और लड़ाइयों को खुद ही निपट जाने देने की डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अच्छी थी। बाइडन यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका को फिर से महान बनाने से उनके यहां लोगों की जेब में डॉलर आएंगे और तब एक ऐसे विदेश नीति देने का उनका वादा पूरा होगा जो मध्यवर्ग को फायदा पहुंचाएगी, न कि अमीरों और उन अनर्थकारी समूहों को जो अब तक हावी रहे हैं। अब यह नहीं कहा जा सकता कि यह ट्रंप की इस नीति से कैसे अलग है, जिसके तहत दूसरे देशों को अमेरिकी चीजें खरीदने के लिए दबाव डाला जाता था। 2020 के पहले के सर्वे बताते हैं कि 80 प्रतिशत वोटर अर्थव्यवस्था की मंदी को सबसे गंभीर मसला मानते थे, जिसमें व्यापारिक सहयोगियों को चेतावनी दी गई थी। यानी अर्थव्यवस्था सर्वोपरि है।

दूसरी बात, इस बात को सीधे कबूल किया गया है कि सुरक्षा के लिए खतरे कई तरह के हैं, और अमेरिका अकेले इनसे नहीं निपट सकता। यह शायद पूरे हॉलीवुड के चेहरे पर तमाचा है, जो अमेरिका को सुपरमैन के रूप में तमाम दादाओं से अकेले निपटते हुए दिखाता रहता है। ट्रंप के विपरीत बाइडन प्रशासन 'नाटो' और यूरोपीय संघ (ईयू) जैसे गठबंधनों को प्रमुखता देना चाहता है। नाटो में जिसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं उस ईयू ने अमेरिका के इस अनुरोध को ठुकरा दिया है कि वह चीन के साथ निवेश के व्यापक समझौते पर दस्तखत करने से पहले थोड़ा इंतजार करें। यह बात गठबंधनों को कह सकते हैं कि मुख्यत: चीन के खिलाफ मजबूत करने की कोशिशों को एक पहेली बना देती है। ईयू के व्यापारिक सहयोगी के रूप में चीन ने अमेरिका से बढ़त ले ली है। यूरोस्टैट के मुताबिक, 2020 में व्यापार 711 अरब डॉलर के बराबर पहुंच गया जबकि अमेरिकी व्यापार 673 अरब डॉलर के बराबर था। जाहिर है, आप उस देश से आमतौर पर टक्कर नहीं लेते, जो आपके जीडीपी में इजाफा करता है। लेकिन 'इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजी' इस महीने की सबसे उल्लेखनीय बात है। फ्रांस ने ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अपने युद्धपोत और पनडुब्बियां साउथ चाइना सी क्षेत्र में भेज दिए, यूके अमेरिकी विमानों से अपने 'कैरियर स्ट्राइक ग्रुप' भेजकर उस क्षेत्र में मजबूत बहुराष्ट्रीय मौजूदगी बना रहा है।

कनाडा ताइवान स्ट्रेट के रास्ते वहां अमेरिकी सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए पहले ही पहुंच चुका है। यह सब काफी प्रभावशाली तो है लेकिन समय ही बताएगा कि व्यापार को युद्ध में बदला जा सकता है या नहीं। इन 'मूल' गठबंधनों के अलावा, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 'राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम हितों' की रक्षा के लिए सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने का भी जिक्र है और इसके बाद भारत के साथ गहरी दोस्ती करने की भी बात की गई है। इस सबके साथ शर्त यह भी है- 'सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करते हुए हम अपने मूल्यों और हितों का भी ख्याल रखेंगे।' यह भारत की जगप्रसिद्ध धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ह्रास की ओर उंगली उठाने वाले लेखों की बढ़ती संख्या की ओर इशारा करने की कोशिश लगती है। सोशल मीडिया और सिविल सोसाइटी पर नए प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाए जाएंगे, भले ही भारत यह हवाला देकर इन सबको एक ढोंग बता दे कि तानाशाह चीन के साथ तो सब मेलजोल बढ़ा ही रहे हैं।

● **अक्स ब्यूरो**

प्रतिरक्षा से ज्यादा कूटनीति पर जोर

लगता है, इस आशंका की पुष्टि की जा रही है कि अमेरिका अपने रक्षा बजट को या तो कम करने जा रहा है या जस का तस रखने जा रहा है। रणनीति में 'तार्किकता', 'कूटनीति को प्राथमिकता' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो पेंटागन में बैठे लोगों में दहशत पैदा कर सकता है। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि यह महकमा आगे के लिए जो सामरिक रणनीति तैयार करेगा उसमें वह अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक, 2017 के बाद से रक्षा बजट में इजाफा होता रहा है, केवल 2021 में आधुनिकीकरण के लिए आवंटन में कमी की गई है। ट्रंप प्रशासन ने पहले चीन, फिर रूस, उत्तरी कोरिया आदि से संभावित टकराव के लिए सेना के ढांचे के वास्ते फंड की व्यवस्था की थी और ओबामा प्रशासन के आदेश को पलट दिया था। क्षमता को दो महाशक्तियों को परास्त करने या उन्हें हमले से रोकने की कसौटियों के आधार पर परिभाषित किया गया था। लेकिन अब यह स्थिति कुछ तो मंदी के कारण और कुछ इस कारण भी बदल सकती है कि चीन को अमेरिकी वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित करने से परहेज किया गया है। यह अपने आप में क्रांतिकारी बात है। आखिर, 1940 के बाद से 'अमेरिकी मूल्य' अमेरिकी वर्चस्व के बूते ही तय होते रहे हैं।

परिवार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज प्रथा है। इस प्रथा के खिलाफ 498-ए के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इस धारा को आम बोलचाल में दहेज के लिए प्रताड़ना के नाम से भी जाना जाता है।

दहेज प्रथाः सरकार दोषी या समाज

हमारे देश में बहुत आसानी से विवाह हो जाता है इसीलिए हमारी न्याय व्यवस्था तलाक देने में माहिर है। दहेज प्रथा की मूल जड़ समाज में है और इस जड़ को खत्म करने के बजाय सरकार कड़े कानून बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ मान लेती हैं। व्यक्ति उस कानून का दुरुपयोग करना भी सीख ही लेता है। जब कानून का दुरुपयोग होता है तो कानून निष्प्रभावी होकर बदलाव की मांग करता है और यही तो लोग चाहते हैं कि कानून कड़े ना हो।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दहेज उत्पीड़न कानून में बदलाव कर दिया। इसमें 498-ए के तहत महिला की शिकायत आने पर पति और ससुराल वालों की तुंरत गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। ऐसा क्यों करना पड़ा क्योंकि कई फर्जी मामले में महिलाओं ने अपने पति को फंसाकर जेल करवा दी थी। मतलब यह कि महिलाओं ने ही इस कानून को निष्क्रिय करने में अहम भूमिका निभाई थी? दहेज उत्पीड़न कानून के तहत कई फर्जी मामले दर्ज हुए जिसके चलते जो महिला सचमुच ही दहेज की शिकार थी उसके साथ कभी न्याय हुआ या नहीं हुआ यह देखने वाली बात है।

परिवार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज प्रथा है। इस प्रथा के खिलाफ 498-ए के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। इस धारा को आम बोलचाल में दहेज के लिए प्रताड़ना के नाम से भी जाना जाता है। 498-ए की धारा में पति या उसके रिश्तेदारों के ऐसे सभी बर्ताव को शामिल किया गया है जो किसी महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाए या उसे आत्महत्या करने पर मजूबर करे। दोषी पाए जाने पर इस धारा के तहत पति को अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। बस, मरने वाली महिला भले ही मर जाए आदमी 3 साल में बाहर निकल आएगा और फिर से शादी करके मजे करेगा।

धर्म और समाज उन शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह है जो वक्त के अनुसार अपने हित में नियम बनाते और तोड़ देते हैं, लेकिन उनके नियमों में कभी भी महिलाओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती रही है। उनके नियम धनवान या शक्तिशाली लोगों पर लागू नहीं होते हैं। दहेज प्रथा में समाज को नहीं बल्कि व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है। दहेज मामले में हत्या कर या तलाक लेकर वे लोग फिर से उसी समाज में विवाह भी कर लेते हैं। ऐसा कौन-सा समाज है जो हत्यारों की शादी करने की इजाजत दे देता है फिर से जुर्म करने के लिए। ऐसा कौन-सा समाज है जिसने एक प्रस्ताव लाकर दहेज प्रथा को गैर-सामाजिक घोषित कर ऐसे लोगों को समाज से बाहर कर दिया है?

आज भी हम देखते हैं कि जब हम किसी की शादी में जाते हैं तो वहां पर दहेज का सामान सजा हुआ मिलता है। लड़की की जब विदाई होती है तब बस की छत पर आपने दहेज का सामान जमाते हुए लोगों को देखा होगा। शादी में समाज ही शामिल होता है न कि कोई व्यक्ति। क्या समाज को यह दिखाई नहीं देता कि कोई अपनी बेटी को कितना दहेज दे रहा है और क्यों? समाज के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग आज दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के किसी भी वर्ग के परिवार में आपको इसका नजारा मिल ही जाएगा। खासतौर पर समृद्ध परिवारों में दहेज लेने की अधिक होड़ लगी रहती है।

हमने धनाढ्य परिवारों की शादी को भी देखा है और अब तो इन समृद्ध परिवारों की तरह की मध्यमवर्गीय परिवारों में भी दिखावे के चलते ये बढ़ गया है। लोग यह समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। भारतीय दंड संहिता भी अपराधी का सहयोग करने वाले को अपराधी मानती है। समाज को यह स्वत: संज्ञान नहीं लेना चाहिए? एक पिता बहुत लाड़-प्यार से अपनी बेटी को पढ़ाता है, फिर उसके लिए अच्छे वर की तलाश करता है। फिर जब अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो बात शुरू होती है कि किस तरह से विवाह करेंगे। फिर धीरे से बातों ही बातों में बात यह भी होने लगती है वर पक्ष की ओर से कि हमने अपनी बेटी की शादी में इतना दहेज दिया और आप देखिए दूसरों रिश्तेदारों और पड़ोसियों को कि वे कितना दे रहे हैं लेकिन हम तो इतना कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। वास्तव में यह तो अप्रत्यक्ष रूप से मांग ही होती है। कहते हैं कि साब हमें कुछ नहीं चाहिए बस बारातियों का स्वागत धूमधाम से कर देना या शादी का खर्च आप ही उठा लेना।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

समाज को उठानी होगी जिम्मेदारी

वर पक्ष में तो कई ऐसे होते हैं जो कि तब तक सीधे बने रहते हैं जब तक की फेरों का समय नहीं आ जाता। इसके बाद वे नाटक करना शुरू कर देते हैं। अगर वहां भी छुटकारा मिल जाए तो आगे ससुराल में लड़की को सताया जाता है, ताने दिए जाते हैं और कभी-कभी तो जान तक ले ली जाती है। खास बात यह कि किसी भी परिवार की यह कहानी समाज के जिम्मेदार लोग देख रहे होते हैं और वे कुछ भी नहीं करते हैं तब भी जबकि महिला आत्महत्या लेती हैं। ये ही समाज के जिम्मेदार लोग फिर से जब व्यक्ति दूसरी शादी करता है तब भी शादी में शामिल होते हैं। आप किसी भी समाज के जो जिम्मेदार हैं उनकी जिंदगी को भी नजदीक से देख लेना तो पता चल जाएगा कि समाज की बागडोर किन लोगों के हाथों में है और वे क्या चुपचाप तमाशा देखते रहते हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 14 वर्ष के वनवास काल के बीच जब जाबालि ऋषि की तपोभूमि मिलने आए तब भगवान गुप्त प्रवास पर नर्मदा तट पर आए। उस समय यह पर्वतों से घिरा था। रास्ते में भगवान शंकर भी उनसे मिलने आतुर थे, लेकिन भगवान और भक्त के बीच वे नहीं आ रहे थे। भगवान राम के पैरों को कंकर न चुभें इसीलिए शंकरजी ने छोटे-छोटे कंकरों को गोलाकार कर दिया। इसलिए कंकर-कंकर में शंकर बोला जाता है।

त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी

रामचरितमानस में व्यावहारिक जीवन में उन्नति के लिए कई चौपाइयां लिखी गई हैं। इसके अलावा भगवान शिव की स्तुति के लिए भी कई चौपाइयों का वर्णन हुआ है। ऐसे में सावन में आप भी इन चौपाइयों के द्वारा शिव की स्तुति कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

वंदे बोधमयं नित्यं गुरु, शंकर रूपिणम।
यमाश्रितो हि वक्रोपि, चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।1।

यह दोहा रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित है। इसमें भगवान शिव की गुरु स्वरूप में प्रणाम की महिमा बताई गई है। इस दोहे का अर्थ है- ज्ञानमय, नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। जिनके माथे पर विराजमान टेढ़ी चंद्रमा भी सभी जगह वंदित होते हैं।

भगवान शिव राम के इष्ट एवं राम शिव के इष्ट हैं। ऐसा संयोग इतिहास में नहीं मिलता कि उपास्य और उपासक में परस्पर इष्ट भाव हो इसी स्थिति को संतजन परस्पर देवोभव का नाम देते हैं। शिव का प्रिय मंत्र नमः शिवाय एवं श्रीराम जय राम, जय-जय राम मंत्र का उच्चारण कर शिव को जल चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं।

भगवान राम ने स्वयं कहा है- शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर मोहि सपनेहु नहि पावा। अर्थात् जो शिव का द्रोह कर के मुझे प्राप्त करना चाहता है वह सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए शिव आराधना के साथ श्रीरामचरितमानस का पाठ बहुत महत्वपूर्ण होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 14 वर्ष के वनवास काल के बीच जब जाबालि ऋषि की तपोभूमि मिलने आए तब भगवान गुप्त प्रवास पर नर्मदा तट पर आए। उस समय यह पर्वतों से घिरा था। रास्ते में भगवान शंकर भी उनसे मिलने आतुर थे, लेकिन भगवान और भक्त के बीच वे नहीं आ रहे थे। भगवान राम के पैरों को कंकर न चुभें इसीलिए शंकरजी ने छोटे-छोटे कंकरों को गोलाकार कर दिया। इसलिए कंकर-कंकर में शंकर बोला जाता है। जब प्रभु श्रीराम रेवा तट पर पहुंचे तो गुफा से नर्मदा जल बह रहा था। श्रीराम यहीं रुके और बालू एकत्र कर एक माह तक उस बालू का नर्मदा जल से अभिषेक करने लगे। आखिरी दिन शंकरजी वहां स्वयं विराजित हो गए और भगवान राम-शंकर का मिलन हुआ। शिवप्रिय मैकल सैल सुता सी, सकल सिद्धि सुख संपति राशि..., रामचरितमानस की ये पंक्तियां श्रीराम और शिव के चरण पड़ने की साक्षी है।

रामचरितमानस के पाठ से भोलेनाथ शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। पाठ के पूर्व शिवजी की उपासना अवश्य करें। इससे मानस का पाठ विशेष लाभकारी होगा।

महामंत्र जोई जपत महेसू,
कासी मुकुति हेतु उपदेसू।

जब भी आप मंत्र जाप करना या सिद्ध करना चाहते हों उसके पहले यह दोहा पढ़ना चाहिए। शिवजी की कृपा से तुरंत ही मंत्र सिद्ध भी होता है और प्रभावशाली भी।

संभु सहज समरथ भगवाना,
एही बिबाह सब विधि कल्याणा।

जब संतान के दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही हो तब इस दोहे का प्रभाव अचूक होता है। नित्य प्रातः शिवजी के समक्ष इस दोहे का 108 बार जाप करें, फिर अपने संतान के सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें।

जो तप करे कुमारी तुम्हारी,
भावी मेटी सकही त्रिपुरारी।

अगर जीवन में ग्रहों या प्रारब्ध के कारण कुछ भी न हो पा रहा हो तो यह दोहा अत्यंत फलदायी होता है। इस दोहे को चारों वेला कम से कम 108 बार पढ़ने से भाग्य का चक्र भी बदल सकता है। परंतु कुछ ऐसी कामना न करें जो उचित न हो।

तव सिव तीसर नयन उघारा,
चितवत कामु भयऊ जरि छारा।

अगर मन भटकता हो और अत्यंत चंचल हो तो यह दोहा लाभकारी होता है। जो लोग काम चिंतन और काम भाव से परेशान हों उनके लिए यह दोहा अत्यंत प्रभावशाली है।

पाणिग्रहण जब कीन्ह महेसा,
हिय हरसे तब सकल सुरेसा।
वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहीं,
जय जय जय संकर सुर करहीं।।

अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दोहे का जाप अत्यंत शुभ होता है। प्रातः काल शिव और पार्वती के समक्ष इस दोहे का जाप करने से शीघ्र और सुखद विवाह होता है।

बिस्वनाथ मम नाथ पुरारी,
त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।

अगर आर्थिक समस्याएं ज्यादा हों या रोजगार की समस्या हो तो इस दोहे का जाप करना चाहिए। प्रातः और रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष कम से कम 108 बार इस दोहे का जाप करना चाहिए।

● **ओम**

एक पाती वृक्ष की

आज के बूफे के दौर से कुछ वर्षों पीछे जाकर यदि सोच सकें तो सहभोज की पंगत याद कर लीजिए...।

जी हां... पंगत की याद आते ही आपको याद आ जाएंगे पत्तल- दोने...। बस...! मैं वही खाखरे का वृक्ष हूं, जो पत्तल-दोने के लिए पत्ते देता हूं...। मैं छोटे-बड़े दोनों ही रूप में मिल जाता हूं...। तेज गर्मी, पथरीला इलाका जो भी हो, मुझे विचलित नहीं करते...। पता है...? गाय और अन्य जानवर भी मेरे पत्ते नहीं खाते... तभी तो मैं हरा-भरा ही बना रहता हूं...।

गावों के लिए तो आज भी मेरी उपयोगिता है... लेकिन शहरी इलाके तो मुझे भूलते ही जा रहे हैं... यही मेरी पीड़ा है...।

तो जब महानगर उन्नति-प्रगति की बात करते हैं तो मैं यही चाहूंगा कि भोजन के लिए डिस्पोजल की जगह पुनः मेरे पत्तों के पत्तल-दोने चलन में आ जाएं... ताकि पर्यावरण व पृथ्वी, दोनों की रक्षा हो सके...।

हर वृक्ष की व्यथा होती है कि मुझे मत उखाड़ो... मुझे मत नोचो... मुझे मत तोड़ो...

मगर मैं कहता हूं... आओ... मुझे तोड़ लो... मेरे पत्ते ले जाओ... परमार्थ का मेरा यही भाव है...।

– **ज्योति जैन**

ओस की बूंदें

उषा और निशा में प्रगाढ़ स्नेह था। पल भर के लिए भी दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं रहती थी। बिछड़ने का नाम सुनते ही उनके आंसू छलकने लगते थे। दुनिया वालों को उनकी यह प्रीति फूटी आंख नहीं सुहाती थी। उनको साथ देखकर लोग तरह तरह की बातें करते थे। उषा थी एकदम उजली, दूध जैसा धवल रंग। सौंदर्य मानों उसके अंग-अंग से टपक पड़ता था। परंतु निशा थी इसके एकदम विपरीत। काली-कलूटी एवं डरावनी सूरत थी उसकी। कोई उसे देखना तक पसंद नहीं करता था। वहीं उषा की एक झलक तक पाने के लिए लोग तरसते थे। फिर भी वे दोनों साथ ही रहती थी।

दुनिया वालों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान, इस बेमेल जोड़ी को अलग कीजिए। हम इन्हें एकसाथ नहीं देखना चाहते हैं। निशा को जब यह मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपनी सखी उषा के लिए दुखी थी। उषा के साथ वह ऐसे ही लगती थी जैसे कलंक का टीका। उसने सोचा काश मैं भी सुंदर होती। मुझे उषा से बिछुड़ना नहीं पड़ता। सदा उसके साथ ही रहती। परंतु तभी उसके मन से आवाज आई। क्या हुआ तुम उजली नहीं हो तो। अपने काले रंग को स्वीकार करो। रंग से ऊपर उठकर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दो।

निशा बेहद उदास थी और अकेली ही बैठी थी। आंखों से टप-टप आंसू गिरकर उसका आंचल गीला कर रहे थे। उषा से बिना मिले ही वह भाग आई थी। तभी उसे पदचापों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उषा उसकी ओर आ रही थी। वह वहां से भाग खड़ी हुई ताकि उषा उसे नहीं देख पाए। उषा भी उसके पीछे-पीछे दौड़ रही थी। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बिखरे हुए कांटों से उसके पैर लहूलुहान हो गए। फिर भी वह दौड़ रही थी। निशा उससे थोड़ी ही दूर आगे थी। उसने दौड़कर निशा का आंचल पकड़ लिया। आंचल गीला था। उसमें से आंसुओं की बूंदें गिर रही थी। उसने आंचल कस कर पकड़ लिया लेकिन निशा तब तक गायब हो चुकी थी। रह गया था तो उसका आंचल और आंसुओं की कुछ बूंदें। उषा अकेली रह गई थी। उसने आंचल ओढ़ लिया और आंसुओं की बूंदों से अपना सुंदर चेहरा धो दिया। तभी सूरज निकल आया। उषा का रंग रूप और भी निखर गया। दिनभर उसका रंग रूप चमकता रहा। फिर निशा आई और उसकी कालिमा सर्वत्र बिखर गई। चांद भी उसका साथ निभाने को निकल आया। सभी नक्षत्रों सहित वह आकाश में चमकता रहा। लोग आश्चर्य चकित थे काली कलूटी निशा का यह रूप देखकर।

– **अर्चना त्यागी**

नारी

नारी का सम्मान ही,
पौरुषता की आन,
नारी की अवहेलना,
नारी का अपमान।
मां-बेटी-पत्नी-बहन,
नारी रूप हजार,
नारी से रिश्ते सजे,
नारी से परिवार।
नारी बीज उगात है,
नारी धरती रूप,
नारी जग सृजित करे,
धर-धर रूप अनूप।
नारी जीवन से भरी,
नारी वृक्ष समान,
जीवन का पालन करे,
नारी है भगवान।
नारी में जो निहित है,
नारी शुद्ध विवेक,
नारी मन निर्मल करे,
हर लेती अविवेक।
पिया संग अनुगामिनी,
ले हाथों में हाथ,
सात जनम की कसम,
ले सदा निभाती साथ।
हर युग में नारी बनी,
बलिदानों की आन,
खुद को अर्पित कर दिया,
कर सबका उत्थान।
नारी परिवर्तन करे,
करती पशुता दूर,
जीवन को सुरभित करे,
प्रेम करे भरपूर।
प्रेम लुटा तन-मन दिया,
करती है बलिदान,
ममता की वर्षा करे,
नारी घर का मान।
मीरा, सची, सुलोचना,
राधा, सीता नाम,
दुर्गा, काली, द्रौपदी,
अनसुइया सुख धाम।
मर्यादा गहना बने,
सजती नारी देह,
संस्कार को पहनकर,
स्वर्णिम बनता गेह।
पिया संग है कामनी,
मातुल सुत के साथ,
सास-ससुर को सेवती,
रुके कभी न हाथ।

– **सुशील कुमार शर्मा**

युवाओं के आगे सब फेल

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-1 से जीत दर्ज कर भारत अब आईसीसी की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। भारत दौरे पर इंग्लैंड ने पहले ही मैच में टीम इंडिया को 227 रनों के बड़े अंतर से हराया था। इंग्लिश टीम के कप्तान जो रूट का दोहरा शतक देखने के बाद लगने लगा था कि टीम इंडिया के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की राह मुश्किल होगी। इंग्लैंड की शानदार शुरुआत ने भारत को तगड़ा झटका दिया था। लेकिन, टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट में जीत के साथ वापसी करते हुए सीरीज बराबर कर ली। लड़खड़ाने के बाद फिर से उठ खड़ी हुई टीम ने अहमदाबाद में खेले गए दोनों टेस्ट मैच में अपने स्पिन आक्रमण के दम पर 2 और 3 दिन में आसानी से जीत हासिल कर ली। इंग्लिश बल्लेबाजों का प्रदर्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने स्पिन गेंदबाजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो।

यह टेस्ट सीरीज भारत के लिए कई मायनों में खास रही है। अव्वल तो तमाम चुनौतियों के बावजूद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाना ही रहा। दरअसल, वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से आईसीसी ने डब्ल्यूटीसी के नियमों में बदलाव किए थे। आईसीसी ने प्रतिशत प्रणाली (परसेंटाइल) से टीमों के चयन का नियम बनाया था। जिसकी वजह से टीम इंडिया के सामने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड को हराने की चुनौती खड़ी हो गई थी। हालांकि, टीम इंडिया ने दोनों ही टीमों के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर यह बाधा पार कर ली। लेकिन, भारत के लिए यह राह आसान नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट कोहली की गैर-मौजूदगी में कार्यकारी कप्तान अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में चोटिल खिलाड़ियों की समस्या से जूझ रही भारत की टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया था। इसके बाद भी डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया को इंग्लैंड पर जीत दर्ज करनी ही थी। खैर, नतीजे सबके सामने हैं और अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा।

टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट जीत में एक खास बात ये भी रही कि टीम के युवा खिलाड़ियों ने जैसा शानदार प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। वह इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में भी जारी रहा। बड़ी बात ये रही कि इस टेस्ट सीरीज की जीत के हीरो भारतीय टीम के दिग्गज नहीं रहे। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सका। विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद के हिसाब से कमजोर प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से खुद को टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित किया। एक शतक और एक अर्धशतक के सहारे रोहित शर्मा ने 4 मैचों में 345 रन ठोके और उनका बल्लेबाजी औसत 57.50 रहा। मुश्किल मौकों पर अधिकतर रोहित का प्रदर्शन अच्छा ही रहा है। युवा खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से वाहवाही लूटी। ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल ने इस सीरीज में कमाल कर दिया।

सीरीज के दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की 329 रनों की पारी के बाद इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 134 पर ढेर हो गई थी। इसके बाद से ही पिच पर सवाल उठाए जाने लगे थे। लेकिन, भारत की ओर से दूसरी पारी में रविचंद्रन अश्विन के शतक ने सभी आलोचकों को एक करारा जवाब दिया था। एक ऐसी पिच जिस पर बल्लेबाज ठीक ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाए, उस पिच पर अश्विन का शतक इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी सीख के तौर पर रहा। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज माइकल वॉन ने चेपॉक की पिच को 'बीच' की तरह बताया। उस 'बीच' पर अश्विन का शतक बेहतरीन 'सर्फिंग' की तरह नजर आया। धैर्य और सावधानी के साथ खेली गई अश्विन की पारी ने आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया था।

सीरीज के तीसरे और चौथे टेस्ट में भारत को क्रमशः 2 और 3 दिन में ही जीत हासिल हो गई। दूसरे टेस्ट से ही जारी हो चुकी पिच की आलोचना को इसके बाद और हवा मिल गई। इंग्लैंड के कई पूर्व खिलाड़ियों एंड्रयू स्ट्रॉस, एलिस्टर कुक और माइकल वॉन ने पिच को लेकर असंतोष जताया था। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 'पिंक बॉल' से हुआ था। इस मैच के दौरान दोनों ही टीमों के बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके थे। बावजूद इसके सारा दोष 'पिच' पर ही लगा दिया गया। चौथे टेस्ट में भी कमोबेश यही हाल रहा और एक बार फिर से 'पिच' पर ही सारा दोषारोपण कर दिया गया। हालांकि, मेहमान टीम के कप्तान जो रूट और उनके किसी खिलाड़ी ने पिच पर सवाल नहीं उठाए। फिर भी इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ियों ने सारा गुस्सा पिच पर निकाला। पिच पर हुए इस विवाद पर रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट के दौरान कहा था कि पिच में कोई 'राक्षस' नहीं थे। दरअसल, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने गलतियां की और उसका खामियाजा पिच को भुगतना पड़ा। दूसरे टेस्ट के बाद से ही इंग्लिश बल्लेबाज भारतीय स्पिन गेंदबाजी के सामने पस्त पड़ गए थे। दरअसल, इंग्लैंड की टीम भारत के स्पिनरों के सामने पस्त रही।

● आशीष नेमा

पंत का अंदाज हो रहा है सुंदर

टीम इंडिया की मध्यक्रम बल्लेबाजी में मजबूती आई है। ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों के ही खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया है। विकेटकीपिंग को लेकर आलोचनाओं का शिकार रहे ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 13 शिकार किए हैं। 4 मैचों में विकेट के पीछे से पंत ने 8 कैच लपके और 5 स्टंपिंग्स कीं। साथ ही पंत ने एक शतक और दो अर्धशतक जड़ते हुए 54 की औसत से 270 रन भी बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने सीरीज में खुद को साबित करने के कम मौके मिलने के बावजूद 90 से ज्यादा के औसत से 181 रन बनाए। ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खेल रहे सुंदर को 7वें और 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दो अर्धशतक लगाते हुए देखना सुकून देता है। इसमें उनकी चौथे टेस्ट की दूसरी पारी भी शामिल है, जिसमें वह शतक बनाने से चूक गए थे और 96 रन बनाकर नाबाद लौटे थे।

मेरा वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया थाः विद्या बालन

विद्या बालन को उनके वजन के चलते काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है। एक इंटरव्यू में विद्या ने अपना दर्द बयां किया और बताया कि कैसे उनका वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। 42 साल की विद्या ने कहा, मैंने जो कुछ भी किया उससे गुजरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। यह बहुत ही सार्वजानिक और उस वक्त अपमानजनक था। मैं गैर-फिल्मी परिवार से आती हूं। वहां कोई मुझे बताने वाला नहीं था कि कोई भी चरण अंतिम नहीं होता। मेरा वजन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था।

लंबे समय तक अपने शरीर से नफरत थी

विद्या ने आगे कहा, मैं हमेशा से फैट गर्ल थी। मैं यह नहीं कहूंगी कि कभी मेरे वजन में उतार-चढ़ाव नहीं हुआ और मैं इसे लेकर बिल्कुल परेशान नहीं हुई। लेकिन मैंने लंबा सफर तय किया है। मेरी जिंदगी में हार्मोनल इश्यूज रहे हैं। लंबे समय तक मुझे अपने शरीर से नफरत थी। मुझे लगता था कि इसने मुझे धोखा दिया है। जिन दिनों में मुझ पर सबसे अच्छा दिखने का दबाव होता था, तब मैं फूल जाती थी और मुझे गुस्सा और निराशा होती थी। जब विद्या से पूछा गया कि उन्होंने बॉडी शैमिंग के मुद्दे के साथ कैसे डील किया तो उनका जवाब था, मैंने खुद को प्यार करना और स्वीकारना शुरू कर दिया। लोग मुझे और स्वीकार करने लगे। उन्होंने मुझ पर प्यार और तारीफ लुटाना शुरू कर दिया। समय के साथ मैंने यह मंजूर कर लिया कि मेरा शरीर ही एकमात्र चीज है, जिसने मुझे जीवित रखा है। क्योंकि जिस दिन शरीर ने काम करना बंद कर दिया, उस दिन मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। यह मायने नहीं रखता कि मैं किस दौर से गुजरी हूं, लेकिन मैं जीवित इसी शरीर की वजह से हूं।

मैंने क्वीन सिर्फ पैसों के लिए साइन की थी, लेकिन इसने मेरी जिंदगी बदल दीः कंगना रनोट

कंगना रनोट स्टारर फिल्म क्वीन की रिलीज को 7 साल पूरे हो गए हैं। यह फिल्म 7 मार्च 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म की एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस ने इमोशनल होते हुए उस समय की परिस्थितियों के बारे में बताया है। उन्होंने लिखा, लगभग एक दशक लंबे कैरियर के बाद मुझे कहा गया कि बॉलीवुड की लीडिंग लेडी होने के लिए मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूं। घुंघराले बाल और दबी हुई आवाज ने इसे बदतर बना दिया था। मैंने क्वीन यह सोचकर साइन की थी कि यह फिल्म कभी रिलीज नहीं होगी। मैंने इसे पैसों के लिए साइन किया था, ताकि मैं न्यूयॉर्क के फिल्म स्कूल में जाकर ट्रेनिंग ले सकूं।

कंगना लिखती हैं, क्वीन मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं है। यह उन सब चीजों का विस्फोट था, जो मैं डिजर्व करती थी और जिन्हें 10 साल तक मुझसे दूर रखा गया था। सबकुछ एक साथ मिल गया। यह ओवरव्हेल्मिंग थी। मैं हकीकत में यह मानती हूं कि जो हमारा है, उसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। आपको अपना हक मिलकर ही रहेगा।

संघर्ष की कहानीः कभी घर चलाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी करते थे वॉचमैन की नौकरी

19 मई, 1974 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे-से कस्बे बुढ़ाना में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की शक्ल-सूरत किसी भी आम भारतीय जैसी है, लेकिन अदाकारी का हुनर लाजवाब है। एक जमाने में वॉचमैन रह चुके नवाज आज भी वक्त निकालकर अपने गांव जाते हैं और खेती-बाड़ी भी करते हैं।

नवाज ने कैरियर की शुरुआत 1999 में आई फिल्म सरफरोश से की। हालांकि इसमें उनका छोटा सा रोल था। साल 2012 तक नवाज ने कई छोटी-बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। फिर अनुराग कश्यप उन्हें फैजल बनाकर गैंग्स

ऑफ वासेपुर में लाए और फैजल के रोल ने उन्हें घर-घर में पॉपुलर बना दिया। नवाज कहते हैं, बड़ौदा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी थी, उसमें डेढ़ साल काम किया। वह नौकरी खतरनाक थी। तमाम तरह के केमिकल की टेस्टिंग करनी पड़ती थी। फिर जॉब छोड़ दी, दिल्ली चला आया और नई नौकरी तलाश करने लगा। वॉचमैन की नौकरी भी की।

महंगाई डायन खाए जात है

लोकतंत्र कक्का हमको एक दिन सैर करते हुए मिल गए। हमने उनको परणाम कर पूछा। कक्का कइसे हो? वैसे कक्का शांत, सहज आदमी हैं, अक्सर हमारा उनका मेल-मिलाप और डिबेट होती रहती है।

ठीक वइसे ही, जइसे संसद में बजट पर। जिसमें बारी-बारी से सब जट लेते हैं और फिर गजट में परकाशित कर देते हैं। लेकिन इस समय कक्का उखड़े-उखड़े दिख रहे थे। हमारी उनसे बहुत पटती थी इसलिए अपुन बेहिचक वार्ताएं करते रहते थे। अपुन को कोई टेंशन नहीं था। काहे की सरकारी मास्टर को अब पेंशन नहीं थी।

कक्का गुस्साए के बोले- तुमको काहे को बताएं, हम कइसे हैं। अब जइसे हैं तो वइसे हैं। यहां मंहगाई से चमड़ी उधड़ रही है और तुम पूछ रहे कइसे हो?

हम बोले मंहगाई? इ तो कब का भाग गई

और ई चमड़ी- यहां तो दमड़ी जा रही

हां, और नहीं तो का, कहे लुगाई बोले का? मंहगाई ने ऐसी हालत खराब की है कि- छोकरों! को लुगाई भी न मिले। हम तो आज की दलबंदी की घेराबंदी में पिस रहे, और संसद, विधानसभा में नेता शायरी पेल रहे।

हम थोड़ा झेंपते हुए बोले, कक्का प्लीज गुस्साओ न! अंग्रेजी वाला सॉरी...

कक्का फिर भनक गए। उनको शायद कम सुनाई दिया था इसलिए वे तर्रा कर बोले, का सोहारी?

यहां तो डालता, रिफाइंड, गैस के दाम सब आसमां को छू रहे और तुम सोहारी-सोहारी चिल्ला रहे हो। जेब में आना नहीं, तो कान छेदाना नहीं।

जब सोहारी नहीं तो तरकारी नहीं। हम बोले कक्का माफ करो। उन्होंने कहा साफ-साफ कहो। हमने कहा हां, कक्का जे! बात है। ई मंहगाई डायन खाए जात है। सखी सइयां तो फूटी कौड़ी नहीं कमात हैं।

कक्का बोले तुम फिल्मी हो। सरकार जुल्मी है।

हमने कहा, देखो! कक्का अइसे न! कहो। आंकड़ों में ग्रोथ है। जी? डीपी जनता की ब्रीथ है। जब जी की डीपी ब्रीथ है, तो सरकार फुल टू क्लीन है। अइसे में जुल्मी का कउनो नहीं, सीन है।

लोकतंत्र कक्का अइसे भड़के कि इक सांस में हमको सुनाए के रख दिए-

पेट्रोल है सौ के पार, गैस चार सौ से-आठ सौ की कतार। सब्सिडी की वैलिडिटी नहीं। इलेक्ट्रीसिटी में भई तकरार। चायपत्ती के दुगुने दाम-किराना लेने में है सबका काम तमाम। किसान दाना बेचे-औने-पौने दाम। हुक्काम छलकाते हैं जाम पर जाम। रिश्वतखोरी का टूटा पैमाना। सरकारी चक्कर में घनचक्कर का जमाना। जनता का यह कैसा इम्तिहान जहां मंहगाई की मार पर मार, भ्रष्टाचार का बसा संसार।

नेताओं की बिस्लेरी बॉटल-जनता नलकूपों में हलाकान। करदाताओं को बना भिखमंगा-नेता करते रहते जनमत को नंगा।

अब तुम कहते हो मंहगाई नहीं?

कक्का का जे! टॉर्चर हम झेल पाने की हालत में नहीं थे। थोड़ा सकपकाए और घबराए। फिर हम कक्का से बोले तुम्हारी बातें शत-प्रतिशत सही हैं। लेकिन यदि मंहगाई है तो आंदोलन क्यों नहीं? वे बोले ज्यादा सयाने न बनों। तुमने नौकरी न पाई- इसलिए तुम्हारी अब तक हुई न सगाई। अब कक्का हमारी बेइज्जती पर उतारू थे। हम बोले कक्का पर्सनल नहीं, वे बोले जब 'आंदोलनजीवी' इंटरनेशनल। तो हम पर्सनल काहे नहीं?

ई 'आंदोलनजीवी' कौन बला है?

इसी ने तो हर आंदोलन को छला है इसलिए किसी का न हुआ भला है। परधानमंत्री को सुना? हमने कहा- हां।

लोकतंत्र कक्का बोले तो 'आत्मनिर्भर' बनो।

हम बोले-जनता महंगाई में आत्मनिर्भर ही तो है, और कइसे बनते हैं?

कक्का ने ठहाके मारते हुए कहा- मारा ही पैंतरा हम पर चलाए दिए। आखिरकार मंहगाई का प्रकोप तुम भी मान लिए।

अब तुम ही बताओ, तुमने बेरोजगारी की कोई बात करी? नेताओं के पिछलग्गू बने और उनकी जयकार करी। भाषणबाजी में तुमने उफान भरी। और अपनी किस्मत में दुधारी तलवार धरी। फॉरम पर फॉरम भरते गए। उस पर भी टैक्स पर टैक्स देते रहे। जितने की भर्ती नहीं, उतनी सरकार की कमाई हुई। जनता की जेब ढीली और तुम बेरोजगारों की शक्ल में तन्हाई हुई।

बोलो मंहगाई हुई कि न?

लोकतंत्र कक्का ने हमारी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। हमको भी उतने ही वोल्ट का करंट लगा, जितने में किसी का वारंट कटा। धड़कन सौ के पार थी। पेट्रोल की मार थी। जेब में मंहगाई की हाहाकार थी। और मुंह में सरकार की जय-जयकार थी।

हम बोले- हम विद्रोही बनेंगे। आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारे ये शब्द सुन कक्का ताव पर आकर बोल उठे- क्या देशद्रोही बनोगे? मंहगाई पर मुंह खोलोगे? सत्ता से कुछ भी बोलोगे? माना कि मंहगाई की मार है, लेकिन अपनी ही सरकार है। फिर बगावत की क्या दरकार है? मंहगाई जरूरी है, जनता इसके बिन अधूरी है। चुनावी बिसात में लिखी गई जनता की किस्मत कोरी है। गोदान उपन्यास जैसे ही- धनिया और होरी हैं।

हर ओर सरकारी खर्चे के चर्चे हैं। जनता के हाथों में केवल चुनावी पर्चे हैं। इसलिए मंहगाई पर न बात करो। सियासी पैंतरों पर सिर्फ टाईम पास करो। ये वक्त भी कट जाएगा, सत्ता पर जो भी आएगा- जनता के खाते में तो वही शून्य आएगा। हमारे पास समय कम था, लोकतंत्र कक्का की बातों में वाकई दम था। महंगाई से जनता का निकलता दम है, सरकारी आंकड़ों में अब भी वही चम-चम है। आखिर में हम कक्का को परणाम कर चलते बनें। लेकिन टीस यही उफनती रह गई कि मंहगाई पर लोकतंत्र कक्का की बात कोई क्यों न सुनें।

● **कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

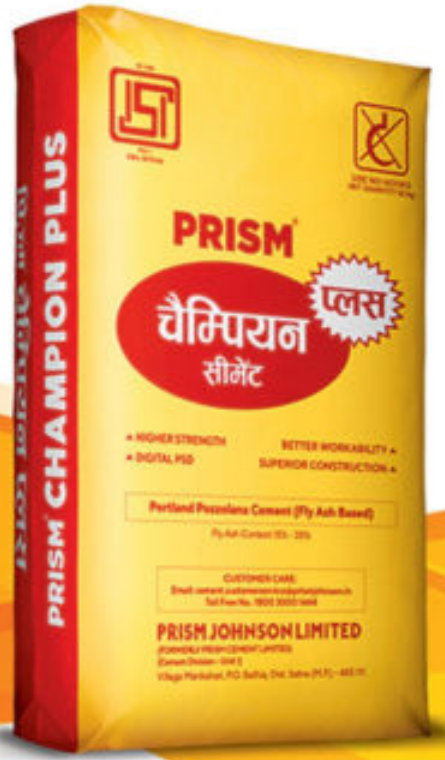

Toll free: 1800-3000-1444
Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

दूर की सोच®

For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
Science House Medicals Pvt.Ltd.
17/1, Sector-1, Shanti Niketan, Near Chetak Bridge
Bhopal (M.P.) INDIA-462023
GST. No. : 23AAPCS9224G1Z5
Email : shbpl@rediffmail.com
PH. : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687
Celebrating
25
YEARS EXPERIENCE